

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol.VIII, Fourth Session, 2015/1936 (Saka)
No.17, Wednesday, March 18, 2015/Phalguna 27, 1936 (Saka)**

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 301 to 304	13-78
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 305 to 320	79-201
Unstarred Question Nos. 3451 to 3680	202-821

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	822-840
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	841
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'S BILLS AND RESOLUTIONS	
8 th Report	841
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
Statement	842
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	
1 st Report	842
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION	
3 rd and 4 th Reports	842
STANDING COMMITTEE ON LABOUR	
4 th Report	843
STATEMENT BY MINISTER	
Hon'ble Prime Minister's visit to Seychelles, Mauritius and Sri Lanka	
Shrimati Sushma Swaraj	844-848
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2522, DATED 11 MARCH, 2015 REGARDING MONITORING OF INFRASTRUCTURE PROJECTS	
General (Retd.) Vijay Kumar Singh	849-850

ELECTION TO COMMITTEE

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical
Sciences and Technology

851

MATTERS UNDER RULE 377

877-893

- (i) Need to take effective measures to check pollution caused by tar balls in the coastal region of Gujarat

Shrimati Jayshreeben Patel

878

- (ii) Need to construct a new railway line from Bilaspur in Chhattisgarh to Jabalpur in Madhya Pradesh via Mungeli, Kawardha and Mandla

Shri Lakhan Lal Sahu

879

- (iii) Need to provide funds for expenditure incurred by co-operative credit societies in disbursement of wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme particularly in Rajasthan

Shri Gajendra Singh Shekhawat

880

- (iv) Need to ban the production of tobacco products in the country

Shri Sanjay Kaka Patil

881

- (v) Need to undertake census of OBCs, Notified Tribes and Vimukta Jati and Nomadic Tribes

Shri Nana Patole

882

- (vi) Need to declare Ahmednagar district in Maharashtra as a tourist destination of national importance and also provide necessary tourist facilities in the district

Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi

883

- (vii) Need to improve medical facilities in hospitals in Sant Kabir Nagar district, Uttar Pradesh
Shri Sharad Tripathi 884
- (viii) Need to establish more medical colleges in the country
Shri P.C. Mohan 885
- (ix) Need to provide funds for Special Tiger Protection Force for Sariska Tiger Reserve
Shri Chand Nath 886
- (x) Need to bring a health insurance policy for the benefit of common man in the country
Shri Rakesh Singh 887
- (xi) Need to make provision for setting up of godowns for storage of foodgrains on platforms of railway stations across the country
Shri Ravneet Singh 888
- (xii) Need to review the decision to close down medical colleges run by Employees' State Insurance Corporation in Tamil Nadu
Dr. P. Venugopal 889
- (xiii) Need to sponsor a resolution in United Nations condemning the genocide of Tamils committed in Sri Lanka
Dr. J. Jayavardhan 890
- (xiv) Need to take stern action against persons involved in trafficking of children
Dr. Ratna De (Nag) 891

- (xv) Need to introduce a new Rajdhani Express train between Bhagalpur (Bihar) and New Delhi or provide the stoppage of Howrah-New Delhi Rajdhani Express at Bhagalpur railway station

Shri Shailesh Kumar

892

- (xvi) Need to permit construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and other State roads stalled due to provisions of Forest Conservation, Act 1980 in Idukki Parliamentary Constituency, Kerala

Adv. Joice George

893

**WAREHOUSING CORPORATIONS
(AMENDMENT) BILL, 2015**

894-941

Motion to Consider

894

Shri Ram Vilas Paswan

894-895

Prof. K.V. Thomas

897-900

Shri Ganesh Singh

901-903

Shri S.R. Vijaya Kumar

904-905

Dr. Tapas Mandal

906-907

Shri Balabhadra Majhi

908-909

Shri Thota Narasimham

910-911

Shri Konda Vishweshwar Reddy

912-913

Shrimati P.K. Sreemathi Teacher

914-916

Dr. Varaprasada Rao Velagapalli

917-919

Shrimati Krishna Raj

920-921

Shri K. Parasuraman

922-924

Dr. Ratna De (Nag)

925-926

Shri N.K. Premachandran

927-930

Shri Kaushalendra Kumar	931
Shri Gajendra Singh Shekhawat	932-933
Shri E.T. Mohammed Basheer	934-935
Shri Ramvilas Paswan	936-940
Clauses 2 to 6 and 1	941
Motion to Pass	941
REPEALING AND AMENDING BILL, 2014	942-970
Motion to Consider	942
Shri D.V. Sadananda Gowda	942
Shri Ninong Ering	943-947
Shri P.P. Chaudhary	948-950
Shri B. Senguttuvan	951-952
Shri Pinaki Mishra	953-955
Dr. Ravindra Babu	956-957
Adv. Joice George	958-959
Shri S.P. Muddahanume Gowda	960-961
Shri D.V. Sadananda Gowda	962-968
Clauses 2 to 4 and 1	969-970
Motion to Pass	970

DISCUSSION UNDER RULE 193

971-977

Agrarian situation in the country

Shri P. Karunakaran

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions

978

Member-wise Index to Unstarred Questions

979-983

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions

984

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

985-986

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 18, 2015/Phalguna 27, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Anto Antony, Shri Deepender Singh Hooda, Shri Jyotiraditya Scindia. The matters though important do not warrant interruption of business of the day. Shri Anto Antony raised the matter of rubber prices. I have allowed it two, three times. Still, I know the problem. Jyotiradityaji raised the issue of heavy rains and that also we discussed it yesterday. We are going to discuss agrarian crisis again. So, I disallow these notices of Adjournment Motion. I will allow you afterwards.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल भी यही बात उठी है और इसी बात पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होनी है। खनीत जी की बात सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर की है, लेकिन उस विषय को बाद में उठाया जा सकता है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : जैसे अभी आपने कहा, कृषि क्षेत्र में जो स्थिति है, उस पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराने के बारे में सरकार भी चाह रही है। हमारे भी बहुत से सदस्यों ने इस विषय को उठाया है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में सिचुएशन गंभीर है। इसलिए जब नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होगी, तो इसके साथ उसे भी जोड़ देंगे। दोनों मंत्री बैठेंगे। हम उचित समय पर बिल पारित होने के बाद चर्चा के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : इस तरफ से भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है। पूरे देश में नुकसान हुआ है। अगर हम एक साथ किसानों की चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, इस विषय को प्रॉयोरिटी दी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यही मुद्दा कल भी उठाया गया है। सब लोग चिंतित हैं। मैंने ऐलारु भी किया था।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, बिल से पहले इस विषय पर चर्चा हो जाए तो अच्छा होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह देख लेंगे कि कैसे करना है।

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे (गुलबर्गा) : एजेंडे के मुताबिक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और रिपिलिंग एक्ट दो बिल हैं। अगर इन बिलों से पहले चर्चा शुरू हो जाए तो सब सदस्य पार्टीसिपेट कर सकेंगे। ये बिल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं जबकि हर बिल पास हो रहे हैं। हमने आज तक 5-6 बिल पास करके दिए हैं। इसमें कोई

दिवक्त नहीं है। लेकिन यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल अलग रख दीजिए और इस पर चर्चा शुरू करवा दीजिए ताकि सब सदस्य हिस्सा ले सकें।

माननीय अध्यक्ष : मैं बात कर लूंगी। अगर सब सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एम. वैकैय्या नायडू : बिल पारित होने के बाद इस बारे में चर्चा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : दोनों बिल छोटे-छोटे हैं।

श्री एम. वैकैय्या नायडू : छोटे-छोटे बिल हैं और वे भी सपोर्ट करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : हम चर्चा करवा देंगे, आप चिन्ता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि इस विषय पर सब सदस्य चर्चा चाहते हैं।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : मैडम, मैंने जो कहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपकी बात भी बताई है कि ज़ीरो आवर में बोलने का चांस दूंगी, लेकिन शान्ति से विषय उठाइए।

11.05 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Q.No. 301, Shri Om Prakash Yadav

श्री ओम प्रकाश यादव: अध्यक्ष महोदया, सरकारी परियोजनाएं इस बात के लिए बदनाम हैं कि वे न तो निश्चित समय पर पूरी हो पाती हैं और न ही आवंटित राशि में उन्हें पूरा किया जा पाता है। अधिकतर परियोजनाएं जब पूरी होती हैं, समय और धन तिगुना खर्च हो जाता है। हमारी सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बल दिया है जो स्वागतयोग्य है। लेकिन बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा समय लगने के कारण अपनी सार्थकता खो देती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी परियोजनाओं का पता लगाने के लिए क्या अध्ययन कराया है? यदि हां, तो इसके बारे में सदन को अवगत कराएं?

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में बताया गया है कि 738 ऐसी परियोजनाएं हैं, इनकी मोनिटरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर ओसीएमएस तैयार किया गया है जिनके अंदर सभी की मोनिटरिंग की जाती है। इसमें 315 परियोजनाएं समय के अनुसार चल रही हैं, 224 लागत के हिसाब से चल रही हैं, 76 दोनों समय और लागत के हिसाब से चल रही हैं। इन चीजों को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें हर मंत्रालय जो इन परियोजनाओं को चला रहे हैं उनको बताया गया है उसमें किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाए। इसके साथ साथ हर मंत्रालय को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज इन सब चीजों का जायजा लेती है, एक सेन्ट्रल तौर पर और साथ-साथ कैबिनेट सेक्रेटरीएट के अंदर ईपीएमजी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया है जो इन सब चीजों का जायजा लेता है। जहां तक इन परियोजनाओं का सवाल है, ज्यादातर परियोजनाओं में इसलिए देर होती है क्योंकि इसके अलग-अलग कारण होते हैं और उन कारणों को जवाब मैंने सवाल के अंदर बताने की कोशिश की है।

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदया, एक अध्ययन के मुताबिक ज्यादातर खनन अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं इस प्रकार की देरी से प्रभावित होती हैं जिसका सीधा असर विकास दर पर पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नई सरकार ने ऐसा क्या बदलाव किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी परियोजनाएं समय पर आवंटित धनराशि के अंदर पूरी की जा सकें?

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह: महोदया, सरकार ने हर मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनाने के लिए कहा है जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरह से हर मंत्रालय अपनी परियोजनाओं का निरीक्षण कर सके और उनको सुचारु रूप से आगे चला सके। हम जब इनका जायजा लेते हैं, हर मंत्रालय को बताते हैं कि कहां कमी है ओसीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रावधान है उस योजना के बारे में हर चीज बताई जा सकती है उसके चित्र उसमें भेजे जा सकते हैं, उसका चार्ट भेजा जा सकता है, उनका अध्ययन करने के बाद उन मंत्रालयों के मंत्रियों से हम विचार-विमर्श करते हैं ताकि इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सके।

श्री ओम बिरला: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संपूर्ण योजनाओं में 1,23,000 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की वृद्धि हुई है। परियोजना बनाते समय ही इसका सही मूल्यांकन, समय का मूल्यांकन, लागत का मूल्यांकन हो जाए और तमाम योजनाओं को गुजरात की तर्ज पर एक एकल खिड़की की तर्ज पर इंडस्ट्रीज में लागू किया जाए, इन परियोजनाओं के लिए जितनी भी स्वीकृतियां हैं चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे वन अभयारण्य का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों उन सारे मामलों की एकल खिड़की योजना के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति हो जाएगी तो लागत और समय वृद्धि के कारण जो देश का नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सकता है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार की कार्य-योजना बनाने का विचार रखते हैं?

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और इन सुझावों पर पहले ही काम किया जा चुका है। हर प्रदेश में एक सेंट्रल कमेटी चीफ सैक्रेट्री के नीचे बनाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि वह अपने स्टेट के सेंट्रल प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सकें।

SHRI V. ELUMALAI: Thank you, Madam.

In his answer the Minister himself has accepted the fund constraint as one of the reasons for delay in implementation of projects. I would like to know whether the Government will come forward to allocate sufficient funds for completion of projects in time, at least to meet the cost overrun because in the answer he has given he has stated that 17 projects are pending in Tamil Nadu.

GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH: One of the reasons for cost overrun or time overrun is improper funding at the initial stage. We have taken note of this. All the Ministries concerned have been apprised of this issue. They have been told

to do a realistic assessment whenever a project is made. Efforts are on to complete projects on time.

DR. ANUPAM HAZRA: Thank you. As we all know the universities across the nation are engaged in research work and in research statistics is one of the important elements. I would like to know through from the hon. Minister whether there is any future plan to conduct statistical workshops and conferences across the universities.

GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH: Although the question does not pertain to this issue, nevertheless this is an on-going process. I am sure, we will take this into account.

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार की 780 परियोजनाएं, जो 150 करोड़ रुपये से ऊपर हैं, वे डिले हैं। इन्होंने यह भी माना है कि 315 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जितना समय था, उससे बहुत ज्यादा हो गया। 224 प्रोजेक्ट्स की कास्ट में काफी वृद्धि हो गयी और 76 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जिसमें दोनों चीजें हो गयीं। मंत्री जी अपने उत्तर में बार-बार कह रहे हैं कि हमने अपने डिपार्टमेंट्स की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, कार्रवाई संस्थाएं, जो निर्माण का कार्य करेंगी, उन्हें कहा गया है कि वे मॉनीटर करें। यह व्यवस्था पहले से लागू है कि कोई भी काम किसी भी कार्रवाई संस्था को अवॉर्ड होता है, तो जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू होता है, एग्रीमेंट होता है, उसी वक्त कम्लीशन का टाइम फिक्स होता है। इसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट्स इतने डिले हो रहे हैं, जिसके कारण 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। आप यह भी कह रहे हैं कि हर स्टेट में चीफ सैक्रेट्री को कह दिया गया है। आज चीफ सैक्रेट्री, जो स्टेट एमपीलैड कमेटी की अध्यक्षता करता है, उसकी बैठक कई-कई साल नहीं होती।

मैं कहना चाहता हूं कि गोंडा-गोरखपुर ब्राडगेज एक लाइन है, जो वर्ष 1997 में स्वीकृत हुई थी और आज वर्ष 2015 है। यह 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, जबकि 1100 करोड़ रुपया लग चुका है, यानी 295 करोड़ रुपया अधिक हो गया। क्या इसकी कोई जवाबदेही तय होगी? अगर सरकार का एक डीपीआर तैयार हुआ, जो कास्ट हुआ, उसमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण अगर 200-300 करोड़ रुपये एक प्रोजेक्ट में बढ़ रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है, इसलिए मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, अब तक ब्राडगेज न होने से बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर में आवागमन में कठिनाई हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए जवाबदेही निर्धारित करने की कोई प्रक्रिया अपनायेंगे?

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने थोड़ी देर पहले अपने उत्तर में कहा था कि हर मंत्रालय को इस चीज के बारे में निर्देश दिये गये हैं कि इस जवाबदेही के लिए किसी की नियुक्ति की जाये। अब तक जवाबदेही की नियुक्ति नहीं थी, इसीलिए इन चीजों के बारे में सही आंकलन नहीं होता था।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। धन्यवाद।

(Q. 302)

श्री राघव लखनपाल: अध्यक्ष महोदया, जब यह प्रश्न बनाया गया था, तब तक हमारी सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत नहीं किया था। इस बजट में इन्टरप्रिन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकों लाभकारी योजनाओं, सेतु, मुद्रा और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा हुई है। इसके साथ-साथ यह भी घोषणा हुई है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब 70,000 करोड़ रुपया अधिक खर्च होगा तो निश्चित रूप से चाहे स्किल क्राफ्ट्समैन हों, इंजीनियर हों, वर्कमैन हों या लेबर हों, इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में हर लैवल पर लोग चाहिए होंगे, लेकिन अपनी कला और सब्जैक्ट को जानते हों। क्या हम इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या मंत्रालय ने इस संबंध में तैयारी की है?

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। वर्ष 2014 में सरकार का गठन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने तय किया कि सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से कौशल विकास का कार्यक्रम फैला हुआ है, उसे एकत्रित करने की आवश्यकता है। जब हम सरकार में आए तो इसी क्रम में वर्ष 2014 में डिपार्टमेंट बनाया गया और 9 नवंबर को मंत्रालय का गठन हुआ। अब तक सरकार को बने मुश्किल से 120 ही दिन हुए थे। माननीय सदस्य ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगभग 70,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ और इसी अनुपात में हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे देश की प्रगति में सकल घरेलू उत्पाद आठ से दस प्रतिशत तक हो जाएगा। सभी सांसदों को जानकारी होनी चाहिए कि नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो मैपिंग की है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग कन्सट्रक्शन से लेकर रोड तक अगले पांच वर्षों में लगभग दस करोड़ लोगों की आवश्यकता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार आटोमोटिव और ऑटोमोबाइल सैक्टर में लगभग सवा तीन करोड़ और हैल्थ सैक्टर में सवा करोड़, टैक्सटाइल में लगभग ढाई करोड़ लोगों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से इलैक्ट्रॉनिक सैक्टर में भी आवश्यकता है। इस तरह 33 सैक्टर स्किल काउंसिल्स हैं।

महोदया, यह चुनौती अपने आप में इतनी बड़ी है। हम 'मेक इन इंडिया' 'भारत निर्माण' की बात कहते हैं तो इन सब क्षेत्रों में यह सबसे महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने जिस विषय के बारे में कहा है यह सबसे बड़ी चिंता है। ऐसा नहीं है कि कौशल विकास का काम आज से शुरू हो रहा है। इस देश में कौशल विकास का काम पहले भी हो रहा था, लेकिन आज लगभग 24 मंत्रालयों में यह काम अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी चीजों में नैशनल स्किल्स

क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत उस मानक के तहत जितने लोग प्रशिक्षण के काम में हैं, उनको इससे संबद्ध करना होगा। यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है।

महोदया, जहां तक नैशनल स्किल क्वालिफिकेशन की बात है, शिक्षा देते हैं, बीए, एमए की डिग्री देते हैं लेकिन कौशल नहीं देने के कारण योग्यता नहीं बन पाती है। इसलिए यह तय हुआ है और सदन को जानकारी होनी चाहिए कि नैशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लैवल-वन बनाया गया है, 27 दिसंबर 2014 को कैबिनेट ने नोटिफाई किया है इसमें अशिक्षित आदमी से लेकर कंपनी के चेयरमैन तक के लिए हर प्रशिक्षण, चाहे शैक्षणिक प्रशिक्षण हो या किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है, उसे नैशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से एलाइन करना होगा। यह दुनिया में 100 देश कर रहे हैं। इस तरह से डिग्री दुनिया के इन 100 देशों में लागू होगी जो आप अपने देश में करेंगे। सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि तीन वर्षों के भीतर अगर सभी ट्रेनिंग संस्थाएं एलाइनमेंट एनएसक्यूएफ के तहत नहीं करेंगी तो उनको किसी प्रकार का ग्रांट नहीं मिलेगा। देश में पांच वर्ष बाद सरकारी सेवा में भी प्रवेश प्राप्त करने के लिए कौशल का होना आवश्यक होगा। इसका भी मापदंड तैयार किया गया है। यह विषय नया है, इसे नए सिरे से टेकअप कर रहे हैं इसलिए इसमें कठिनाई है लेकिन यह सदन की जानकारी के लिए है।

श्री राघव लखनपाल: माननीय अध्यक्ष जी, अभी बताया गया कि स्किल काउंसिल बनाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या कोई टार्गेट रखा गया है? प्रति वर्ष डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज़ इतने लोगों को ट्रेड किया जाएगा? क्या सभी प्रदेशों को यह सुविधा मिलेगी? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है। क्या सरकार विचार करेगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्किल काउंसिल्स खोले जाएं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक मंत्रालय के तहत नैशनल स्किल डैवलपमेंट कार्पोरेशन है। सरकार ने नैशनल स्किल डैवलपमेंट कार्पोरेशन के नाम पर एक ऐसी संस्था का गठन किया है, जो सरकारी नियंत्रण में होते हुए भी प्राइवेट तौर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर सकेगी। यह फ्लैक्सिबल है। हम इसे सरकारी नहीं रखना चाहते हैं, फ्लैक्सिबल रखना चाहते हैं। 33 सैक्टर स्किल काउंसिल के बनाए गए हैं, जिसमें ऑटोमोटिव, हेल्थ, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, एन्वयार्नमेंट, स्पोर्ट्स आदि हैं। इन संस्थाओं को अधिकार है। मैं एक साधारण उदाहरण देना चाहता हूँ। हम वैल्डर की बात कहते हैं कि देश में वैल्डरों का अभाव है। वैल्डर में हम सामान्य रूप में समझ नहीं पाते हैं। एक वैल्डर होता है जो गाड़ी असैम्बलिंग लाइन पर जाकर छः स्टिच लगाता है। एक वेल्डर वह है जो गैस-पाइपलाइन का काम करता है, उसका टॉर्च वगैरह अलग होता है, एक वेल्डर वह है, जो गोताखोरी जानता है और समुद्र के भीतर

जाकर वेल्डिंग भी करता है। इसलिए इन सभी चीजों को परिभाषित करने के लिए और माननीय सदस्य का जो सवाल है, उत्तर प्रदेश के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उनके प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार की बड़ी योजना चल रही है। लेकिन माननीय सांसदों की उपस्थिति रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हर सांसद अपने आप को कौशल विकास से जुड़ा हुआ देखे, इसलिए हमारा यह प्रयास है कि अगले तीन महीने के भीतर सभी सांसदों के किसी एक क्षेत्र में कोई ऐसी योजना लेकर आएँ, ताकि आपकी उपस्थिति कौशल विकास के माध्यम से आपके क्षेत्र में दिखे, हमारा ऐसा प्रयास है।

SHRI DUSHYANT SINGH: Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. The hon. Prime Minister has instructed the Ministry of Skill Development to set up 2500 Multi-skill Institutes throughout the country. Various State Governments are ready to have these institutes, even my State of Rajasthan. This Ministry was set up in the year 2014. This Ministry works as nodal Ministry for 24 other Ministries under which the hon. Minister has mentioned about mapping under NSDS and NSDC. Under this he works under the Ministry of Labour which deals with ITIs and the Ministry of Human Resource Development. How is the Ministry of Skill Development planning to finalise schemes to design and roll out, at the earliest, to benefit our youth vis-à-vis Multi-skilled Institutes in various parts of the country to provide unemployed youth and to skill the employed youth and give it an impetus? What are the Budgetary provisions? When we talk about 24 Ministries, every Ministry has their own nodal place from where they work. What are the mappings and what are the structures the Ministry has to show what they have done and how they are going to help the new Multi-skilled Institutes?

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, this is a very important question and I have been struggling with this issue ever since the hon. Prime Minister gave me this assignment. There is an issue because under the allocation of Business Rules, ITIs have to be transferred to my Ministry, but unfortunately due to some coordination problem it has not happened and these 2500 Skill Centres which are going to be established, we are not going to call them as ITIs. Under the Prime

Minister's Mission which is going to be launched shortly, which we are planning, the Skill Development Mission, these Skill institutes which we are talking is going to be 2500. Now, it is not to be given completely in the Government sector because we already have 12000 ITIs in this country, out of which 4000 are in the Government sector and about 8000 are in private sector. The very fact that the ITIs have, not to a very great extent, been able to deliver what we actually expected them to do, and this whole concept of skill development came on a different forum. With these 2500 new Skill Centres or Skill Institutes which they are talking, there was an allocation of about Rs. 40 crore, but possibly the Ministry of Labour has returned it. Now this has been given as my baby and I would try to see this formulation in a PPP mode. Suppose the Tata Motors or the Hyundai Motors wants to establish one particular place on automotive or health care, may be MAX, may be Apollo, if any of these hospitals want to come up with health care, we will try to put it up. I am still trying to find out how to put these 2500. Somehow this year I could not get enough allocation as far as the Ministry is concerned, but I would like to flag this issue that Rs. 6000 crore under various Ministries are being spent and possibly there is an outcome which means that the result of employment through a particular training is one big challenge for us today. I would say that these 2500 Multi-skill institutes about which the hon. Member has mentioned, would possibly take in 500 districts, four such institutes in each and every Member of Parliament's constituency. All this is because we have to make the people of this country realise that 'Make in India' will only happen if we are able to achieve this 300 million people who have to be trained. The NSDA in 2009 had talked about 500 million people but I have not been able to collate that figures how it was 500 million. But even if we are able to train some 200 million people by the end of our term, I think, it would be the biggest achievement in the history of this country.

SHRI R. DHRUVANARAYANA : Madam, the Government has been running various schemes for skill and awareness of farmers but the larger role of

agripreneurship or entrepreneurship in agriculture is not explored to the maximum. Agri business has the potential to contribute to soil management in warehousing, collateral finance, contract farming, cleaning and grading services and also procurement of produces from farmers.

Would the hon. Minister come out with a scheme to make our farmers as entrepreneurs in agriculture in rural areas so that they can undertake these activities?

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: This is a very interesting question because we have created the Agriculture Sector Skill Council.

As the Prime Minister in his discussion had mentioned, every man who is born goes through a life cycle and what is done at every age, right from his birth when he is given a *malish* by the grandmother or the mother is an art. Right from there to the high school, to the time he learns driving his car to getting a licence to work in the factory or when he works in the fields and at every place, there is a skill. The moment you endorse this skill and recognise the skill, you are able to raise productivity.

When we are talking about GDP, the Sector Skill Council of Agriculture, we are not talking about actual agriculture which is looked after by another Ministry. I am talking about the skills. Almost every sector which we are looking at today requires skill. This is a major challenge and it has been about 110 days for me in this Ministry. We have to partner the States as far as skill development of agriculture is concerned. Today, agriculture forms about 14 per cent of the GDP. It is on the lower end. We have to make it more competitive.

On the suggestion of the hon. Member, we are trying to map, under the Agriculture Sector Skill Council, the domain which is not under agriculture but beyond in skill development and rural development. I can tell you that Agriculture Ministry has about Rs. 400 crore for the job. In fact, the amount of Rs. 1500 crore which has been announced under the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana is not with my Ministry. It has been given to the Ministry of Rural

Development. We are trying to see how best we can make them align with the requirement of the hon. Member.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was established in November, 2014 under the leadership of our hon. Prime Minister. This was one of the best decisions which the new Government has ever taken.

Looking at the number of youths and entrepreneurs in the country, I think there is a need to boost the aspirations towards starting their own business and entrepreneurship development. Besides the development of skill and entrepreneurship, I want to know whether the Ministry has any plan or policy to support new entrepreneurs in the field of marketing since the youth of the country is capable of undertaking R&D products or produce the products. This is very much required because many youths start the business but they get stuck up only in the field of marketing.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, on the issue of entrepreneurship, employment will not be created maximum in large industries but small entrepreneurs are the base for this country.

On the issue which the hon. Member is mentioning, we have created a fund of about Rs. 10,000 crores in the previous Budget that has yet to be rolled out. At this point of time, this particular issue of entrepreneurship is not actually handled by me. When questions come down to me, I have to rely on other Ministries but the Ministry of Small Scale and Medium Enterprises is handling aspects like incubation and other things but we are also trying to get some corpus fund because world over, riches have not been created by big industries. Riches have been created by people who have gone as innovators and incubated ideas to create wealth. I can quote a number of such cases. But NSDC has already provided for a platform on which we are trying to develop entrepreneurship in coordination with snapdeal and other platforms. This is one place where India has been actually lagging behind and we do not have start-ups and start-up enterprises. Even a

country like Israel would outsmart India in many ways. A country with a population of seven millions would have around 4000 start-ups and India, in the last 30 to 40 years, has about 2500 start-ups only. This is a new thing which is catching on to the people and this generation is all set to become entrepreneurs and that is the biggest job creator in this whole set up and eco system. That is what we have to achieve which is just a beginning. We have lost 65 years in doing this. This is just a beginning. We have to accept that.

माननीय अध्यक्ष: पूनम महाजन जी, आप पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन: मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ, वैसे मेरा नाम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: मुझे क्षमा करेंगे, मेरे पास लिस्ट में पूनम माडम का नाम है। मैंने गलती से आपका नाम पुकार लिया। यहां पर दो-दो पूनम हैं और दोनों यंग हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पर युवा ज्यादा पूरक प्रश्न पूछें। पूनम माडम जी आप अपना पूरक प्रश्न पूछें।

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: I have written my Division No. It is 126.

HON. SPEAKER: Sorry, please go ahead.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Madam Speaker, thank you. The hon. Minister's detailed reply to the previous supplementary questions, leaves a very little scope for any further supplementary questions.

First of all, I would like to congratulate the hon. Minister on the roadmap that he has chalked out for each and every district. When you talk about tool rooms which are the big training centres as far as giving training or training the youth or students, we still have States which have no tool rooms at all. States as large as Madhya Pradesh and Bihar might just have one tool room.

The hon. Minister has just mentioned in his reply that his Ministry is planning to provide this in each and every Lok Sabha constituency. I congratulate the hon. Minister for the same. But all I would like to know, through you, from the Minister is whether any survey is being conducted in each and every Lok Sabha constituency or each and every district of our country on this issue because there is

a specialised unit everywhere. I have a brass manufacturing unit where the brass components are supplied in Morbi, at Saurashtra in Gujarat. We may have a huge ceramic industry. In Moradabad we might have something else related to brass. So, the entire country has different things in different districts. In order to employ the youth of that particular district, we have to train them according to avenues available to them and according to the industries available to them in their respective districts.

So, I would like to know from the hon. Minister whether any survey is being conducted in this regard as to which district or which Lok Sabha constituency requires what kind of skill development institute. Thank you.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I think the hon. Member has done a lot of work in asking this question.

माननीय अध्यक्ष: वह स्वयं एक अच्छी आंत्रप्रोन्योर हैं।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: This question would not have had she not studied it in detail. I appreciate that she has studied this Question in detail.

In fact, the National Skill Development Corporation has done a district-wise skill mapping and every district of this country, except for the State of Bihar, where I come from. There that job has not been completed which will get completed. In every district of the country, a study on the job requirement and the skill gap has been done. It would be difficult to segregate constituency-wise, but it has already been done. This is how we are going ahead with deciding what kind of vocational training or what kind of skill training we have to offer. It is a huge task. We are talking of a country with 1260 million people and a workforce of about 500 million people. We have just started it.

श्री मानशंकर निनामा: अध्यक्ष महोदया, कौशल विकास से जुड़े हुए विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य कौशल एवम् आजीविका विकास निगम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टीम ने कौशल संदर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय में कॉमर्स कॉलेज बनाने के लिए साइन किया है। राज्य सरकार और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

के बीच इस बारे में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत विभिन्न गतिविधियां होंगी। इस कड़ी में विकास निगम के साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह राज्य के सभी वाणिज्यिक महाविद्यालयों तक संचालित करना है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री मानशंकर निनामा : वाणिज्य से स्नातक करने वाले छात्रों को कम्पनियों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाएगा। अतः केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगार के लिए शिक्षा के लिए तकनीकी तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से संस्थाओं एवं कम्पनियों की आवश्यकता के हिसाब से मासिक, त्रिमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रशिक्षण दे कर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : इसमें प्रश्न नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, मैं समझ गया हूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है?

माननीय अध्यक्ष : आप समझदार हैं, जो प्रश्न समझ गए हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, राजस्थान सरकार स्किल डेवलपमेंट में बेहतरीन काम कर रही है और उसके बारे में माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आपके राज्य का जो स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन है, वह बहुत अच्छा काम कर रहा है और आजीविका मिशन में अगर आप सम्पर्क करेंगे तो राजस्थान सरकार सचमुच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आदि कई प्रांतों में अच्छा काम हो रहा है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ ऐसा होना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल रहा है कि यदि हम पिछले पांच दशकों में शिक्षा के साथ स्किल को जोड़ देते, तो निश्चित रूप से यह काम आसान हो जाता। लेकिन वर्ष 1988 में सबसे पहले एचआरडी में शुरू किया गया और उसके बाद वर्ष 2011 में इसे रिवाइज्ड किया गया और वर्ष 2012 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है यह नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से लिंक-अप हो कर आया है। कई राज्यों में यह शुरू हुआ है और आज स्कूल तथा कालेज से निकलने के बाद जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हरियाणा राज्य ने उसे प्रारम्भ किया है और अभी 21000 सैक्शन पूरे देश में हैं और कई सारे विश्वविद्यालय हैं। अगर आपके यहां कोई विश्वविद्यालय है और वहां के वाइस चांसलर तथा जो आटोनोमस बॉडी है, अगर एनएचटीसी से एलाइन करेगा तो वह अधिकृत है तथा अपनी-अपनी संस्थाओं में आप स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण का काम प्रारम्भ कर सकते हैं और यह सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। आप अगर अपने विश्वविद्यालय को हमारे यहां से संबद्ध कराना चाहते हैं तो आपके यहां के सलेबस में स्किल डेवलपमेंट का काम प्रारम्भ किया जा सकता है, यह सरकार ने निर्णय लिया है।

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर बहुत से युवा सांसद और कुछ वृद्ध सांसद भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस बारे में बहुत से माननीय सांसदों की रुचि और चिंता है। अगर सदन चाहता है तो इस विषय पर चर्चा भी की जा सकती है।

कई माननीय सदस्य : जी हाँ, महोदया।

माननीय अध्यक्ष : मेरा मंत्री जी से भी निवेदन है कि कभी युवा सांसदों के साथ बैठक और चर्चा करके, उनके सुझाव भी लिए जाएं। इस बारे में हम आगे काम कर सकते हैं।

(Q. 303)

ADV. JOICE GEORGE : Ours is a multi-lingual country with 22 official languages in 12 States. In India, only 5 per cent of the people know English. The rest are deprived of the benefits of information communication technology due to their lack of knowledge in English. The Technology Development for Indian Languages Programme is a very important programme. It is having a lot of things to do for the uplift of the lives of the poor people in the agrarian areas. Here, the benefits of information technology can reach the common man only when software tools, human and machine interfaces are available in their own language. The hon. Minister was kind enough to give me an answer. All our languages are having these development activities. Technology tools are there. Our hon. Prime Minister has announced the *Jan Dhan Yojana* also. We are focusing on banking for the poor people, we are focusing on tourism, we are focusing on health aspects where technology has a vital role to play. My specific question is this.

माननीय अध्यक्ष : स्पैसिफिक और तुरन्त प्रश्न पूछना भी एक स्किल है।

ADV. JOICE GEORGE: I want to know whether the Government is having any programme to have some technological tools and other technological advancement schemes in banking and healthcare sectors.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I want to inform this august House that in a population of India of 1.1 billion-plus, we have 97.5 crore mobiles in India! It is a big growth sector. The internet service providers have given the statistics that by the end of last year, we have got 30 crore internet connectivity in India. Therefore, we have surpassed America and we are second to China. This is a matter of great growth. In terms of smart phones, India has got the biggest consumption after America.

In this connection, our Prime Minister took the initiative of Digital India. Digital India is more for the poor, underprivileged. Earlier, a question was asked - What scenario we are unfolding? By the use of these technology, carpenter, barber, electrician, farmer can find new job. It is happening with what we are going to coordinate. But this cannot happen if it is only English. Therefore, technological development of Indian languages became the key programme of our Government. I wish to inform this hon. House with great degree of happiness that we have developed tools in 22 languages for font, for immediate translation of same in English script, for translation, etc. and we consciously distributed those 12 CDs.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): *Mantriji*, what are the languages?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: All the 22 constitutionally recognized languages of India. I want to assure this House. The Prime Minister was very keen, it must go in all the languages. Today, about 1.27 crore of these software, which is on the website, have been downloaded; all are being used; and it is our mission that the entire software technology language is available in local languages. In that direction, we are doing our best.

As far as SMS is concerned, I want to inform that we have a Mobile Sewa whereby we are sending messages in five Indian languages simultaneously translated. I have told the Department of Information Technology to further improve it. All these efforts are going on. I am sure, the same would bring in results.

ADV. JOICE GEORGE: Regarding the international standardization of our language system, I would like to know from the hon. Minister as to what are the steps taken for standardizing our language tools internationally through international standardization bodies.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Obviously, whenever these languages are going to be a software language, there is a proper process of standardization, not only in terms of transliteration. What is 'transliteration'? If something is said in Malayalam, immediately it would come in English script. It has to be translated. I told the Department that it should be explained in a manner that if some good idea is coming from Malayalam, it must be available to the farmers of Bihar and *vice versa*. The whole process is going on because we feel that Internet is one of the finest creations of human mind but Internet to become global must be properly 'local' as well, what we call as 'glocal'. Therefore, we have also got Unicode storage standard for proper maintenance of these languages.

DR.K. KAMARAJ: The C-DAC, Chennai has developed an operating system called 'Bharat Operating System Solution'(BOSS), which was released last in 2013. I want to know from the hon. Minister. Is his Ministry continuously developing the operating system? This is the operating system with many languages, where regional languages can also be used. Is the Ministry further developing the operating system? Why is there low adaptation of this operating system in the Government sector – be it the State or the Central?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Today, sitting in this hon. House, and speaking, wish to compliment our scientists in C-DoT who are doing the good work. I have also asked them to be more communicative. The people of the country can know as to what achievement they have done. As far as various specific schemes are concerned, there is 'Live Open Operating Scheme' in all the 22 languages, and other schemes are also talked about. What is important is that these development and evolution of system is an ongoing process. You cannot stop only with one because the technology is going so fast. Every day new

technology is coming about. In India also, as hon. Rudy was saying during the previous question, new start-up industries in the field of IT are doing such a great job in terms of finding of new solutions, new ideas, finding great access to people. Therefore, all these evolutions will go on; we shall support fully any new inventions and innovations.

माननीय अध्यक्ष : हिन्दी की तो कोई समस्या नहीं है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, हिन्दी में ही समस्या है। हिन्दी का उत्तर बड़ी मुश्किल से मिला है। हमने वहां शिकायत की है और उसमें जब वह उत्तर हाथ में आया तो उसमें टीडीआईएल (अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म) लिखा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ यही आग्रह है तथा मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि हिन्दी के जो फॉन्ट्स होते हैं, दुनिया में अंग्रेजी के फॉन्ट्स नहीं बदलते, हिन्दी के फॉन्ट्स बदलते रहते हैं। हमें इसी सदन से उत्तर मिला कि 1991 में कोई कानून बन गया, उसके बावजूद भी हर पांच साल में हिन्दी के फॉन्ट्स बदल जाते हैं, यह एक उदाहरण है।

मेरा दूसरा आग्रह यह है कि प्रचलन की भाषा, हम अगर गूगल के ट्रांसलेशन को मानेंगे कि यह भारतीय भाषाओं का ट्रांसलेशन है, इसी सदन में बहुत सारे हिन्दी भाषी या स्थानीय भाषा के जो भी सदस्य होंगे, हम देखते हैं कि शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्थानीय भाषा प्रचलन की भाषा में कैसे आयेगा। टीडीआईएल हिन्दी के उत्तर में शार्टफार्म में है। मुझे लगता है कि प्रचलन की भाषा जब तक भारतीय भाषाएं नहीं बनेगी, प्रशासनिक तरीके से उसका हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक हम अपना स्थान नहीं पा सकते।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हम कब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शब्द हैं, शब्दकोष है, लेकिन अगर वह प्रचलन की भाषा में नहीं है, अगर हम उसे सामान्य तौर से उपलब्ध नहीं करा सकते तो मैं समझता हूँ कि हमारा लक्ष्य अधूरा रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर आम तौर पर सांसदों के बीच में या संसद के ट्रांसलेशन में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकें कि यह हिंदी का अनुवाद है, कहीं किसी और का नहीं है, क्योंकि हमारे पास शब्दकोश है, वह आप कब तक उपलब्ध करायेंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, हिन्दी के प्रेमी हैं, मैं उनकी चिंता को समझता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जब मैं अफसरों से बात कर रहा था तो मैंने अपनी यही चिंता उन्हें बताई कि पूरी तकनीकी भाषा में जो विषय रखे जाएं, वे इतने सरल और सहज हों कि आम लोगों के द्वारा समझे जाएं और मैंने विशेष रूप से यह सवाल किया कि

किसानों को जो हम लाखों की संख्या में संदेश भेजते हैं, उनकी भाषा क्या है। मैं आपको आश्चर्य करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो विषय आए हैं, जो विशेष रूप से फरवरी, मार्च में लगभग बीस करोड़ किसानों को भेजे गये, उनकी भाषा बहुत ही सरल है, जैसे 'हवा तेज रहने की संभावना है, कृपया यह ध्यान रखें' तो यह भाषा बिल्कुल समझने लायक है। टीडीआईएल के बारे में आपने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उस चिंता को समझता हूँ। लेकिन कई बार आप समझते होंगे कि शार्ट फार्म को समझने में लोगों को सुविधा होती है। इसलिए उन्होंने टीडीआईएल लिखा होगा, लेकिन मैं निर्देश करूँगा कि आगे से जब भी प्रश्न का उत्तर हो और अगर अंग्रेजी नाम है तो उसका हिन्दी अनुवाद होना चाहिए।

एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि चाहे गूगल हो या बाकी अन्य कोई प्लेटफार्म हो, इसके बारे में विभाग की ओर से हमारा संदेश हमेशा रहा है कि भाषा कोई भी हो, तकनीकी भाषा सरल तरीके से रखी जाए, ताकि आम लोगों को समझ में आए। अगर हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो डिजिटल दूरी गरीबों और अमीरों के बीच है और हम इस दूरी को पाटना चाहते हैं तो वह सरल भाषा के माध्यम से ही होगा। यह मैं बार-बार आग्रह करता हूँ और अगर सदन के सम्मानित सदस्यों का इस दिशा में कोई विशेष सुझाव है तो मैं उस पर पूरी गंभीरता से विचार करूँगा।

(Q. 304)

MOHAMMED FAIZAL: Madam, before I ask the question, I would like to extend my sincere thanks to the hon. Minister on behalf of the entire students of Lakshadweep, especially Lakshadweep Students Association, for enhancing their scholarship which was pending for the last six years. I am thankful to you also, Madam. You had given me an opportunity to raise that issue in the 'Zero Hour' during the previous Session.

I am very happy to see the Answer of the hon. Minister. My specific question to the Minister is this. I would like to know whether the Government of India is planning to start employment and skill-oriented institutions in my constituency, Lakshadweep. If so, what are the modalities of recruiting the trainers?

The reason why I asked this question specifically is that Lakshadweep is going through a very tough situation. During 2008, all the schools, all the Government schools of Lakshadweep were upgraded to plus two. The hon. Minister knows that; I have taken that matter to the Minister also. But from 2008, till date, the teachers are appointed on contract basis, on yearly basis. The inherent problem of this contractual appointment is that every year the students have to face new teachers.

Madam, kindly give me some time because I am the only MP from Lakshadweep. There is no MLA, no Chief Minister. I have to raise the issue and you have given me ample opportunity for that also.

HON. SPEAKER: I am giving you the opportunity.

MOHAMMED FAIZAL: Thank you very much, Madam. In fact, I met the hon. Prime Minister also day before yesterday. I was requesting him for his kind intervention i.e. there is a proposal pending in the Ministry of HRD from 2011 onwards for creating 120 Post-Graduate teachers' posts which will definitely improve the condition of education in Lakshadweep. If you take the graph of education, the quality of education has come down because of unscientific method

of recruitment of contract teachers. Even though my question was not on this and I was elucidating the problems of my constituency. My specific question to the hon. Minister is that whether such skill oriented institutions are being planned to start in my constituency? And, what are the methods of recruitment?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam, it seems today is a day of thanks giving for the Ministry. It is because of the hon. Member's question, specially, part 'c'. I was quite intrigued when the Member posed a question asking specifically about the Indian Centre for Research and Development of Community Education. The UGC has absolutely no information about this so called Centre. I took a morning meeting to know as to what this Centre is all about. The hon. Member of this House has asked a pertinent question with regard to this organization. We, within the Ministry, hunting on an open course, which is on internet, and we found that this particular institution claims to be the coordinating agency of all community colleges in India, which is a false claim.

I would like to thank the hon. Member for asking this part of the question because it enables us now to investigate as to why such a private institution, which is not within the realm of the UGC or the AICTE, is making such a claim thereby raising many questions. So, I thank him for that. I would also acknowledge on the floor of the House that the Member has appealed to me on many issues with regard to the state of education in Lakshadweep and I have extended all the support that I can through the Ministry of HRD so that all solutions can be found. But rationalization of teachers is an issue which cannot be done Centrally. Ever since I have received the responsibility under the leadership of the hon. Prime Minister for HRD in the country, I have personally appealed to every State, written to them, spoken to them, in dialogues with State Education Ministers and even requested the administrators within that Union Territories also for rationalization of teachers because we provide for permanent faculty to be there.

Insofar as skilling is concerned, I think, my senior colleague Mr. Rudy has spoken about his desire and his initiative to set up a skilling component and

initiative in every district in every Lok Sabha Constituency. I am sure that his initiative will take care of a lot of your needs. Apart from that, there is something which we have launched under the UGC which is called the Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra. In the 12th Plan, we planned to set up 100 such Centres. The guidelines for this were notified in December 2014. It has been available on the website of UGC so that any institution which is NAAC Grade A can apply for this along with an NGO and philanthropic foundation and open up a skilling centre. I invite any application that the hon. Member deems fit through the UGC so that people in Lakshadweep can be more empowered.

I would also like to say that the UGC is going to give a grant of Rs. 5 crore for this and allow adjunct faculty, which means, that industry experts can be allowed into these skilling centres to make our young trained and make employable.

MOHAMMED FAIZAL: I would like to thank the hon. Minister for her elaborate answer. My second supplementary is that as far as Lakshadweep is concerned, it is coming directly under the Ministry of HRD. Whatever the methodology for recruitment is adopted in Lakshadweep that is with the concurrence of the concerned Ministry. Again I would like to request you to sanction 120 Post-Graduate teachers' posts which are pending with you. That will be the final solution.

Now, till such time, what will be the methodology for the appointment of contract teachers in this Island? The prime concern is to select a good teacher rather than giving employment to 'X' or 'Y'. The methodology, which is adopted there, is giving advantage to a person who is having more marks in his academic session rather than finding out whether he has the ability to teach the students in a better way.

So, my specific question in this regard is that Madam, I have written a letter to you requesting you to keep all the qualified teachers in the same platform. Let them compete each other and show their calibre and take the best teachers from them, and that is what we want. Is there any move from the Ministry to streamline the contract appointment of teachers in Lakshadweep?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, though the Question pertains to Skill Oriented Courses, I acknowledge the concern expressed by the hon. Member. I would also like to say that 'yes', skilling up and scaling up our teaching faculty is also a concern which is shared by everybody in this House and across the nation.

Madam Speaker, the hon. Prime Minister, on the 25th December, 2014, launched the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching. Apart from that, the NCTE guidelines, which were notified last year, 2014 under the instructions of the MHRD insisted that teachers when they are trained should spend 20 weeks in a classroom teaching so that they can be analysed for their skills and their skills after analysis can be supplemented with any other support that is needed and also we can have better skill teachers. But I would also like to tell the Member that apart from the teachers' skilling programme or training programme that we have initiated, we are also taking care that teachers within the system currently in conjunction with the States are given in-service training also.

श्री हरीश मीना: महोदया, देश में प्रतिवर्ष स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी साक्षरता दर भी बढ़ती जा रही है और इसके साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यही हाल कौशल विकास का है। कितने ही आई.टी.आई. के पढ़े लड़के हैं, कितने ही बीएड डिग्री प्राप्त लड़के हैं, जो लाखों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं और जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसको सार्थक कब बनाया जाएगा, क्योंकि आज जो भी युवक शिक्षा ग्रहण करता है, उसका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। क्या सरकार उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करेगी? धन्यवाद।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय स्पीकर साहिबा, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने का दायित्व है, इसलिए मैं अपने आपको उससे सीमित रखते हुए इतना कहना चाहूँगी कि 11 नवंबर, 2014 जो हमारा नेशनल एजुकेशन डे था, हमने उस वक्त एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और देश को उसे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से समर्पित किया। यह निर्णय तब हमारे मंत्रालय में लिया गया जब प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में इस सरकार के पहले सेशन में आपकी उपस्थिति में कहा था कि क्या भारत में यह संभावना नहीं हो सकती कि जो बच्चा कक्षा 9 में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और मान लीजिए कारपेंटर बन जाता है, तो उसकी स्किल की रिकॉग्निशन हो और अगर वह आगे बढ़कर कोई डिग्री लेना चाहता है, ताकि उसके स्किल का सम्मान बढ़े तो क्या हम यह व्यवस्था नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस चिंता के व्यक्त होने के बाद और उनके दिशा-निर्देश पर हमने “SAMVAY” नाम का एक स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स, एक फ्रेमवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें हमने कहा कि भले ही आप कक्षा 9 में पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन लेवल थ्री पर दोबारा आपकी स्किल को सेक्टर स्किल काउंसिल रिकग्नाइज करेगा, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि होंगे और उस स्किल से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित प्रतिनिधि होंगे, वे आपको रिकॉग्निशन देंगे आपके स्किल का ताकि आप दोबारा एजुकेशन सिस्टम में आकर डिग्री लेना चाहें तो लें। जो चिंता माननीय सदस्य ने व्यक्त की कि आप स्किल्ड तो हो जाते हैं, लेकिन उस स्किल का सम्मान नहीं होता, उस सम्मान हेतु हम सर्टिफिकेशन के माध्यम से यह प्रयास करते हैं। साथ ही साथ स्कूल में भी यही प्रयास है कि आप कक्षा 9 से ही एक वोकेशनल कोर्स भी अलाऊ करते हैं, जिसे हम बोर्ड के एग्जाम में भी रिकॉग्निशन करते हैं ताकि 12वीं कक्षा तक स्किल अगर प्राप्त करना चाहें तो सर्टिफिकेशन को, प्रमाण-पत्र को वह स्टूडेंट साथ में लेकर जॉब मार्केट में उतरे।

माननीय अध्यक्ष : श्री अभिषेक सिंह। प्रश्न के सन्दर्भ में ही पूरक प्रश्न आना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें।

श्री अभिषेक सिंह: महोदया, अभी-अभी आदरणीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, काफी हद तक मेरा सवाल उसी पर आधारित था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है, जहाँ मेन स्ट्रीम और वोकेशनल एजुकेशन सीमलेस हो सके। मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, प्रश्न के सन्दर्भ में ही आपका प्रश्न आना चाहिए।

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, मंत्री महोदया ने सप्लीमेंट्री प्रश्न का जो उत्तर दिया है, मेरा प्रश्न उसी पर आधारित है। एजुकेशन में पूरा पैराडाइम शिफ्ट करना है। जैसा उन्होंने कहा कि शिक्षा मर्यादा देती है, अगर उसे काम की मर्यादा नहीं देते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर, तो वह ओरिएन्टेशन नहीं आता है।

12.00 hrs

हमारे जीवन में हम शिक्षा में यह पाते हैं और कहा जाता है कि “पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब” - कहा जाता है कि पढ़ लो नहीं तो फिर ज़िन्दगी भर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज शिक्षा का जो मूलभूत ढाँचा है, उसमें शुरूआत से ही स्कूली एजुकेशन से काम के प्रति जो सम्मान है, वह मिलना चाहिए। दूसरा, उसका रिकॉग्निशन हो और वर्टिकल मोबिलिटी एनश्योर करने के लिए आपको क्रेडिट सिस्टम और टैस्ट ऑन डिमांड रखना चाहिए कि हमें यह काम आता है, हम यह टैस्ट लेंगे और आपके दो काउंसिल जो दो अलट-अलग विभागों में भी हो रहा है, उसमें कौशल भी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपका जो शिक्षा का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसको इस्तेमाल करना - हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना और जो लोग यह दक्षता लेना चाहते हैं, क्या आप सब कालेजेज़, विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कालेज को अनुमति देंगे कि वे पोलिटैक्निक की तरह शिक्षा दें?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would quickly answer this question, Madam Speaker. हमने यूजीसी के माध्यम से सभी कालेजों और यूनिवर्सिटीज़ को यह सूचना भिजवाई है। 20 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के दौरान यूजीसी कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ वर्कशाप कर रही है, जिसमें न सिर्फ इस क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा अथवा ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम भारत के इतिहास में पहली बार लागू हो रहा है जिसमें मल्टी डिडिप्लिनरी चॉइस हमारे स्टुडेंट्स को मिल रही है। आपका जो आग्रह था कि हम डिग्निटी ऑफ लेबर की चर्चा करते हैं और मोबिलिटी प्रदान करते हैं, यह उसी प्रयास का एक विाय है। हमारा एक और प्रयास है कि आपने रूडी जी का उत्तर तो सुना है, लेकिन मैं उसमें सप्लीमेंट कर दूँ कि नैट ए ग्रेडेड 1000 कालेजेज़ में भी हम इसको रूल आउट करने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे छात्रों को और देश के नागरिकों को यह सुविधा और लाभ पहुँचे।

HON. SPEAKER: Very good.

12.01 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2038/16/15]

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2039/16/15]

(तीन) वर्ष 2015-2016 के लिए विदेश मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2040/16/15]

(2) (एक) हज कमेटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) हज कमेटी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2041/16/15]

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Urban Development for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2042/16/15]

- (2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2043/16/15]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2044/16/15]

- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2045/16/15]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2046/16/15]

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2047/16/15]

(तीन) वर्ष 2015-2016 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2048/16/15]

(चार) वर्ष 2015-2016 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2049/16/15]

(पाँच) वर्ष 2015-2016 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2050/16/15]

(6) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पहला संशोधन) नियम, 2015 जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2051/16/15]

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Human Resource Development for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2052/16/15]

- (2) Outcome Budget of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2053/16/15]

- (3) Outcome Budget of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2054/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): Madam, on behalf of my colleague, Dr. Harsh Vardhan, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2055/16/15]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshar, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshar, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2056/16/15]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Science and Technology for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2057/16/15]

- (ii) Outcome Budget of the Department of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science and Technology, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2058/16/15]

- (iii) Outcome Budget of the Department of Bio-technology, Ministry of Science and Technology, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2059/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2060/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2062/16/15]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2063/16/15]

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए अंतरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2064/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2061/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2015-2016 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2065/16/15]

- (2) वर्ष 2015-2016 के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2066/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान और निकोबार आईलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान और निकोबार आईलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2067/16/15]

- (3) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2068/16/15]

- (5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2069/16/15]

- (7) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2070/16/15]

- (9) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2071/16/15]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत माँगें।

(Placed in Library, See No. LT 2072/16/15)

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए इस्पात मंत्रालय का परिणामी बजट।

(Placed in Library, See No. LT 2073/16/15)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2074/16/15)

(3)(एक) केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2075/16/15)

(5) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2076/16/15)

(7) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2077/16/15)

(9) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2078/16/15)

(11) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2079/16/15)

(13) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2080/16/15)

(15) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2081/16/15)

(17) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाम्बे, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2082/16/15)

(19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2083/16/15)

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2084/16/15)

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2085/16/15)

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2086/16/15)

(27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2087/16/15)

(29) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-। और II), दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-। और II), दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-। और II), दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2088/16/15)

(31) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2089/16/15)

(33) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2090/16/15)

(35) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2091/16/15)

(37)(एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2092/16/15)

(39)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2093/16/15)

(41)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2094/16/15)

(43) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2095/16/15)

(45)(एक) गवर्नमेंट ऑफ दि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) गवर्नमेंट ऑफ दि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2096/16/15)

(47)(एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2097/16/15)

49)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2098/16/15)

(51)(एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2099/16/15)

(53) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2100/16/15)

(55) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2101/16/15)

(57) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2102/16/15)

(59) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2103/16/15)

(61)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रंगला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रंगला के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2104/16/15)

(63)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2105/16/15)

(65)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2106/16/15)

(67) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2107/16/15)

(69) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2108/16/15)

(71) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइजल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइजल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2109/16/15)

(73) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रवंगला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रवंगला के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2110/16/15)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2111/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, on behalf of my colleague Shri Babulal Supriyo, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Delhi Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Delhi Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2112/16/15]

(3) A copy of the Annual Statement (Hindi and English versions) of the discretionary allotments made under 5% discretionary quota during the calendar year 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2113/16/15]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ-

(1) वर्ष 2015-16 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2114/16/15]

(2) वर्ष 2015-16 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2115/16/15]

12.02 hrs**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following two messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th March, 2015 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendation to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”
 - (ii) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on 12th March, 2015 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”
-

12.03 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
8th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.04 hrs

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES
Statement

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से 'नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल), परिवर्तित नाम एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' विषय पर नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय I में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.05 hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

1st Report

SHRI RAJEN GOHAIN (NOWGONG): I beg to present the First Report (Hindi and English versions) of the Committee on Welfare of Other Backward Classes (2014-15) on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Fourth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on "Reservation in employment and welfare measures for OBCs in Reserve Bank of India" pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services).

12.06 hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

3rd and 4th Reports

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तीसरा की-गर्ड-कार्यवाही प्रतिवेदन और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR

4th Report

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से 'रेडियो कश्मीर, सीबीएस रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के नैमित्तिक कर्मकारों/कलाकारों का नियमितिकरण' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.07 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Hon'ble Prime Minister's visit to Seychelles, Mauritius and Sri Lanka

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल में सेशेल्स, मॉरीशस तथा श्रीलंका की यात्रा के बारे में वक्तव्य दे रही हूं। इन यात्राओं का महत्व इसी बात से पता लग सकता है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 34 साल बाद सेशेल्स, 10 साल बाद मॉरीशस और 28 साल बाद श्रीलंका की यात्रा की।

अध्यक्ष जी, पिछले 34 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री सेशेल्स नहीं गए, 28 वर्षों से पड़ोसी देश श्रीलंका नहीं गए और दस सालों से मॉरीशस भी नहीं गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो 34 साल बाद सेशेल्स गए, 10 साल बाद मॉरीशस गए और 28 साल बाद श्रीलंका की यात्रा की।

महोदया, ये तीनों देश हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देशों में से हैं। इन देशों के साथ हमारा लम्बा इतिहास है, जिसके तहत लोगों के बीच आपसी संबंध, आर्थिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे रहे हैं। इस अवसर पर इन सभी मुद्दों को एक नई ऊंचाई तक ले जाया गया है।

अध्यक्ष जी, सेशेल्स की यात्रा 10 से 11 मार्च, 2015 तक हुई। प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति जेम्स माइकल ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और उन्हें विदाई दी। उन्होंने जो द्विपक्षीय बैठक की, उसके तहत आर्थिक, अवसंरचनात्मक और समुद्री सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गयी। प्रधानमंत्री जी ने भारत के सहयोग से स्थापित किया गया तटीय निगरानी रडार प्रणाली का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस यात्रा के महत्वपूर्ण परिणामों के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दूसरा डार्नियर एयरक्राफ्ट तोहफे में दिया, तीन माह की अवधि के लिए ग्राटिस वीजा दिए जाने की घोषणा की और ई.टी.ए. में सेशेल्स को शामिल किया। एजम्पशन द्वीप पर बुनियादी सुविधाओं का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग, हाइड्रोग्राफी में सहयोग और नौकायन चार्टों की बिक्री के लिए चार करारों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने 'ब्लू इकॉनोमी' में सहयोग संबंधी एक संयुक्त कार्यसमूह गठित करने का भी निर्णय किया।

अध्यक्ष जी, समग्र रूप से प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने संक्षिप्त यात्रा होते हुए भी भारत और सेशेल्स के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। इससे सेशेल्स जो सामुद्रिक संप्रेषण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें एक सकारात्मक भाव सृजित हुआ है।

अब मैं मॉरीशस की बात करती हूँ। मॉरीशस की यात्रा 11-12 मार्च, 2015 को की गई। भारत और मॉरीशस के बीच मौजूदा परम्परागत सौहार्द को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी का मॉरीशस के सभी वर्गों द्वारा सर्वोच्च प्रोटोकॉल के साथ हार्दिक स्वागत किया गया। मॉरीशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति राजुकेश्यवर पुरय्याग तथा प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ बैठक की। मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष, संचार, प्रौद्योगिकी एवं नवसंचार मंत्री और लेबर पार्टी के शिष्ट मंडल ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की।

महोदया, मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मॉरीशस की नेशनल असेम्बली के विशेष सत्र को सम्बोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ मिलकर अपतटीय निगरानी जहाज बाराकूडा को प्रचालित किया, जो कि भारत द्वारा निर्यात किया गया पहला कस्टम द्वारा बनाया गया जहाज है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ मिलकर विश्व हिन्दी सचिवालय भवन के निर्माण की आधिकारिक शुरुआत करने के लिए एक पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा को भी सम्बोधित किया। उन्होंने अप्रवासी घाट को देखा तथा गंगा तालाब पर पूजा-अर्चना भी की।

प्रधानमंत्री जी ने मॉरीशस सरकार द्वारा निर्धारित परियोजना के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की उदार ऋण श्रंखला की घोषणा की और पांच द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। वे दस्तावेज क्या हैं, अगलेगा द्वीप पर समुद्री तथा हवाई परिवहन के विकास के लिए, समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए, चिकित्सा की परंपरागत प्रणालियों और होमियोपैथी में सहयोग के लिए वर्ष 2015-18 के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए और भारत से आमों का मॉरीशस में आयात करने के लिए यह हस्ताक्षर किए गए।

कुल-मिलाकर प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने मॉरीशस के साथ द्विपक्षीय सहयोग को उच्च स्तर तक ले जाने तथा मॉरीशस के साथ भारत के अद्वितीय तथा विशेष संबंधों को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है।

अब मैं श्रीलंका की यात्रा की बात करती हूँ।

The Parliamentary Affairs Minister wants that I should speak in English on Sri Lanka.

HON. SPEAKER: All right.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Hon. Speaker, the visit to Sri Lanka took place on 13-14 March 2015. It was the fourth high level engagement with that country

since the election of President Sirisena on 9th January 2015. The House will recall that President Sirisena paid his first visit abroad to India later in February. The Sri Lankan Foreign Minister and I did reciprocal visits before and after that of the President.

Prime Minister was received by Prime Minister Ranil Wickremesinghe. He held talks with President Sirisena and senior members of the Government. Prime Minister also met the leadership across the political spectrum including former Presidents Kumaratunga and Mahinda Rajapaksa. He addressed the Sri Lankan Parliament and the Ceylon Chamber of Commerce.

The visit expressed India's strong support for democracy and reform in Sri Lanka. Prime Minister noted in his address to the Parliament that recent elections reflected the collective voice of the nation—the hope for change, reconciliation and unity. He expressed confidence in the future of Sri Lanka, defined by unity and integrity, peace and harmony, and opportunity and dignity for everyone. He underlined, that for India, the unity and integrity of Sri Lanka are paramount.

Prime Minister's talks with the Sri Lankan leadership covered a very wide range of issues. He conveyed India's sincere support and good wishes for Sri Lanka's new journey of peace, reconciliation and progress. India stands with Sri Lanka in its efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of society, including the Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Sri Lanka. Prime Minister also declared that we believe that the early and full implementation of the 13th Amendment and going beyond it would contribute to this process.

Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to visit Jaffna. Prime Minister unveiled the foundation stone of the Jaffna Cultural Centre to be built under a grant offered by India. He handed over certificates to the beneficiaries of the Indian Housing Project for internally displaced persons. At Talaimannar, he flagged off the inaugural train on the track to Madhu Road. Prime Minister also visited the ancient temple of Naguleswaram at Jaffna.

The problems of fishermen were also discussed during the talks. Prime Minister pointed out that this was a complex issue involving livelihood and humanitarian concerns on both sides, and India and Sri Lanka need to find a long term solution. Fishermen's associations of both countries must meet at the earliest to work out a mutually acceptable arrangement.

During his stay, Prime Minister underscored our common Buddhist heritage. He visited the Mahabodhi Society in Colombo, offered *dana* to monks and planted a sapling. Prime Minister also offered prayers along with President Sirisena at the venerated Sri Mahabodhi Tree at Anuradhapura.

On the economic side, Prime Minister addressed the Ceylon Chamber of Commerce where he spoke of new purpose and clarity in our policies. He pointed out the benefits of regional economic cooperation and urged Sri Lankan business to take advantage of the opportunities that India is creating for its neighbours.

Among the main outcomes of the Prime Minister's talks in Sri Lanka were:

- a) inclusion of Sri Lanka in the Electronic Travel Authorisation (ETA) Scheme from 14th April, coinciding with the occasion of the Sinhala and Tamil New Year;
- b) setting up of a Joint Task Force to develop the Trincomalee Upper Oil Tank Farm;
- c) announcement of a fresh line of credit for US \$ 318 million for Sri Lanka's railway sector;
- d) extension of currency swap facility of US \$ 1.5 billion by Reserve Bank of India to Sri Lanka's Central Bank;
- e) creating a Joint Task Force for cooperation in the Ocean Economy;
- f) direct flights between Delhi and Colombo by Air India to begin this summer;
- g) holding of a Festival of India in Sri Lanka; and
- h) cooperation in development of a Ramayana Trail in Sri Lanka and the Buddhist Circuit in India.

Four agreements/MoUs were signed during the visit: on customs cooperation; visa exemption for diplomatic and official passport holders; youth development; and construction of an auditorium in Ruhuna University in Matara, Sri Lanka.

The Sri Lanka visit by Prime Minister provided an opportunity to strengthen ties with a very close neighbour and a fellow SAARC member. Recent developments in that country have created new openings and opportunities on many long-standing issues. From our side, the intent was to assure all sections of Sri Lanka that India wishes them well in their quest for peace and prosperity and this was fulfilled in Prime Minister's visit.

Hon. Speaker, I am confident that this House welcomes Prime Minister's visit to these three important countries in the Indian Ocean which has promoted greater understanding and cooperation in this region.

[Placed in Library, See No. LT 2116/16/15]

... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I wish to say something about what the hon. Minister of External Affairs said about the fishermen's issue. After the visit of our Prime Minister, the Sri Lankan Prime Minister asked for action against Indian fishermen, Tamil Nadu fishermen. ... (*Interruptions*) He has given shooting orders if our fishermen go there. ... (*Interruptions*) This is the relationship we are having with Sri Lanka. ... (*Interruptions*) I would request the hon. Minister to see that it has to be taken seriously. Immediately the Sri Lankan Prime Minister allowed the shooting of our Indian fishermen. ... (*Interruptions*) This is a serious issue. Therefore, Madam, I would request you to allow us to discuss this matter under Rule 193 or some other rule. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Madam, if the hon. Members want a discussion on this statement under Rule 193, I am ready for that.

HON. SPEAKER: Okay, if you give notice.

12.20 hrs**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION
No.2522 DATED 11TH MARCH, 2015 REGARDING MONITORING OF
INFRASTRUCTURE PROJECTS***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH): I beg to lay on the table a Statement correcting the reply (Hindi and English versions) to Unstarred Question No.2522 given on 11th March, 2015 by Shrimati Poonam Mahajan and Shri Sanjay Kaka Patil, MPs regarding 'Monitoring of Infrastructure Projects'. This statement pertains to a particular mistake that had crept in the Question. The statement is lengthy. I do not want to take the precious time of the House. I seek your permission to lay the statement on the Table of the House.

HON. SPEAKER: You can lay it on the Table.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2117/16/15.

CORRECTION STATEMENT MADE BY MINISTER OF STATE(INDEPENDENT CHARGE) FOR STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION ENCLOSING THE ANNEXURE -I A (ENGLISH AND HINDI) OF THE REPLY TO PART (a) TO (c) OF THE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2522 RAISED BY SHRIMATI POONAM MAHAJAN AND SHRI SANJAY KAKA PATIL, HON'BLE MEMBERS OF PARLIAMENT (LOK SABHA), ANSWERED ON 11.03.2015, REGARDING "MONITORING OF INFRASTRUCTURE PROJECTS".

I beg to make a statement to enclose the corrected Annexure -_I A (English and Hindi) of the reply to Part (a) to (c) in respect of "Details of State-wise Central Sector Projects showing Time Overruns in Road Transport and Highways, Power and Railways Sector (as on 31.03.2014)" for the Lok Sabha Unstarred Question No. 2522 answered by Ministry of Statistics and Programme Implementation on 11.03.2015.

2. It has come to Ministry's notice that an inadvertent error occurred in Annexure -I A (English and Hindi Versions) in the reply given to the Lok Sabha Unstarred Question No. 2522 answered on 11.03.2015. One line in the first page of the Annexure -I A after S. No. 1 containing the text "ARUNACHAL PRADESH" inadvertently got deleted (during computer work). Consequently, the Projects at S. No. 2, 3 and 4 pertaining to the State of Arunachal Pradesh were inadvertently reflected under the State of Andhra Pradesh.

3. The Corrcing Statement may be brought to the notice of the House.

4. The inconvenience caused is regretted.

12.21 hrs**ELECTION TO COMMITTEE
Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): On behalf of Dr. Harsh Vardhan, I beg to move:

“That in pursuance of sub-section (j) of section 5 read with sub-sections (1) and (2) of section 6 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, subject to the other provisions of the said Act and the Rules and Regulations made thereunder. ”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of sub-section (j) of section 5 read with sub-sections (1) and (2) of section 6 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, subject to the other provisions of the said Act and the Rules and Regulations made thereunder. ”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, the zero hour.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam Speaker, several Members of Parliament including me raised the issue of falling prices of natural rubber in domestic market on various occasions in Lok Sabha and outside. In response to that, the Government repeats the same answer that the price of natural rubber in the country is determined by the price trends in the international markets, that a proposal for enhancing the import duty is under consideration of the Government, and that the Government is implementing various schemes for scaling up the production of natural rubber.

I would like to invite the attention of the Government to the fact that falling prices of natural rubber is largely related to the massive influx of foreign rubber into domestic market under various import routes and channels. This created an artificial surplus of rubber in domestic market as a result of which there is no demand from the manufacturers. It is learnt that the manufacturers have stocks of rubber to meet their requirement for the next six months. This stockpile has already exceeded the mark of 3.5 lakh metric tonnes of natural rubber. Due to the reluctance of manufacturers to buy domestically produced rubber, there has been no rubber trade taking place in domestic market for the last several days. Only middlemen procure rubber at the rate of below Rs.100 per kilogram

Procurement price of one kilogram rubber is Rs.150. In 2011 it was Rs.250. This shows that the rubber growers in the country are in an acute financial crisis. Large scale import of natural rubber is the major reason behind the fall in prices rather than the influence of price trends in international markets. It is obvious from the fact that a fall in prices does not lead to a corresponding decline in prices of finished products of rubber. Therefore, the Government should take urgent measures to regulate the influx of foreign-grown rubber, either by imposing a ban on it or by enhancing the import duty.

Hon. Commerce Minister assured in Rajya Sabha that she was going to enhance the import duty up to 25 per cent. In Lok Sabha, the Parliamentary Affairs Minister assured us that he would instruct the Minister to call a meeting of Kerala MPs and discuss the matter immediately. But nothing happened in the last so many weeks. It is a serious issue. There is one more issue. The import duty on the tyre imported in the country is only 12 per cent. To enhance the import duty on imported tyres upto 25 per cent is a necessity. The used tyres are imported into the country. We have seen the trend in the last so many years that almost 60 per cent of the manufacturing units are closed now and 40 lakh rubber farmers are in severe crisis. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: S/Shri M.B. Rajesh, Joice George, Jose K. Mani and P.K. Biju are allowed to associate with the matter raised by Shri Anto Antony.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, when a promise is made in this House to convene a meeting, it is the duty of the concerned Minister to call the meeting immediately, otherwise what is the use raising this issue and keeping quiet? This also goes against him; we will have to move a Privilege Motion. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will ask the Parliamentary Affairs Minister about it.... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : We asked for the Motion from the Government for the farmers. When its importance is not known to the Government, then what is the use? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से बात करूंगी।

...(*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम लोगों ने लास्ट सेशन में इस विषय को रेज किया था। उन्होंने मीटिंग बुलाने के लिए कहा था। ...(*व्यवधान*) आप बोलते जाइए, हम सुनेंगे ...(*व्यवधान*) यह अच्छा नहीं है। ...(*व्यवधान*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, in the other House, the Minister of Commerce made a statement.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं होता, यह शून्य काल में नहीं होता है।

...(व्यवधान)

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, बार-बार विपक्ष से कलेक्टिव रिस्पॉन्सबिलिटी की बात करते हैं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर यहा बैठी हूं, वे जो भी बोलेंगे उसे मैं स्वयं लिखूंगी और साथी मंत्री को अवगत कराऊंगी, जिससे वे आकर जवाब दे सकें, आप चर्चा शुरू कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मगर जीरो ऑवर में ऐसा हर बार नहीं होता है कि मिनिस्टर को कुछ बोलने के लिए कहूं, यह पद्धति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया (गुना) : मैडम, यह आपके इन्स्ट्रक्शन का उल्लंघन हो रहा है, चेयर का एक सम्मान नहीं रखा जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चेयर ने कुछ नहीं कहा था, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने सोओ-मोटो कुछ कहा था, मैं उनसे बात करूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसका कोई कुछ गलत अर्थ न निकाले। मुझे मालूम है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जीरो ऑवर में कोई एक मंत्री होना चाहिए, आप चर्चा शुरू कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : सुषमा जी, बात बिल्कुल अलग है, यह खबर का विषय है, पहले भी यह दो-तीन बार उठ चुका है। उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि मैं पार्टिकुलर मिनिस्टर को केरल के सांसद को बुलाकर चर्चा करें। यह अभी तक नहीं हुई है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से बात करूंगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि चेयर ने कोई निर्देश दिया था। उन्होंने स्वयं कहा था। मैं आपको इस बारे में सूचित करूंगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि शून्यकाल में चर्चा नहीं होती, कोई मिनिस्टर रिप्लाय नहीं देता।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : महोदया, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले वतन पर मर-मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा। हर संस्था अपनी-अपनी कम्यूनिटी की छवि को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करती है। लेकिन पंजाब में अकाली दल, एस.जी.पी.सी. के माध्यम से लगातार सिखों की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ताजा घटना हमारे लिए बहुत ही खेदजनक बात है।

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं, खेदजनक बोलो।

श्री रवनीत सिंह : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ नानकशाही कलेंडर जारी हुआ है। जिसमें हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कातिलों को शहीद का दर्जा दिया है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया है, उन्हें शहीद बताया है। इससे दुख और खेद की बात क्या होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो गांधी जी के हत्यारे को भी स्टेच्यू के रूप में मान देने की बात करते हैं। अब इंदिरा जी के कातिलों को मान और सम्मान देने की बात करते हैं। पंजाब में बी.जे.पी. और अकाली दल की सरकार है। एस.जी.पी.सी. की ऐसी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि वह सरकार के बिना यह फैसला पंजाब में लागू करे। पंजाब के नौजवान, चाहे फौज में हों या पैरामिलिट्री फोर्सज में हों, एक तरफ वे नौजवान बॉर्डर पर अपनी शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एस.जी.पी.सी. और पंजाब सरकार उन लोगों को शहीद बता रही है, जिन्होंने हमारी पूर्व प्रधान मंत्री जी का कत्ल किया। जो नौजवान बॉर्डर पर अपनी शहादतें दे रहे हैं, उनके मन पर और उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी?

दूसरी बात यह है कि पंजाब के हर परिवार से कोई न कोई मੈबर एन.आर.आई. है। उन सिखों पर कनाडा, अमेरिका में लगातार रैशल अटैक हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद कनाडा, अमेरिका में सिखों पर कोई रैशल अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी?

मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान की रक्षा करने का काम सरकार का है। अगर कोई गलत संविधान, खालिस्तान का झंडा और उसका संविधान बनाने की कोशिश करे, तो उसे रोकने की ड्यूटी किसकी बनती है? सरकार इस कलेंडर को जल्दी से जल्दी गैर कानूनी डाकूमैट डिक्लेयर करे, क्योंकि एस.जी.पी.सी. का इलैक्शन करवाना सीधा केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र में बी.जे.पी. की सरकार है और पंजाब में अकाली दल और बी.जे.पी. की सरकार है, इसलिए इस कलेंडर को जल्द से जल्द इल्लिगल डाकूमैट डिक्लेयर करके वापस लिया जाये। उसके बाद ही सिखों और पंजाबियों का मान-सम्मान बहाल किया जा सकता है। ...(व्यवधान) इस चीज से सिखों और पंजाबियों के दिलों पर बहुत बड़ी चोट लगी है। जब इस कलेंडर को वापस लिया जायेगा, तभी सिख और पंजाबी चैन से रह सकेंगे, क्योंकि पहले ही इन्होंने पंजाब में 70 परसेंट नौजवान ड्रग्स में लगा दिये हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बार-बार रिपीटिशन मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: अगर यह चीज नौजवान और पंजाबियों में चली गयी कि जो लोगों को मारते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, तो फिर पंजाब को बचाना मुश्किल होगा। पहले ही वहां आग लगी हुई है। अगर यह चिनगारी दोबारा लग गयी, तो यह जिम्मेदारी अकाली दल और बी.जे.पी. सरकार की होगी। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, मेरी एक ही रिक्वैस्ट है कि सरकार कम से कम ऐसे इश्यू पर रिस्पांड करे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, शून्य काल की हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: श्रीमती सुषमा स्वराज जी यहां बैठी हैं। वे उस पर रिस्पांड कर सकती हैं। ... (व्यवधान) अगर सरकार इस इश्यू पर रिस्पांड नहीं करेगी, तो फिर किस इश्यू पर रिस्पांड करेगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता। हर बात पर जवाब नहीं दिया जाता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. श्रीनिवास राव।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, आप बैठ जाइये। हर बात का जवाब नहीं होता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल के. श्रीनिवास राव जी की ही बात रिकार्ड में जायेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, आप बैठ जाइये। अभी के. श्रीनिवास राव जी बोलेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप जीरो ऑवर मत चलाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता। शून्य काल में हर समय इस तरीके से नहीं होता। आप सब बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)... *

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only Shri K. Srinivas is permitted.

... (Interruptions)... *

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only what Shri K. Srinivas says will go on record.

... (Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइये। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दू माजरा जी, आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, वे आपके पीछे खड़े हैं और उन्हें तकलीफ हो रही है। आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Hon. Speaker, on 2nd March, 2015, in response to Question No. 1105 that I raised, hon. Minister of Railways replied that the Rajdhani Express 22101/22702 between Vijayawada and New Delhi, an A/c express train, has been introduced in the Railway Budget 2014-15 and will be implemented when rolling stock is available during the current financial year. It is pertinent to note that the said train was announced in the Railway Budget 2014-15 and was to be implemented during the course of the current financial year which ends on the 31st March, 2015. In this connection the Government is requested to take immediate necessary action to provide rolling stock so that the train can be started immediately.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जमशेदपुर में मिडल हाई स्कूल, मुसावनी माइन्स मिडल हाई स्कूल, मुसावनी माइन्स हाई स्कूल, सुरदा माइन्स मिडल स्कूल, सुरदा माइन्स हाई स्कूल, आईसीसी माइन्स हाई

* Not recorded.

स्कूल, छः माइनिंग स्कूल कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित होते थे। सितंबर, 2002 में अचानक सभी विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारियों के भुगतान पर रोक लगा दी गई और उक्त छः विद्यालयों का संचालन बंद कर दिया गया। इससे यहां के बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा और माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने में वंचित रह गए। उक्त विद्यालय बंद होने से 1995 से लगभग 105 शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के वेतन और भत्तों पर रोक लगा दी गई जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 14 शिक्षकों की मौत हो गई।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अविलंब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित विद्यालयों को शुरु किया जाए। यहां भारत सरकार द्वारा 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाए। वीआरएस स्कीम के तहत लगभग 10,000 मजदूरों का एरियर भुगतान बाकी है और अनुकम्पा के आधार पर पिछले दस सालों से एक भी नौकरी नहीं मिली है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you, Madam. Turmeric is a very unique spice which is widely used in food, medicine, pharmaceuticals, dyes and cosmetics, not only in India but also in the South Asian countries, Europe, Africa, etc. Turmeric is the only spice in India which has witnessed intellectual property infringement by the USA. In the light of the increasing tensions and deadlock at the WTO meetings, I would sincerely request the Commerce Minister, through you, Madam, to set up a Turmeric Board which will be extremely helpful to speed up the process of attaining the Geographical Indication, the GI tag, which is pending for the Erode turmeric, which is under the consideration at the WTO along with other regional specific turmeric varieties.

Madam, also for turmeric the Minimum Support Price is never declared. So, the farmers are facing a huge crisis because the prices fluctuate from Rs.4,000 to Rs.15,000. So, it is a serious problem in many areas and I would sincerely request the Minister to, in building the brand value of our country, turmeric will also be a crucial factor, kindly form a Turmeric Board on the lines of Coffee and Rubber Boards.

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kavitha Kalvakuntla.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे सदन में गहरी वेदना प्रकट करने की अनुमति दी। हाल ही में मैं अंडमान गया था। यहां अभी शहीदों की बात हो रही थी। जिन शहीदों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, हमारे देश में उनको आज भी जो सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। जब हम अंडमान गए तो पता चला कि जिन स्वतंत्रता सैनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और सबसे ज्यादा सैनानी काले पानी की सजा में अंडमान में थे। इनमें एक सैनानी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सांवरकर थे। मैं जब वहां पहुंचा, पूर्व सरकार के मंत्री माननीय राम नाईक जी, जो अभी गवर्नर हैं, उन्होंने वहां सांवरकर जी के सम्मान में कविताओं की पंक्तियां प्लेक के नाम पर लगाई थी। वह पंक्तियां थीं -

‘की घेतले न व्रत हे आम्ही अंधतेने
लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्गमाने॥
जे दिव्य दाहक म्हणूनी असावयाचे
बुद्ध्याची वाण धरिले करी हे सतीचे॥’

व्रत लेकर उन्होंने कहा -

‘जयोस्तुते! जयो! श्री महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे
स्वतंत्रते भगवती त्वां अहं यशोयुतां वंदे॥’

जब उन्हें फ्रांस में अरेस्ट किया गया था, तब उन्होंने कहा था -

‘ने मजसी ने परत मातृभूमीसा
सागरा प्राण तलमलला॥’

इनकी सरकार ने ऐसे स्वतंत्रता सैनानी का प्लेक वहां से हटाया था। हमारी सरकार ने कहा था कि उसे हम लगाएंगे, लेकिन आज अंडमान की जेल में स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के कहीं भी यह कवन नहीं लगाया गया है, इसे लगाने की मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी एक और प्रार्थना है कि वहाँ लाइट एंड साउंड का एक प्रोग्राम वर्ष 1989 में शुरू किया गया था। वह भी बिल्कुल निराशाजनक है। मैंने पूछा कि यह ऐसा क्यों है? इससे हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को पता चले कि कैसे लोग थे, उन्होंने कितना अन्याय बर्दाश्त किया। जब कोर्ट से उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई तो श्री सावरकर जी से कोर्ट ने पूछा कि 50-50 साल की दो बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, सौ साल की सज़ा हो गयी है, क्या इतना जीओगे! उन्होंने कहा- क्या इतने वर्षों तक आपकी सरकार वहाँ रहेगी, आपकी सत्ता रहेगी? ऐसे लोग जो हमारे नये पीढ़ी के लिए ऊर्जा बन सकते हैं, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार

जल्द से जल्द वहाँ प्लाक लगाये और उसी तरह से साउंड एंड लाइट के प्रोग्राम को एक ऊर्जादायी और प्रेरणादायी प्रोग्राम बनाया जाए।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे श्री अरविन्द सावंत जी द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी को श्री अरविन्द सावंत जी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. I wish to draw your kind attention towards an important issue pertaining to the molestation and rape of a woman, who was the wife of a CRPF *jawan* staying in the CRPF, quarters by a CRPF personnel and the culprit threatened her of dire consequences if she dared to file a complaint against him. One of the *jawans* who hails from my constituency is working in CRPF and presently posted at Gadchiroli of Maharashtra and has retained his quarters at Pune and kept his wife and family with his in-laws in his quarters, Gadchiroli. It is in the remotest area of Maharashtra and is badly affected by naxalite activities.

In May, 2014 one of the *Havaldars* of CRPF, I do not want to name him, forcibly entered into the quarters of the victim and after locking the premises from inside raped her. She immediately filed a complaint with the DIG of CRPF and though she received repeated assurances that strict action would be taken against the culprit, no action has so far been taken against him. She, later on, came to know that the culprit had worked in the DIG's quarters and had good relations with the DIG. After she received no response from the DIG, she approached the local police station. Here also the DIG tried to influence the local police personnel and instead of registering a case of rape, police had registered a simple case of molestation and had granted sufficient time to the culprit to get bail from the court.

माननीय अध्यक्ष : आप चाहेंगे कि इसकी इन्क्वायरी हो जाए।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: She was approached by the DIG of the CRPF, who was the in-charge of the Telegaon campus, saying that the culprit

and the organisation would pay a sum of Rs. 5 lakh to her and that she should take her case back and not pursue the matter further. When she refused to take back the case, she was threatened of dire consequences. She was asked to vacate the quarters. Her husband was working in Gadchiroli. She was staying in Telegaon campus with her children.

माननीय अध्यक्ष : आप इतना बोलें कि सीआरपीएफ के अधिकारी उनकी समस्या को संज्ञान में लें।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव : मैडम, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उनको क्वार्टर खाली करने के लिए कहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। सदन में हम महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं। एक महिला, जो सरकार के क्वार्टर में काम करती है, उस पर रेप होता है और सीआरपीएफ के सरकारी अधिकारी उनकी मदद नहीं करते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से और डी.जी. से मिला था, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि कल्पिट के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाए।

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Madam Speaker, River Palar flows across my constituency, Vellore to a distance of about 100 kilometres and the water of this river is used for drinking and irrigational purposes. There is a thick concentration of over 1000 tanneries in Vaniyambadi, Pernambut, Ambur and Ranipet which are situated on the banks of the River. They are engaged in the leather tanning process and in that process, they use about 170 chemicals. After the treatment of leather using these chemicals, they discharge untreated effluents. In those days, when there was not much environmental awareness, they were discharged into the river which contaminated underground water. The Supreme Court, on the principle of polluted pay, directed payment of compensation to the farmers and other affected parties. Despite nearly two decades of the passing of the order, the offending tanneries have not paid up the money either due to the closure or due to their economic conditions. As a result, the affected parties and the farmers have not received due compensation.

I urge upon the Ministry of Environment as a one-time measure to pay off the compensation and later on, they may recover it from the offending tanners. I also urge upon the Ministry of Water Resources to sanction adequate funds in

order to rejuvenate River Palar which will be in the interest of lakhs of farmers and other citizens in my constituency.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से देश के और उत्तर प्रदेश के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हर बार प्रश्न-चिह्न उठते रहते हैं। इस समय केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गन्ना किसान तबाह है। चीनी मिले बंद हो रही हैं। वहां पहले से नोटिस लगा कर किसानों को अवगत कराया जा रहा है कि पता नहीं भविष्य में चीनी मिले चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरे देश के अंदर चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी राशि बकाया है। यह केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या तो बनी ही है साथ ही कानून व्यवस्था के लिए बड़ी गंभीर स्थिति पैदा करेगी।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि शुगर डेवलपमेंट फंड में बहुत बड़ी राशि जमा है। देश के अंदर चीनी उद्योग के पुनरुद्धार के बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो सके और साथ-साथ इस देश के अंदर चीनी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए तथा इस वजह से उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था चाहे वह देश का विषय हो या किसी भी राज्य का विषय क्यों न हो, उससे बचाया जा सके, इस बारे में गंभीरता से पहल होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी, श्री ददन मिश्रा और श्री राजेन्द्र अग्रवाल अपने आपको योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Hon. Speaker, Tuticorin is the hub of roadways connecting Tirunelveli, Tiruchendur and Madurai. The four-lane Highway, NH-45B, which connects VOC Port, Tuticorin and Madurai and bypasses Tuticorin, goes around the city. So, the four-lane Highway cuts at three places, namely, from Tuticorin to Madurai, Tirunelveli and Tiruchendur.

To approach Tirunelveli, the four-lane National Highway, 7A with road over-bridge is prevailing but there is only a circular road present at Tiruchendur crossing road at Uppodai which is an accident prone area due to non-availability of an over-bridge. Since 2011, 44 accidents have taken place there causing death of 15 people and 33 people have been grievously injured.

At Kurukuchallai Junction, the old traditional Tirunelveli to Rameswaram route crosses Tuticorin-Madurai Highway, NH-45B. Here also, many accidents happen due to the non-availability of an over-bridge. As these roads are used by many pilgrims and tourists from all over India who visit Kanyakumari, Rameswaram and Tiruchendur, people are suffering a lot due to the non-availability of an over-bridge with service road connectivity at Uppodai and Kurukuchallai Junctions.

I urge upon the Union Minister for Road Transport and Highways to provide a road over-bridge at both Uppodai and Kurukuchallai Junctions at NH-45B.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Madam Speaker, thank you. I would like to raise an important matter before the House.

The number of toll booths is increasing year by year. Now we have 360 toll booths across the country as per the website of the NHAI. Our hon. Minister stated that the Government is going to scrap 125 toll booths in our country. Across the country, incidents of protests against toll booths are rising. These BOT toll people are trying to curtail fundamental rights of the people to travel and also the freedom of expression. Some of the toll booths are being run with the help of goons and anti-social elements. They are harassing even the Padma Bhushan and Padma Shri awardees, and also the Members of Parliament and Members of Legislative Assemblies. Some of the BOT companies have not given the actual expenditure statement for some of the works that they have done. They have given wrong expenditure statement and according to that they decide their toll charges for the vehicles.

In Maharashtra, as we all know, one of the tallest leaders of the Communist Party was brutally murdered. He was fighting against these toll booths and was fighting to protect the right of freedom of expression of our citizens.

I would urge upon the Government, to bring a strong legislation to stop such heinous crimes and atrocities in the toll booths. A direction must go from the

Ministry to the BOT companies that their rates should be as per the Government directions. With these words, I thank you.

HON. SPEAKER: Dr. A. Sampath, Shri M.B. Rajesh, Shri C.N. Jayadevan, Adv. Joice George and Shrimati P.K. Sreemathi Teacher are allowed to associate with the matter raised by Shri P.K. Biju.

श्री भगवंत खुबा (बीदर): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस 16वीं लोक सभा के अंदर करीब 314 माननीय सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा निवेदन है कि ग्रामीण भाग के अंदर डाक सेवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमने माना है और अनुभव भी किया है। भविष्य में भी हम इसके महत्व को अनुभव करते रहेंगे। लेकिन 10 मार्च से करीब 2,50,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन महत्वपूर्ण कर्मचारियों की सेवाओं को कंसिडर करके उन्हें कनिष्ठ डाक कर्मियों के समान वेतन और आम डाक कर्मचारियों की तरह सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। मैं इसके लिए सरकार से आग्रह करता हूँ। अभी ग्रामीण भाग के अंदर डाक सेवाएं टोटल ठप हो गई हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी उनके वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार को विचार कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री सी.आर. चौधरी, रामचरण बोहरा एवम् देवजी एम. पटेल को श्री भगवंत खुबा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बाबू लाल चौधरी - उपस्थित नहीं।

श्री चाँद नाथ।

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पहले सहकारिता के तहत गोदामों के निर्माण, पुनर्निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 100 प्रतिशत यानि पूरा का पूरा खर्च सब्सिडी के तौर पर मिलता था। लेकिन आर.के.वी.आई. के दिशा निर्देश 2014 के अनुसार अब प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत ही सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत आदि के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए माननीय कृषि मंत्री जी से वर्ष 2014 में माननीय राज्य मंत्री सहकारिता विभाग ने इस उद्देश्य हेतु सौ प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करवाने का निवेदन किया था, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस कार्य के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को निर्देश दिए जाएं, जिससे कि नए गोदामों का कार्य प्रारम्भ हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल कस्वां, श्री सी.आर.चौधरी, श्री रामचरण बोहरा, श्री देवजी एम. पटेल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री चांद नाथ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Madam, I thank you for giving me this opportunity to raise a most sensitive and alarming issue about the atrocities committed on the Scheduled Tribes.

I hail from Araku constituency of Andhra Pradesh which is the only tribal constituency in my State. I appreciate the efforts of the Government in enacting the Scheduled Caste/Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 2014. This Act has been enacted but the implementation is very poor in my area. Not only in my area but also in the entire country, the implementation of this Act has not been in proper shape. It is alarming to know that 1.78 crore cases have been pending from the district courts up to the Supreme Court of India pertaining to atrocities.

I wish to bring to the notice of the hon. Minister that this Act provides for actions to be treated as offence but no such cases have been registered by the Government officials. Also, forceful ousting, encroachment of lands belonging to Scheduled Tribes, sexual assaults and any social assault have also been brought under the purview of this Act. This Act also specifies that a non-SC, non-ST Government employee working in the areas of tribal areas and not performing his duties is also subjected to imprisonment up to 6 years. But nothing of this sort has been implemented. Many cases have been pending in the courts.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards this issue and request him to speed up these cases.

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Madam, through you, I want to draw the attention of the hon. Minister of Urban Development regarding development of Amravati as a Smart City.

Hon. Speaker, Amravati is a holy city, the birth place of Lord Krishna's wife Rukmini, having more than 10 lakh cosmopolitan population. People from all over India visit this holy place frequently. Amravati is a Municipal Corporation Area and big business hub which is well-connected with the Indian Railways.

NTC Finlay Mill is situated in Amravati. There is a wholesale cloth market in Amravati which supply cloth to the adjoining States. A Missile factory is going to start there. The India Bull Coal Power Project is also situated in Amravati. Several industries under the Maharashtra Industrial Development Corporation are situated in Amravati. There is a big Railway Junction at Badnera adjoining Amravati in the same Corporation Area. Amravati itself has a big modern Railway Station from where seven trains to the various corners of the country are running.

Hanuman Vyayam Prasarak Mandal is situated in Amravati. Thousands of pupil from all over India and abroad come to study there. Several Medical, Engineering and Polytechnic institutes/Colleges and Marathi, Urdu and English Medium Schools are situated in Amravati. Amravati is a divisional place of adjoining five districts such as Amravati, Akola, Yavatmal, Buldhana and Wasim.

Chikaldhara Hill Station is also adjoining the National Tiger Project to attract the tourists. Amravati is also situated on the Chhattisgarh-Gujarat National Highway.

I would request the hon. Minister of Urban Development to kindly consider the above facts and to instruct the officials concerned to develop Amravati as a Smart City.

13.00 hrs

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आंगनवाड़ी केन्द्र की चर्चा आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। उनकी जो सेविकाएं होती हैं, उनके मानदेय को वेतनमान करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मैं यही प्वाइंट उठाना चाहती थी लेकिन बजट में बोलने का मुझे समय नहीं मिला था। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो सेविकाएं होती हैं, उनको मात्र 14508 रुपये 40 बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए मिलते हैं ताकि वे कुपोषण से बचे रहें। उनको मात्र 3000 रुपये महीना मानदेय मिलता है जिसके तहत उनको बच्चों को कु-पोषण से बचाते हुए न सिर्फ अच्छा राशन ही देना होता है बल्कि सूखा राशन भी उन्हें गर्भवती महिलाओं को महीने में एक बार देना होता है। उसके बाद उनको 22 रजिस्टर मेनटेन करने होते हैं। जन्म-मृत्यु का भी पंजीकरण वे ही करती हैं। उनकी ड्यूटी परीक्षाओं एवं चुनाव में भी लगती है लेकिन उनको कोई भत्ता या सम्मान कुछ नहीं दिया जाता है। यदि एक सेविका की तनखाह मात्र 3000

रुपये महीना होगी और जो 14508 रुपये में उसको तीस दिन चालीस बच्चों को खिलाना होता है और उसमें एक एल.एस. भी रख दिया गया है जो महीने में तीन चार दिन आकर निरीक्षण भी करता है, माननीय अध्यक्ष जी, यह बात आपसे भी छिपी हुई नहीं है कि आंगनवाड़ी केन्द्र में कितना भ्रष्टाचार है। वे सरेआम कहती हैं कि हमें एल.एस. को भी देना है, ऊपर भी पहुंचाना है और उन चालीस बच्चों को भी हमें कुपोषण से बचाते हुए हैल्दी राशन देना है ताकि वे स्वस्थ रहें तो यह बात सोचने योग्य है कि वे सेविकाएं मात्र 3000 रुपये महीने में अपने आपको और बच्चों को क्या स्वस्थ कर पाएंगी? इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि एक तो उनके मानदेय को वेतनमान किया जाए और कम से कम उनकी तनखाह को 9000 रुपये उनके सम्मान को देखते हुए किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री धनंजय महाडीक, श्री डी.के.सुरेश, श्री एस.पी.मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों में जो स्कूल हैं और खास तौर से जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें पढ़ाई नाम मात्र की रह गई है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स बिल्कुल खराब है और उनकी तुलना में पब्लिक स्कूल के बच्चों में पढ़ाई का स्तर बहुत है। उसका एक कारण यह भी है कि स्कॉलरशिप उनको जो मिलती भी है तो बाद में मिलती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्कॉलरशिप शुरू में जैसे ही एडमिशन ले लिया जाता है, 6 महीने की पहले दे दी जाए और ज्वाइंट एकाउंट प्रिंसिपल के साथ खोल दिया जाए और हर महीने या हर तीन महीने बाद उनको दे दी जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई कर सकें।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है। ज़ीरो ऑवर में इतना लम्बा भाषण नहीं देना होता है।

डॉ. उदित राज: दूसरी बात यह है कि दो लाख से ज्यादा जिन पेरेंट्स कि इंकम है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप जैसे नहीं मिल रही है और जैसे ओबीसी की 6 लाख की है तो ऐसे ही 6 लाख की इंकम लिमिट इनकी भी लगाई जाए। तमाम एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया जाता। यूजीसी का एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं देते। आपकी बात हो गई है।

डॉ. उदित राज: यूजीसी द्वारा पिछले वर्ष 3 प्रतिशत ही ग्रांट दी गई थी क्योंकि यूजीसी ने पहले पैसा खर्च नहीं किया था। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डा. उदित राज जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। एयर कनेक्टिविटी की बात बोल रहा हूँ। मैक्सिम समय यहां पर नॉर्थ ईस्ट की बात उठती है लेकिन हम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलता है।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। बराबर मौका दिया जाता है।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : मैडम, जो निर्वाचन क्षेत्र जोरहाट है, यहां पर एयर कनेक्टिविटी खराब है। गुवाहाटी हम लोग सुबह नहीं पहुंच पाते। 11 बजे से हम लोगों की कोई फ्लाइट नहीं है। वहां पर वापसी में समस्या है और जोरहाट में दो यूनिवर्सिटी है। एयर इंडिया ने पूरा विद्वान कर दिया, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन फिर भी सर्विसेज रैस्टर नहीं की गई और किराया भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज को वह थोड़ा देखें।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र भावनगर की समस्याओं को रखने का मौका दिया। जैसे कि सब जानते हैं कि देश में 75 प्रतिशत नमक का उत्पादन अकेले गुजरात राज्य में होता है और पूरे गुजरात राज्य का 50 प्रतिशत उत्पादन मेरे निर्वाचन क्षेत्र भावनगर में होता है। भावनगर नमक का इतना बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी यहां की नमक कंपनियां सुविधाओं के अभाव में काम कर रही हैं। नमक की आवश्यकता देश के प्रत्येक नागरिक को है। इसलिए नमक के व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हम नमक निर्माता कंपनियों को उनकी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तो नमक का व्यापार दम तोड़ देगा। गुजरात के भावनगर में स्थित कंपनियों में आने-जाने का मार्ग असुविधाजनक है। मजदूरों को रहने की सुविधा, उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधा और उनके आरोग्य की सुविधा उपलब्ध कराने की बहुत जरूरत है।

इसके अलावा गुजरात में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है, फिर भी साल्ट कमिश्नरेट गुजरात में नहीं बैठते हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि साल्ट कमिश्नरेट गुजरात में या भावनगर में बैठें और नमक उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान देकर उनकी समस्याओं को हल किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री राज कुमार सैनी, आप यह क्या मुद्दा उठा रहे हैं, यह स्टेट का मैटर है, यहां आप पॉइंट्स की बात क्यों कर रहे हैं, यह मैं समझी नहीं, आप थोड़े में बताइये।

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : मैडम, यह पूरे देश का मैटर है, आपने मुझे जीरो ऑवर में इसका जिक्र करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे देश में प्रदूषित जल निकासी की जो समस्या है, वह बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। प्रधान मंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। परंतु देश के गांवों के तालाबों में सड़ रहे गंदे पानी की निकासी की एक बड़ी समस्या है, जो इसकी राह में एक रोड़ा बना हुआ है। पहले तालाबों का पानी मवेशियों के पीने और सिंचाई हेतु इस्तेमाल हो जाता था, परंतु अब तालाबों में शौचालयों का गंदा पानी जाने के कारण वह न तो मवेशियों के काबिल रहा है और न वह पानी सिंचाई के काबिल रहा, बल्कि वह बीमारियों को अलग से न्यौता दे रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस समस्या का समाधान पूरे देश के पैमाने पर किया जाए। आज यह केवल प्रदेश का विषय नहीं रहा, यह पूरे देश का विषय बन गया है। क्योंकि ज्यों-ज्यों हमने शौचालयों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, उनमें से जो गंदा पानी जा रहा है, उसमें तरह-तरह के कैमिकल्स जा रहे हैं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए पूरे देश में ही बड़ा विस्तृत सिस्टम लाया जाना चाहिए, जिससे तालाबों के सड़े हुए गंदे पानी से गांवों में होने वाली बीमारियों से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह प्रश्न केवल मेरे लोक सभा क्षेत्र तक सीमित है। वहां 135 किलोमीटर लम्बा सीमा विवाद है, एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है और 135 किलोमीटर मेरे लोक सभा क्षेत्र का हिस्सा बनता है। वहां तीन मार्ग हैं - पानीपत-खटीमा मार्ग, करनाल-मेरठ मार्ग और अम्बाला-सहारनपुर मार्ग। इन तीनों मार्गों पर टोल टैक्स लगाया हुआ है। पिछले पचास सालों से ये मार्ग बने हुए हैं और पुल भी पचास सालों से बने हुए हैं। जो कीमत कभी आई होगी, वह वसूल हो चुकी। वहां कोई नई सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इन तीनों मार्गों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है और यह भी संभव है कि सरकार के द्वारा वह टोल टैक्स न लगाया गया हो, बल्कि कोई माफिया ही वहां पर पैसे वसूल कर रहा हो।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वहां तुरंत टोल टैक्स को समाप्त किया जाए। इसी के साथ-साथ सीमा विवाद भी आजकल ऐसा बढ़ गया है कि मेरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा में कभी दीक्षित अवार्ड बना था, जो कभी भारत सरकार के गृह मंत्री होते थे, उनकी अध्यक्षता में वह अवार्ड दिया गया था और सीमा निर्धारित कर दी गई थी। मैं चाहता हूँ कि जो दीक्षित

अवार्ड है, जिसके अनुसार सीमा निर्धारित की गई है, जिस प्रदेश की जमीन जहां पर है, उस प्रदेश के किसानों को वहां पर खेती करने का अवसर मिले और उन्हें सुरक्षा मिले। धन्यवाद।

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे यहां आगरा जनपद में अभी कुछ दिन पहले इतनी भयंकर बरसात और ओला पड़ा है, जिससे किसानों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, कई लोग मर चुके हैं और जो कम्पैनसेशन वाला मीटर है, वह बहुत पुराना नियम है। आज नौ हजार रुपये प्रति हैक्टेअर के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है। मगर नौ हजार रुपये हैक्टेअर के हिसाब से दो हजार रुपये प्रति बीघा पड़ता है। दो हजार रुपये प्रति बीघा पर तो आज किसान की जुताई भी नहीं हो पाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की लागत का डेढ़ गुना का वायदा किया गया था। आलू की फसल 90 पर्सेंट खत्म हो चुकी है। आलू की फसल के लिए आज कम से कम 40 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से लागत पड़ती है। किसान बिल्कुल मर चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब ऋणों को माफ किया जाए और किसानों का जो पुराना नियम है, उसको बदला जाए तथा किसानों को फसल बीमा योजना के आधार पर हर फसल की लागत जैसे आलू की लागत 40 हजार रूपए है, गेहूं की लागत करीब 20 हजार रूपए है तथा सरसों की लागत करीब 15 हजार प्रति बीघा के हिसाब + लाभ के आधार पर बीमा दिलाया जाए तथा मुआवजा दिलाया जाए। पशुधन के मरने पर भैंस के मात्र आज 15-16,000 रूपए प्रति के हिसाब से मिलता है, जबकि आज भैंस की कीमत बाजार के हिसाब से करीब 70,000 रूपए मिलना चाहिए। अतः इस पुराने नियम को बदलना जरूरी है।

SHRI NEIPHIU RIO (NAGALAND): Madam Speaker, thank you very much for giving me time.

Madam, with the advancement of knowledge and technology, the world has shrunk into a global village and we are witnessing to the fast pace of progress and development in the country. However, the North-Eastern Region and particularly, the Nagaland is facing poor connectivity problem.

You are aware that Dimapur Airport is operated since 1972. However, it has now been reduced to only five flights in a week connecting to Kolkata and that is also sharing with Dibrugarh in Assam. In November, 2014, one flight was introduced only on Monday but it has again been withdrawn on 12th February,

2015. There are high fares due to the fact that there is a 'no fly zone'. The flights have to take a longer route of Manipur.

Therefore, I urge the Air Headquarters under the Defence Ministry to issue clearance of 'no fly zone'. During the visit of the hon. Prime Minister at Dimapur in 2014, the night landing facility was operated but later on it was closed. It should be operated for all the flights.

You are aware that Nagaland is not having even a single private airline in operation. We are left with no option but with Air India. Therefore, I request the Ministry of Civil Aviation to ask the corporate bodies to perform their social responsibility in these difficulty areas. I also request the Civil Aviation Ministry to provide us a flight which connects us to Delhi via Guwahati or Kolkata on a daily basis. The Dimapur Airport needs to be improved and upgraded. The intra-connectivity flights within the North-East also need to be restarted immediately.

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बहराइच की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदया, हमारा संसदीय क्षेत्र बहराइच नेपाल की सीमा से सटा हुआ, चार नदियों से घिरा, जंगल प्रभावित तराई क्षेत्र है। जनपद बहराइच मूल रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जनपद बहराइच में सन् 2013 में मैडिकल कॉलेज का प्रस्ताव हुआ था। इस मैडिकल कॉलेज के लिए जिला प्रशासन द्वारा 20 एकड़ जमीन उपलब्ध करानी था। जमीन उपलब्ध न कराने के कारण मैडिकल कॉलेज स्थगित कर दिया गया है। महोदया, सरकार की यह योजना सन् 2013 में आई थी, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ न होने के कारण योजना जस की तस, धरी की धरी रह गई है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए राज्य सरकार की मंशा साफ होती तो जमीन का रोना न रोना पड़ता। ... (व्यवधान) महोदया, यह समस्या उन लाखों लोगों की है, इन समस्याओं को देखते हुए जनपद में उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया जाए कि वहां पर मैडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध करा कर मैडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए।

HON. SPEAKER: Shri Daddan Mishra is permitted to associate with the issue raised by Sadhvi Savitri Bai Phule.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, this is a local issue but it has a national ramification because it deals with my constituency. When waterways were in operation in Cuttack, Odisha, during the British period after 1866 and when Odisha faced a very severe famine, more than 10 million people had perished during that period. The traders had build up a Malgodown. Subsequently, when the Indian Railways or the Bengal-Nagpur Railway came into operation in 1901, then this area was given by the Bengal Presidency to the Railways. A levy was charged, a license fee was being collected from the traders, wholesale traders, sub-wholesale traders and shopkeepers and railway became the mode of transport. Licence fee is being collected. Peculiarly in February 2015, a notice has been served. When I went back last weekend, a large number of traders from Malgodam – they are thousands in number as Malgodam, Cuttack caters to the whole of the State providing food stock and other materials – came to me and said that this was what the NDA Government had done. Railway gave a notice to them to vacate this place by 31st of March. Thousands of traders are going to be shifted from that place. What for? The whole mechanism of providing succour to different districts is going to be hampered. My request is this. They are paying licence fee. They are in occupation of this place for the last 130 or 140 years. This is the concern, which I thought that I should bring it to the notice of this Government, through you, Madam.

I am raising it in 'Zero Hour'. I know that the Government will not respond to me but, I think, there will be some response from the Government ...

(Interruptions)

HON. SPEAKER: You are knocking the door.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would request the Government to take immediate steps to withdraw this eviction notice so that they can continue to do their work in Malgodam, and the Malgodam traders should not be evicted.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): महोदया, आपने मेरे क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में चन्दगढ़ ताल्लुका है, जो

पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। यूनेस्को ने इसे इको सेंसेटिव जोन और वर्ल्ड हैरीटेज का दर्जा दिया है। हाल ही में यहाँ ए.वी.एच. नामक एक केमिकल फैक्ट्री शुरू हुई है, जो कोलतार डिस्टिलेशन प्लांट है। यह कर्नाटक से सिर्फ दस किलोमीटर दूर है। मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट एंड फॉरेस्ट की मान्यता की इसको जरूरत है, क्योंकि यह ए ग्रेड में आता है, पर कंपनी ने इसे बी ग्रेड दिखाकर स्टेट से परमीशन ली है। इसमें जो केमिकल्स बनते हैं, उनसे जो पॉल्यूशन होता है, उससे कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, ऐसा पता चला है। जो ए.वी.एच. कंपनी है, अगर इसके अगल-बगल में आप देखेंगे तो दस किलोमीटर की रेडियस में तीन बड़ी नदियाँ और 22 वाटर रिजर्व वायर्स हैं, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को पानी सप्लाई करती हैं। ये सभी इसकी वजह से हैपर हो सकती है। इसके पॉल्यूशन की वजह से जो केशू क्रॉप, जंगल की वनस्पतियाँ और आम इन्सान को खतरा पैदा हो गया है। 72 ग्राम पंचायतों ने इसके खिलाफ एक एजेंडा निकालकर विरोध प्रस्ताव दिया था, फिर भी यह फैक्ट्री शुरू हो गई। 28 फरवरी को दस हजार से ज्यादा लोगों ने एक मोर्चा निकालकर यह पूरी फैक्ट्री जला दी है, फैक्ट्री के साथ केमिकल के चार टैंकर भी जला दिए हैं, गाड़ियाँ जला दी हैं, लॉ एंड आर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन यहाँ पर निर्मित हुई है। इस फैक्ट्री का रॉ मैटीरियल बेल्लारी, कर्नाटक से आएगा, जो कि वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है, वह जयगढ़ पोर्ट जाएगा, जो साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर है। इसका वेस्ट पूना में जाएगा, जो 200 किलोमीटर दूर है। यह सभी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वह इकोसेंसेटिव एरिया में जाएगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जन भावना का, लोगों की भावना का आदर करते हुए इस फैक्ट्री को तुरन्त हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। अभी विधानसभा में भी पचास से ज्यादा एमएलएज ने इसका प्रोटेस्ट किया है। अभी भी लोग धरने पर हमारे क्षेत्र में बैठे हैं। आप कृपा करके यह फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, I would like to draw the attention of the Ministry of Water Resources, through you, that Farakka barrage project is the largest barrage across the river Ganges in our country. The length of that barrage is two miles and it consists of 109 lock-gates. It used to cater the requisite water on the one hand to Bangladesh and on the other hand it facilitates the flow of water to the Kolkata port. Three days earlier, 45 lock-gates got collapsed and totally washed away. Naturally, huge quantum of water is being flown to Bangladesh. It is a national loss. So, the Government should take serious note of it, and maintenance should be given the highest

priority. Farakka barrage project is a national project. It is a strategic project. It needs to be given due consideration.

HON. SPEAKER : Shri Md. Badaruddoza Khan is permitted to associate with the issue raised by Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, जब देश में अनाज की कमी थी तो पंजाब के किसान ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि देश को आत्मनिर्भर बनाकर खुद वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाया - कभी कुदरत की मार, कभी किसी कानून की मार, चाहे वह भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे स्वामिनाथन की रिपोर्ट को लागू न करने का मामला हो, चाहे एम.एस.पी. को खत्म करने का मामला हो। अभी जो मार किसान पर पड़ने वाली है, वह यह है कि एफ.सी.आई. ने ऐलान कर दिया है कि हम 50 परसेंट कम गोहूँ पिछली बार से खरीदेंगे जिससे बेमौसमी बरसात की मार झेल रहे किसान को और भी दोहरी मार पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को यह निर्देश दें कि वह पंजाब के किसानों का पूरे का पूरा गोहूँ खरीदें। इसमें कमी न करें ताकि पंजाब के किसान को बचाया जा सके। पहले ही वह खुदकुशी कर रहा है, कर्ज़ई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एफ.सी.आई. को आर्डर दिया जाए कि वह पूरा गोहूँ खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदया, मेरठ में एक मीट प्लांट है। ... (व्यवधान) इसमें 30 नवंबर को 90 टन मीट पकड़ा गया जो बाद में गोमांस निकला। इस मीट को बेचने की इजाज़त नहीं थी पर मालिकों ने इसे बेच दिया। इसको बंद किया गया। इसी प्रकार की घटना 2012 में भी हुई थी। तब 70 टन मीट पकड़ा गया था। वह भी गोमांस निकला था। उसको भी इसी प्रकार से बेच दिया गया था। मेरे क्षेत्र की कठिनाई यह है कि इस प्रकार से मीट प्लांट के नाम पर अवैध कमेले वहाँ पर चल रहे हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशुओं का कटान हो रहा है, गोवंश का कटान हो रहा है। पशुओं की चोरी हो रही है, पशुओं को छीन लिया जा रहा है और सारे के सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत रहती है। मेरा निवेदन यह है कि इस बार भी इसमें छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। जो मथुरा लैब से टैस्ट होकर आया कि यह गोमांस है, उस पर सवाल खड़े करके दोबारा सैम्पल भेजने की मांग हो रही है। जो प्रकरण है, इसमें अधिकारियों की संलिप्तता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि संपूर्ण प्रकरण की जाँच कराएँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे इस अवैध कारोबार को बंद कराएँ और गोवंश की हत्या बंद हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष जी, इस वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना करने की घोषणा की है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं। इस वर्ष तीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खोले जाने हैं। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद में की जाए। संभाजीनगर एशिया का सबसे तेजी से औद्योगिक विकास करने वाला शहर है। आने वाले दिनों में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर शुरू होने के बाद विकास की गति और बढ़ने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि इस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। यहाँ ज़मीन की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ ल्यूपेन, ओखाड और अजंता फार्मा जैसी कई फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं। चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर ने भी माननीय मंत्री से विनती की है। मैं आपके माध्यम से विनती करूँगा कि यह इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ संभाजीनगर में खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती वीणा देवी।

कोई नाम लेकर एप्लीगेशन नहीं लगाना है, जनरल जो बात बोलनी है, वह बोल दीजिए।

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर): अध्यक्ष जी, हमारे मुंगेर संसदीय क्षेत्र के बाढ़ विधान सभा के नगर परिषद् एरिया में भारत सरकार के शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वहाँ के गरीबों एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए एक आवास परियोजना चलाई गई थी। वहाँ इसके लिए जो रकम दी गई थी, वह बिचौलियों के हाथ धरी की धरी रह गई लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो विकलांग हैं, उन्हें अभी कोई सहारा नहीं मिल रहा है। क्या यह शहरी विकास है? तत्काल कार्रवाई करते हुए आवासीय परियोजना प्रारंभ कर लाभार्थियों को उनका हक प्रदान किया जाए।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.25 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.34 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at Thirty Four Minutes
past Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to take effective measures to check pollution caused by tar balls in the coastal region of Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : भारतीय समुद्री सीमा में 'टारबोल प्रदूषण' के कारण गुजरात के तीथल, मरोली, उमरगांव तथा प्राकृतिक सौन्दर्य और पर्यावरण के लिए जाना जाने वाला नारगोल का प्रवासन सेन्टर भयग्रस्त हो गया है। ऑयल युक्त कचरे के कारण समुद्र में जमी हुई काई भी प्रदूषित हो रही है जिसके कारण वहां के लोगों में चमड़ी का रोग बढ़ रहा है। समुद्र में ऑयल फैलने के कारण उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं जैसे - डॉलफिन, कछुआ, जैलीफिश, दरियाई जीवों इत्यादि को हानि पहुंच रही है तथा यह जीव-जंतु प्रदूषण के कारण मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। इस फैलते प्रदूषण के कारण समुद्री जीव सृष्टि के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसके कारण ग्राउण्ड वाटर भी प्रदूषित हो रहा है तथा यहां के कोस्ट गार्ड के पास अपनी खुद की कोई लेबोर्ट्री भी नहीं है। एन.आई.ओ. ने पर्यावरण मंत्रालय को लेब बनाने के लिए भी कहा है लेकिन कोस्ट गार्ड लेब की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस प्रदूषण के मूल तक जाने तथा उससे निजात पाने के लिए कड़ कदम उठाए जाएं और गुजरात में 'वाटर फिंगर प्रिंटिंग लेबोरेटरी' की स्थापना की जाए।

(ii) Need to construct a new railway line from Bilaspur in Chhattisgarh to Jabalpur in Madhya Pradesh via Mungeli, Kawardha and Mandla

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर रेलवे स्टेशन से वाया मुंगेली, कवर्धा, मंडला, जबलपुर तक ब्रिटिश कालीन सरकार द्वारा रेल लाइन सर्वेक्षित है जिसके लिए कृषि एवं वन विभाग की भूमि अधिग्रहित की गई है। इस रेल लाइन के निर्माण से कवर्धा में खनिज संकट के पर्याप्त भंडार का सही दोहन हो पाएगा एवं रास्ता सुलभ परिवहन होने से राज्य एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही कवर्धा में स्थित भौरमदेव शक्कर कारखाना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पंडरिया में निर्मित होने वाले शक्कर कारखाना का उत्पाद देश के अनेक भागों में आसानी से परिचालित होने से राज्य के किसानों को गन्ने का मूल्य समुचित रूप से प्राप्त होगा जिससे किसान आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तथा रोजगार के सृजन होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। नए औद्योगिक क्षेत्र में विकास बढ़ेगा। संबंधित क्षेत्र में यातायात के अभाव में उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने में पीछे रहते हैं। वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अतिशीघ्र स्वीकृत कर रेल लाइन का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ सभी जिलों का समग्र विकास होगा अपितु साथ ही सरकार को राजस्व की उचित मात्रा में प्राप्ति होगी जिससे छत्तीसगढ़ राज्य को एक नई दिशा मिलेगी।

(iii) Need to provide funds for expenditure incurred by co-operative credit societies in disbursement of wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme particularly in Rajasthan

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएं राज्य में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना' श्रमिकों के माध्यम से भुगतान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संस्थाओं द्वारा 39 लाख मनरेगा श्रमिकों को भुगतान का कार्य अब तक संतोषजनक हो रहा है परंतु इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन हेतु होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। अतः इन संस्थाओं को इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी मजबूत है तथा इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी सीमांत कृषकों में लगभग 80 प्रतिशत को फसली ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है। अतः यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हो रहे खर्चों की पूर्ति स्वरूप अन्य एजेंसियों की भांति कुछ प्रतिशत निर्धारित किया जाए। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से भी निवेदन किया है।

अतः मेरा माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से आग्रह है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में श्रमिकों को भुगतान में हो रहे व्ययों हेतु सहकारी संस्थाओं को प्रति खाता प्रतिवर्ष अन्य संस्थाओं की भांति राशि उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए और किए गए भुगतान की राशि के 2 प्रतिशत के समक्ष राशि सहकारी संस्थाओं को प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवाई जाए।

**(iv) Need to ban the production of tobacco products
in the country**

श्री संजय काका पाटील (सांगली) : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण तंबाकू सेवन भी है। तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों पर होने वाले खर्च से परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। तंबाकू सेवन के आर्थिक प्रभाव भयावह है। स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ तंबाकू जनित बीमारियों पर खर्च हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय का करीब 4.7 प्रतिशत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों पर खर्च हो रहा है। तंबाकू से होने वाली राष्ट्र को आर्थिक क्षति भारत में जी.डी.पी. का करीब 2 प्रतिशत है। तंबाकू जनित बीमारियों पर वर्ष 2011 में 16,800 करोड़ रुपये खर्च हुए। तंबाकू से सालाना एक लाख करोड़ रुपये की हानि होती है।

सरकार ने तंबाकू व अन्य तंबाकू उत्पादक (संशोधन) विधेयक को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। सिगरेट, बीड़ी व तंबाकू से बने पदार्थ जैसे गुटखा, खैनी इत्यादि से ओरल कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब समय आ गया है जब सरकार को इसे रोकना होगा व इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगे व तंबाकू उत्पादों के उत्पादन पर रोक लगा दी जाए। हमें अपने नौजवानों को इस व्यसन से बचाना होगा। सिगरेट उत्पादन निर्यात के लिए हो परंतु देश में इसे रोकना होगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस दिशा में तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं।

**(v) Need to undertake census of OBCs, Notified Tribes
and Vimukta Jati and Nomadic Tribes**

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : केन्द्र सरकार ने हाल ही में 15 मार्च के पहले जाति आधारित जनगणना पूरी करने का राज्यों को आदेश दिया है। सरकार ने जनगणना के प्रस्ताव के प्रारूप को देश में राज्यों के ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका को मान्यता के लिए भेजा है। इस प्रस्ताव में एस.सी. एस.टी. एवं अन्य जातियों को 'इतर' ऐसे शब्द से उल्लेखित किया है। इसके कारण ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जाति की स्वतंत्र जनगणना न होने से इन जातियों के समाज पर अन्याय हुआ है। वर्ष 1931 में ब्रिटिश काल से अभी तक ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जाति की जनगणना न होने से इस समाज का 66 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास न होने से आज भी पिछड़ा हुआ है। भारतीय संविधान की धारा 340 के अनुसार ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करना अनिवार्य है। लेकिन इस समाज की जाति निहाय स्वतंत्र जनगणना न होने से इन जातियों की निश्चित संख्या कितनी है, इसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि प्रस्ताव पारित कर ओबीसी, एनटी और विजेएनटी जाति की स्वतंत्रता से जनगणना कराने के विषय में शीघ्रता से कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।

(vi) Need to declare Ahmednagar district in Maharashtra as a tourist destination of national importance and also provide necessary tourist facilities in the district

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : मेरा संसदीय क्षेत्र अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण एवं विस्तार में बड़ा जिला है। महाराष्ट्र तथा देश में अहमदनगर जिला एक ऐतिहासिक दृष्टि से ख्याति प्राप्त है। पर्यटन, भौगोलिक विस्तार, पहाड़ी विस्तार, बड़े जल संचयन क्षेत्र, पुरातन वास्तु, धार्मिक पर्यटन, कृषि उपज व उत्पादन, औद्योगिक इकाई, रक्षा मंत्रालय के बड़े कार्यालय व आर्मी प्रशिक्षण तथा स्थायी कैम्प, देश की सबसे बड़ी शुगर इण्डस्ट्री, प्राकृतिक सौन्दर्य की धरोहर आदि विभिन्न क्षेत्र में अहमदनगर जिला महाराष्ट्र के अन्य जिलों से भिन्न पहचान रखता है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से इस जिले को मुख्य मानबिंदु पर लाने में कोताही बरती जा रही है तथा स्थानीय शासन तंत्र भी इस विषय को जिले का राजस्व बढ़ाने की दिशा में उदासीन होने का समय-समय पर अनुभव आया है। अहमदनगर जिले में मुख्य दर्शनीय पर्यटन स्थल निम्नवत् हैं :-

1. नगर का ऐतिहासिक किला जिसमें अंग्रेजों ने पंडित नेहरू एवं लौहपुरुष सरदार पटेल साहेब को कैद रखा था;
2. धार्मिक दृष्टि से अवतार मेहरबाबा;
3. शिर्डी के साईबाबा;
4. शनिशिगणापुर;
5. मोहाटा देवी; एवं
6. महान जैन संत आचार्य सम्राट आनन्द ऋषि जी का तीर्थस्थान।

मुगल शासन काल में अहमदशाह निजाम ने यह शहर बसाया और उसकी यह राजधानी रही। यहां कई प्रवेश द्वारों के अवशेष एवं दरवाजे आज भी शहर की शान है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अहमदनगर जिले में आपार पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में स्थापित करते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया जाए तथा इसके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य योजना तैयार करके इसे स्मार्ट सिटी में शामिल करके बजट में इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए।

**(vii) Need to improve medical facilities in hospitals in
Sant Kabir Nagar district, Uttar Pradesh**

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैं सरकार का ध्यान जिला अस्पतालों की बुरी हालत की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो अस्पताल अहम भूमिका निभाते थे, आज वह असफल हो रहे हैं। अधिकांश अस्पतालों में जांच के लिए आधुनिक मशीनों का नितांत अभाव है जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाना पड़ रहा है जहां उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। जिला संत कबीर नगर (उ.प्र.) जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर सी.टी. स्कैन, डायलाइसिस, कैथ लैब जैसी कोई भी रेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजी की आधुनिक मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे पिछड़े और गरीब इलाकों में आम जनता को समय पर और सही इलाज मिल सके।

(viii) Need to establish more medical colleges in the country

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): India which is having a population of 125 crore is one of the most dynamic democracies in the world, having a doctor-population ratio of 1:1700 against the projected target of 1:1000 made by High Level Expert Group for Universal Health Coverage constituted by the Planning Commission. To achieve the goal set by the High Level Expert Group (HLEG), India has to establish 200 new medical colleges within 10 years to meet the projected shortage of 6,00,000, doctors.

Further, India is facing gross shortage of medical teachers. More attention is required to render medical services, education and research. Most of all, rural health services are in dire need of trained specialists and super specialists.

60% of specialist posts are still vacant at community health centres. This shortage is expected to rise to about 50% in the next four years. With recent rationalization in infrastructure and faculty requirement for medical colleges, the number of MBBS and post graduate seats is likely to double soon.

Despite the low doctor-population ratio, other indicators like literacy, hygiene and health awareness also play a major role to achieve the World Health Organisation benchmark of 4 doctors for every 1000 people. For achieving the WHO benchmark of doctor-population ratio, long term planning to establish more medical colleges across India covering all the States & Union Territories is required.

I request the Honble Union Minister for Health & Family Welfare to look into the matter for establishment of 200 targeted medical colleges as early as possible.

**(ix) Need to provide funds for Special Tiger Protection
Force for Sariska Tiger Reserve**

श्री चाँद नाथ (अलवर): मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर (राजस्थान) के अंतर्गत आने वाले 'सरिस्का टाइगर रिजर्व' में बाघों की सुरक्षा के लिए गठित होने वाली राष्ट्रीय बाघ संरक्षण बल (स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स) के गठन के लिए आवश्यक बजट की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा 2012 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की स्वीकृति मिल चुकी है और वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्य योजना में आवश्यक वित्तीय प्रावधान सम्मिलित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए, जो लगभग 112.00 लाख रुपये थे लेकिन 2013-14 के बजट में इस राशि का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसके बाद 2014-15 के बजट में भी सरकार द्वारा कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए।

**(x) Need to bring a health insurance policy for
the benefit of common man in the country**

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : हमारे देश में आजादी के बाद से ही आम आदमी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसता रहा है। वर्षों के बाद आज आमजन के मन में सरकार के प्रति उम्मीद की किरण जागी है। मैं सरकार का ध्यान देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। देश में इलाज के लिए छोटे-बड़े सरकारी और निजी अस्पताल मौजूद हैं। सरकारी अस्पतालों में निश्चित ही मध्यम व निम्न आय वर्ग के लोग इलाज के लिए जाते हैं। अधिसंख्य आबादी इस वर्ग की होने के कारण सरकारी अस्पतालों में भीड़ होना स्वाभाविक है। शासकीय अस्पतालों में इलाज तो होता है किंतु सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है तथा इलाज में देरी भी होती है। जिसके कारण मर्ज और कष्ट बढ़ता चला जाता है और फिर इनमें से कुछ मरीज जो थोड़े सक्षम होते हैं। हिम्मत जुटाकर निजी अस्पतालों की शरण में चले जाते हैं। शासकीय अस्पतालों में लोग आर्थिक तंगी के कारण मजबूरी में जाते हैं। सरकार से अपेक्षा यही है कि कम से कम आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी स्वाभिमान के साथ पूरा उपचार तो मिले। बीमा के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता आई है और आर्थिक रूप से सक्षम लोग मेडिकलेम जैसी पॉलिसी ले रहे हैं। लेकिन इसे भी वही लोग अपना रहे हैं जो पॉलिसी का भारी प्रीमियम देने की हैसियत रखते हैं। इस कारण से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग ऐसे बीमा के प्रति जागरूकता होने के बावजूद पॉलिसी नहीं ले पाते हैं। केन्द्र के शासकीय कर्मचारियों के लिए सी.जी.एच.एस. जैसी स्वास्थ्य योजना चल रही है जिसमें वे अल्प राशि का भुगतान कर सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा लाभ उठा पाते हैं। किंतु राज्यों के कर्मचारियों और आमजनों के लिए देश में ऐसी कोई योजना सरकार की ओर से नहीं बनी है। बीमा के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं और इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई जाए जिसका लाभ स्वाभिमान से देश का हर नागरिक उठा सके। इससे राज्यों में स्थित शासकीय अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी, लोगों के पास निजी अस्पतालों का विकल्प भी होगा और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार भी मिल सकेगा।

(xi) Need to make provision for setting up of godowns for storage of foodgrains on platforms of railway stations across the country

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Owing to an increase in the central pool, stock generated increased under the UPA Government from 196.38 lakh metric tonnes (April 2008) to 823.17 lakh metric tonnes (June 2012). There is an urgent need to increase storage facilities across the country.

I would like to draw the kind attention of the Government towards the loss of foodgrains due to inadequate storage facilities and inefficient movement of foodgrains from surplus regions to deficit regions which is a matter of grave concern.

I propose a Public-Public Partnership model between the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and the Ministry of Railways.

There are more than 7000 Railway stations in the country. One of the platforms of some railway stations which are not on the main line and which have fewer train stoppages can be used as storage spaces. The foodgrains will be safe on the already raised plinth of the railway stations. Wherever required, sheds can be constructed on them.

The proposal will cater to the issues of proper storage of grains across every part of India and their timely efficient movement due to the proximity to railway network.

Besides securing our foodgrains, this proposal will bring down the extra cost incurred by the Government on logistics and higher rent given for hiring private godowns.

(xii) Need to review the decision to close down medical colleges run by Employees' State Insurance Corporation in Tamil Nadu

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): The proposed move of Employees' State Insurance Corporation (ESIC) to withdraw from the medical college projects undertaken by it covers two such projects at Chennai and Coimbatore in Tamil Nadu. Of the ESIC's two Medical College projects in Tamil Nadu, the project in Chennai at K.K. Nagar is a functioning Medical College since 2013-14, with an undergraduate intake of 100 each year and also has 38 postgraduate students on rolls during the current academic year (2014-15). The other project is a proposed Medical College at Coimbatore under construction which is yet to get MCI approval. The sudden and drastic decision of ESIC not to further admit students and to exit from medical education has come as a rude shock to the students studying in the college. This has fuelled anxiety and agitation amongst the students studying in them. With a view to resolving the uncertainty and ensuring that they are not abandoned midway and to allay the fear amongst the students, I request the Ministers concerned to intervene in the matter.

(xiii) Need to sponsor a resolution in United Nations condemning the genocide of Tamils committed in Sri Lanka

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): In the final stages of the civil war in Sri Lanka, there was ethnic pogrom and genocide was perpetrated on Tamil minority in Sri Lanka.

Former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi thalavi amma had requested that the Government of India should sponsor a resolution in the United Nations condemning the genocide that took place in Sri Lanka and take stringent action against all those responsible for the genocide in order to render justice to the Tamils in Sri Lanka. The resolution should also provide for holding a referendum amongst Tamils in Sri Lanka and the displaced Sri Lankan Tamils across the world for formation of a separate Tamil Eelam. Further, voluntary repatriation of Sri Lankan Tamil refugees is premature and should be deferred for the present as conditions in the Northern and Eastern provinces of Sri Lanka are still not conducive for the Tamil refugees to return to their native land. The process of voluntary repatriation could be considered only after concrete and credible measures are taken by the Sri Lankan government and the Sri Lankan refugees in Tamil Nadu are given adequate verifiable assurances and have gained the requisite confidence to return to their native land.

**(xiv) Need to take stern action against persons involved
in trafficking of children**

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): In spite of all around development, we still come across incidents of trafficking of children. Many cases of child trafficking do not get reported. We have laws like Immoral Traffic Prevention Act, 1956 which deals with trafficking of children and Government is making efforts through Anti trafficking modal cell under the Ministry of Home Affairs but the situation has not improved and such cases continue to happen. Recently suspected trafficking of 578 children came to the notice from West Bengal, Jharkhand, Bihar on 25th May 2014. 123 children of West Bengal were found in a Railway Station in Kerala without any valid document. Children easily fall prey to the wrong persons working in orphanages or Juvenile Homes. Strict vigilance should be kept at bus stands, railway stations, national highways, orphanages, Juvenile Homes, Charitable institutes. Children rescued should be sent to proper and safe places and rehabilitated. Those indulging in child trafficking should be severely punished. I strongly urge the Government to strive to check child trafficking in the country.

(xv) Need to introduce a new Rajdhani Express train between Bhagalpur (Bihar) and New Delhi or provide the stoppage of Howrah-New Delhi Rajdhani Express at Bhagalpur railway station

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर बिहार राज्य की राजधानी पटना के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहां पर देश के कई हिस्सों से सिल्क व्यापार के लिए लोगों का आना-जाना लगा रहता है। भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से भी मशहूर है। पर्यटन के लिए भी यहां लोग आते हैं। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी दूसरी शहर भागलपुर में राजधानी एक्सप्रेस की यात्रा सुविधा नहीं है। जिससे यहां आने-जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है। भागलपुर से दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की मांग स्थानीय जनता द्वारा काफी अरसे से किया जा रहा है। रेल बजट 2015-16 में भी भागलपुर से होकर कोई राजधानी एक्सप्रेस की घोषणा नहीं हो सकी है। जिससे स्थानीय नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि बिहार की सबसे बड़ी दूसरी शहर सिल्क नगरी भागलपुर से नई राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ कराया जाए अथवा हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को भागलपुर में ठहराव देते हुए बरास्ता भागलपुर से चलायी जाए तो भागलपुर से राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा मिल जाने के पश्चात् भागलपुर की आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा।

(xvi) Need to permit construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and other State roads stalled due to provisions of Forest Conservation, Act 1980 in Idukki Parliamentary Constituency, Kerala

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The forest department has been obstructing the road work under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) citing the provisions of the Forest Conservation Act 1980 which came into force on 25-10-1980. The department is stalling maintenance work of roads which were in existence prior to this act coming into being even for National Highways, road Maintained by Public Work Department, Gramin roads leading to Tribal settlements etc. Since the forest conservation act does not have retrospective effect as regards the maintenance and improvement of infrastructure including roads, the act of the forest department is arbitrary, unlawful and deny the right of the People guaranteed under the Part 3 of the Constitution. In this regard, the Ministry of Environment & Forests had issued guidelines No. F. No. 5-3/2007-FC on 07-01-2011 making it clear that even the forest roads constructed before 25-08-1980 can be converted into pucca roads without attracting the provisions of the act. Even then the construction of seven PMGSY roads, 32 roads maintained by state PWD and maintenance of the National Highways are being obstructed by the Kerala Forest department in my Idukki Parliamentary constituency. Hence, I urge upon the Government to intervene in this matter for facilitating the development of infrastructure in rural and backward areas.

14.34 hrs

**WAREHOUSING CORPORATIONS
(AMENDMENT) BILL, 2015**

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will take up discussion on the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015.

Shri Ram Vilas Paswan.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

“कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक टेक्नीकल है। सी.डब्ल्यू.सी. है, वह वर्ष 1957 में बना था और वर्ष 1999 में इसे मिनी रत्न सूची-1 का दर्जा दिया गया था। जो इस कानून की धारा 5 है, इसमें सरकारी गारंटी लेने का प्रावधान है। जो पी.एस.यू. मिनी रत्न हो जाती है, उसमें सरकारी गारंटी खत्म हो जाती है और उसको वित्तीय अधिकार स्वयं मिल जाता है, सरकार की गारंटी का अधिकार खत्म हो जाता है। लोक उद्यम विभाग ने कहा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, जिससे इनको वित्तीय अधिकार मिल जाएं। इसको लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस समय यूपीए की सरकार में यह प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाया गया और कैबिनेट ने 2 जून, 2011 को इसको अनुमोदित कर दिया था। इसके बाद 28.12.2011 को इसी लोक सभा में इसे पेश किया गया था। लोक सभा ने इसे स्थायी समिति में भेज दिया था। स्थायी समिति ने भी इस संशोधन का समर्थन करते हुए 30 अगस्त, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 15वीं लोक सभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो सका। 15वीं लोक सभा में जो विधेयक आया था, जो पास नहीं हो सका था, उसी को लेकर हम आए हैं और यदि यह बिल पास हो जाता है तो जो बजटीय सहायता और गारन्टी देने के लिए जो केन्द्र सरकार के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, वह ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगा। इनको अपना वित्तीय अधिकार, 500 करोड़ रूपए तक का पूँजी व्यय, बिना सरकार की अनुमति से करने का इनको अधिकार मिल जाएगा और ज्वाइंट वेंचर का भी अधिकार मिल जाएगा।

वर्ष 1967-68 से ही यह मुनाफे में चल रहा है, इसलिए अभी तक वह गारन्टी देने की नौबत नहीं आई है। इसलिए मैंने 5(1) में संशोधन की बात रखी है और जब 5(1) में संशोधन हो जाता है तो इसके अलावा जो धारा 27(4) है, 30(2) है, 31(8) है, और 39 है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

इसलिए उसमें भी संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह बस इतना ही है। इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, बस टेक्निकल मामला है। पूर्ववर्ती सरकार जिसे लाई थी, उसको हम ला रहे हैं और उम्मीद है कि सदन बिना चर्चा के ही इसे पास कर देगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, be taken into consideration.”

Prof. K.V. Thomas to speak

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Of course, the Minister has moved this Bill, and Prof. K.V. Thomas has to speak. मेरा एक संशय इसमें है। यह ठीक है कि पिछली गवर्नमेंट इसे लाई थी और आप भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक और बात है, लेकिन मुझे इस बात का संशय है कि अगर गवर्नमेंट गारंटी निकल गयी तो शेयर होल्डर्स के लिए कल के दिन, यानी इस कारपोरेशन में जो आस्था रखते हैं या सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में जो एग्रीकल्चरिस्ट अपना माल रखते हैं और दूसरे जो भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टोक होल्डर्स हैं, उनका विश्वास इस पर से उठ जाएगा। अगर गवर्नमेंट गारंटी ही नहीं है तो हम उसमें क्यों रखें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता यह प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जब आहिस्ता-आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो इस वक्त नो लॉस, नो प्रॉफिट बोलिए या थोड़ा प्रॉफिट वर्ष 1958 के बाद जो कर रहे हैं, अगर वह खत्म हुआ तो उसके बाद आम जनता को खासकर किसानों को तकलीफ होगी। उसके लिए आपको सोचना होगा, यह एक बात है।

दूसरा प्वाइंट यह है कि आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से गारंटी निकल जाएगी। वे कल बोलेंगे कि पी.पी.पी. मोड में होगा, ज्वाइंट बेन्चर में होगा या प्राइवेट आदमी उसको कैपचर कर लेंगे, तब इसमें से रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। नेचुरली जो आदमी उन्हें ज्यादा खरीदते हैं, वे अपना शेयर होल्डिंग वहां रख देते हैं, तो उनकी वॉइस चलती है। उन्हें इस दिशा में भी सोचना चाहिए।

यह ठीक है कि पिछली गवर्नमेन्ट इसे यहां लेकर आयी थी, और आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, यह बात और है। मेरा संशय यह है कि इसमें अगर बाहर से आये हुए शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी बन गयी और दूसरी चीज यह है कि गवर्नमेन्ट की जो एसेट है, अगर आज आप उसे दूसरों को देंगे तो कल किसानों को तकलीफ होगी। इसे ध्यान में रख कर, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए?

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, I rise to support the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015 further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, which has not been taken for discussion in this House.

This Bill is the child of the UPA-II Government and to be precise, this Bill was authored when I was the Food Minister in the UPA-II Government. Some apprehensions, which Shri Kharge raised here, had been discussed in detail. After finding out ways and means to address those apprehensions, this Bill was brought. Then, it also went to the Standing Committee.

We never believe in opposing a Bill for the sake of opposition unless the very solemn substance of our Bill is clandestinely removed. Now, the purpose of the Bill is to allow withdrawal of the Government guarantee extended to the Central Warehousing Corporation. In the process, the Government will be absolved of its responsibility of being the guarantor. The dispensation of the guarantee is overdue.

I know the good performance of the Central Warehousing Corporation from very close quarters. The performance of the Corporation has been quite spectacular. The owned and constructed capacity of the warehousing has increased from 67.60 lakh tonnes in 2008-09, the beginning of the UPA-II Government, to 75.81 lakh tonnes in 2013-14, the end of the UPA-II Government. There has been substantial enhancement in the storage capacity during this period. The turnover of the organisation rose from Rs. 849.25 crore in 2008-09 to Rs. 1,528.19 crore in 2013-14. It means that there has been a nearly 100 per cent increase. Profit before tax has shown an increase from Rs. 110.44 crore in 2008-09 to Rs. 256.47 crore in 2013-14. Profit after tax has increased from Rs. 110.46 crore in 2008-09 to Rs. 161.05 crore in 2013-14. The dividend given by the Corporation rose from 30 per cent in 2008-09 to 48 per cent in 2013-14. I congratulate the Chief Executives and officers of the CWC for this commendable achievement.

Nevertheless, I would like to emphasise a few points which deserve to be followed by the new Government. It is necessary to upgrade the existing bulk handling infrastructure through enabling Government policies, focusing on mechanical harvesting, construction of a series of silos at procurement and distribution centres and transportation of grains from silos to rail heads and to destinations through specially designed tracks and railway wagons.

My request to my hon. colleague is that we have started a large number of modernization processes, like computerization and *in camera* operations. As a result, damage in FCI alone, which was to the tune of 2.5 per cent in 2008-09, has come down to 0.01 per cent. So this modernisation process has to continue.

Sir, we have got a big challenge. The magnitude of the problem can be gauged from the following indicators. Food grains production this year is to the tune of 264.7 million tonnes. It was a record production that we had. But the post-harvest losses in wheat were eight per cent of the production, and 11 per cent of production in the case of rice. We have to bring down these losses at the time of harvest as also after harvest.

At present the storage capacity available is 108 million metric tonnes, and the storage capacity to be created for FCI and PDS requirements is 150 lakh metric tonnes. The existing gap for meeting private commercial demand is 200 lakh metric tonnes. So the total warehousing gap is to the tune of 350 lakh tonnes. So we need more godowns, more warehouses and better technologies. In this direction private sector can play a major role to build and manage the storage capacity in the country. This is particularly so in respect of incorporated bulk handling storage and transportation. There is also a need to fund these operations through public issues by private enterprises, soft loan guarantees like NABARD and commercial borrowings.

In this connection I would like to give a signal to the Government that in this process of expansion and modernisation, it should not go into the private hands and corporate houses. You can try the cooperative movement in the country

like in Andhra and in Odisha where a large number of cooperative societies have come in for constructing these storages.

Our ports need to be strengthened with the involvement of private sector. There are very little warehousing facilities for storage of food grains at the ports. Non-traditional ports also should be equipped to handle the increasing need of food grains traffic. This involvement of private sector in strengthening the storage infrastructure should be made an integral part of Make in India Initiative of the Government.

In large parts of rural areas manual harvesting and thrashing is in force. Grains in small quantities are collected, bagged and taken to the storage point. Bagging, loading and unloading process pushes up the cost of operations. Where the mechanical harvesting is done, grain in bulk is collected and this lends itself to bulk movement to the silos and to the distribution point.

The one successful model of bulk handling of food grains is the model evolved by the Food Corporation of India and the Adani Agri Logistics Limited together. This is in Punjab. It is a very successful project which we have initiated and it has become very successful.

Earlier we were following the American models but we have now developed our own models. No doubt there were teething troubles initially and the subsequent issues hampered its progress. However, in 2013 these irritants were sorted out and now it is operating successfully.

Under this model specially designed rakes or dedicated trains are put in place which constitute basically a modern wagon loading system which allows the wagons to be filled at the rate of 700 tonnes per hour, taking only 2.5 minutes to fill one wagon. This would also provide ultra modern storage and transportation facilities to the Food Corporation of India. The cost of this project is only Rs.600 crore. The purpose of the project is to prevent wastage of food grains and to preserve the inherent nutritional content in the process of modernisation.

Another example which I remember of PPP in bulk handling is the L.T. Overseas model. They operate in partnership with the Government of Punjab. They have set up a silo in Amritsar. Grain is brought in bags, unpacked and stored in the silo, and taken for bulk processing and distribution.

Sir, this House passed the Warehousing Development (Regulatory) Authority Act. This requires the warehouses to be registered under this Authority and when farmers store their agricultural products in these registered warehouses, they get electronic receipt. With this electronic receipt, they can get financial assistance from the banks, even cooperative banks at a very small interest rate. This saves the farmers from distress sale of their products. This is one of the areas where we have to give stress so that farmers do not go in for the distress sale when production is high. For example, this year the sugar production has been high and the price has fallen to Rs 25 per kilogram in the market and huge arrears are to be given to the farmers. This is the time when we can make use of registered warehouses.

With these words, I request my hon. colleague to move forward into developmental activities. Irrespective of political conservations we have, we will support the Government when we have taken a path; a path of progress and development to modern technology.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, में इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने विधेयक के मूल उद्देश्य के बारे में बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। यह अलग बात है कि प्रतिपक्ष के साथी श्री खड़गे जी ने और श्री थॉमस जी ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं। जबकि इस विधेयक का मूल स्वरूप वही है जो 2012 में यूपीए-2 के समय आया था, इसमें नया कुछ भी नहीं है। उस समय उनको आशंकाएं नहीं थीं कि यह निजी क्षेत्र में चला जाएगा, अगर इससे सरकारी गारंटी दूर हो गई तो आज जब नई सरकार ने संशोधन बिल प्रस्तुत किया है तब उनको आशंका दिखाई दे रही है। मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार देश हित में उन सभी तरह के निर्णय के लिए काम कर रही है, चाहे वह यूपीए सरकार के समय के मामले हों, चाहे आज की जरूरत के अनुसार हो। निश्चित तौर पर यह निगम पूरी तरह से लाभ पर काम कर रहा है तो यह स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार की जो गारंटी थी उससे उसे मुक्त किया जाना चाहिए। जिस तरह से निगम को मिनी रत्ना कंपनी को दर्जा मिला है, उसके भी कुछ मापदंड हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने जो मापदंड बनाए हैं उसके आधार पर सरकारी गारंटी है उसे हटाना ही होगा। इसी बात के लिए यह संशोधन लाया गया है।

यह विधेयक 1962 के विधेयक में संशोधन कर रहा है, इसमें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि उपज या अन्य वस्तुओं के भंडारण के प्रयोजन के लिए है। आज मंत्री जी ने कहा है कि धारा 5 जिसमें केन्द्र सरकार की गारंटी से उनको अलग करने का अधिकार देगी। इसी तरह से इसके उप-धाराएं हैं 27, 30, 31 और 39 इसमें जो संशोधन होगा, इससे इस निगम को पूरे अधिकार मिलेंगे। धारा 5 की उप- धारा 1 में निर्दिष्ट प्रत्याभूति वापस ली जाएगी और केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से धारा 27 में भंडारण निगम को उधार लेने का अधिकार मिलेगा। धारा 30 में लाभों का अधिकार मिलेगा। धारा 31 में भंडारण निगम को लेखा और लेखा परीक्षा का अधिकार सौंपा जाएगा। धारा 39 में आय कर से संबंधित मामलों में स्वायत्ता मिलेगी। यह बात बिल्कुल सही है कि आज देश में भंडारगृहों की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि अनाज खरीदने के बाद खुले में पड़ा सड़ता रहता है। अगर हम पिछले दिनों के उदाहरण देखें, तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि हमारे उत्पादन के अनुसार भंडारण की उतनी क्षमता नहीं है।

अभी श्री थॉमस साहब कह रहे थे कि इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हमारा कहना है कि निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत तो है, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी जरूरत हमें गांवों में है। आज गांव में अनाज का उत्पादन हो रहा है, जिसकी सरकार खरीद भी कर रही है, लेकिन उसे खुले में रखती है।

हमारा लाखों टन अनाज, सब्जियां और फल खराब हो रहे हैं। शीत भंडारण न होने के कारण आज वे फसलें खराब हो रही हैं। इस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे भी प्राकृतिक आपदाओं ने किसान को बहुत कमजोर बना दिया है। आये दिन फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं।

अभी पिछले दिनों भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण खड़ी गेहूं और चने की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी। हमारे मध्य प्रदेश के 30 जिलों में, लगभग सवा तीन हजार गांवों में बिल्कुल पकी हुई फसल नष्ट हो गयी। किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में हमारी सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत उसके भंडारण की है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आंकड़ों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहां 6488 शीत भंडार हैं, जिनकी क्षमता 40 लाख टन है। हमारे देश का उत्पादन 10.4 करोड़ टन के आस पास है, जबकि भंडारण की क्षमता 3.84 फीसदी है। इस अंसतुलन को कैसे पूरा किया जाये, कैसे हम उन्हें पूरी तरह से भंडारण की सुविधा दे सकें, यह हमें सोचना होगा। जब किसान का अनाज आता है तब बाजार में उसका भाव कम होता है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसके तहत कोई सोसायटी या कोआपरेटिव संस्था बने, जिससे हमें अपनी आवश्यकतानुसार कुछ पैसा लोन के तौर पर मिल जाये और जैसे ही बाजार का भाव ठीक हो जाये, वैसे ही हमारा अनाज या सब्जी-फल बिक जाये। मैं समझता हूं कि इससे किसान को लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था भी आने वाले समय में बनाने की जरूरत है।

हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को ऑफर दिया है कि निजी क्षेत्र में अगर वह अपने गांव में गोदाम बनाना चाहते हैं तो हम इन-इन शर्तों पर उन्हें अनुमति देने के लिए तैयार हैं। उसका इतना लाभ हुआ कि आज गांव-गांव में गोदाम बनना शुरू हो गया। हमें लगता है कि पूरे देश में ऐसी योजना बनानी चाहिए। लेकिन जो किसान अपनी जमीन पर भंडारण के लिए गोदाम बनाता है, उसे कहीं न कहीं सरकार के साथ अनुबंधित करना चाहिए। अगर हम उसके साथ अनुबंध करेंगे, तो बैंक उसे लोन देगा। लेकिन अनुबंध न होने के कारण बैंक लोन नहीं दे पा रहा।

पिछले दिनों जो स्थिति सामने आयी है, उस बारे में मेरा सीधा-सीधा यही कहना है कि सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार करे। चूंकि हमारी सरकार चाहती है कि किसान का जो खेती का धंधा है, वह फायदे का बने। खेती का धंधा तभी फायदे में हो सकता है, जब एक ओर लागत खर्च घटे और दूसरी तरफ भंडारण की व्यवस्था हो, ताकि बाजार के अनुसार उन्हें अपनी चीजों का दाम मिल सके। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फसल की पूरी तरह से सुरक्षा हो जाये। इस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है।

जब हम भंडारगृहों के बारे में चर्चा करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका सीधा संबंध किसानों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। किसानों के उत्पादन की रक्षा और सुरक्षा की जवाबदारी आज देश के लिए बहुत आवश्यक है। फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सबको खाद्यान्न की सुरक्षा का अधिकार मिला।

15.00 hrs

मध्य प्रदेश में जितना भी गेहूं और धान पैदा हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने 100 प्रतिशत खरीद की। हमारी सरकार 100 प्रतिशत खरीद भी करती थी और बोनस भी देती थी, लेकिन जब से खाद्य सुरक्षा विधेयक आया है उस पर कहीं न कहीं रोक लग गई, उसे पुनः चालू किया जाए। हमारे राज्य को जितनी आवश्यकता है, जितना फूड सिक्योरिटी के लिए अनाज चाहिए, उतना खरीद सकता है, लेकिन राज्य सरकार अगर बाकी का खरीदना चाहती है तो वह कहां रखेगी? इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ है तो उसकी खरीद की जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। यह किसानों के लिए बहुत जरूरी है।

महोदय, माननीय मंत्री जी बड़े अनुभवी हैं। बहुत समय से कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। उन्हें मालूम है कि देश के किसानों की क्या जरूरत है। गांव और किसान को मजबूत करके विभाग को कैसे आगे ले जाना है। वेयरहाउस को कैसे मजबूत करना है। इसके साथ कई विषय जुड़े हुए हैं। एफसीआई के जहां केंद्र हैं, वह उन्हीं के पास खरीद कर रही है। एफसीआई के केंद्र निर्धारित हैं कि यहीं खरीद करेंगे, मध्य प्रदेश में इतने लाख टन करेंगे, अन्य राज्यों में इतने लाख टन खरीद करेंगे। मेरा प्रश्न है कि बाकी की खरीद कौन करेगा? मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए ताकि किसान की फसल के उत्पादन की पूरी खरीद सरकार के माध्यम से हो सके और दाम बढ़ सके। यह विधेयक देश के लिए बहुत जरूरी है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसे बिना बहस पारित करने की जरूरत है। इसमें टैक्नीकल संशोधन है। कांग्रेस के मित्रों ने इस बिल का समर्थन किया है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं बाकी वक्ताओं से भी कहूंगा कि इस बिल को सहमति के साथ पारित कराएं। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for enabling me to be a participant in this debate on the Warehousing Corporations (Amendment) Bill.

I thank our beloved leader, Puratchi Thalaivi, Amma, who has compassion for the poor and cautious care for the protection of public sector undertakings that help save our economy. Let me marshal my thoughts following the footsteps of our beloved leader. This Warehousing Corporations (Amendment) Bill, which seeks to bring about certain amendments to the original Warehousing Corporations Act of 1962, makes me to think and blink for a while.

I think. Yes, I begin to think. It is because a profit-making corporation, that is the Central Warehousing Corporation that has been paying dividend to the Government of India since 1957-58, is being taken out of the protective arms of the Government.

CWC's activities spread all over the country form the backbone of our public distribution system. CWC is also a mini-ratna public sector enterprise. Apart from being profit earning company, it does not depend on any financial support or contingent liability on the part of the Government. Right from 2003, the net worth of the Corporation has been positive. But, still the Government prefers now to withdraw and absolve itself of its responsibility of being its guarantor. So, I blink.

We can presume that the Government in the near future may shed its shares of this profit-making Corporation. The Government appears to be distancing itself from its responsibility of proving its *de facto* ownership over this Corporation as a guarantor.

I do not know why this Government is moving away from the Central Warehousing Corporation which is deemed to have been included among the securities enumerated in Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 and is also expected to be approved securities for the purpose of the Insurance Act, 1938 and

the banking Companies Act, 1949. The founding of this Corporation with the incorporation of so many Acts enacted in the previous era only shows the great concern of the founding fathers to have a solid foundation for this Corporation to benefit the food security policy and the poorer sections of the society especially during food scarcity situations.

While withdrawing from its role of being a guarantor, I do not know why this Government is withdrawing the exemptions given to this Corporation under the Income Tax Act of 1961.

Hereafter the Warehousing Corporation shall be liable to income tax and super tax accordingly on its income, profits and gains. When the dividends from this corporation were constantly and annually paid to the Government, why this Government seeks to tax this company's income, profits and gains? I fail to understand that. I do not know whether I am right in bringing into my mind the age old tale of the golden goose now and I would like to impress upon the Government to go slow in abdicating its responsibility towards this organisation.

With these words, I conclude.

Thank you.

DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT): Hon. Deputy-Speaker, Sir, a premier Warehousing Agency in India established in 1957 providing logistics support to the agriculture sector is one of the biggest public warehouse operators in the country offering logistics services to a diverse group of clients.

CWC is operating 464 warehouses across the country with a storage capacity of 10.8 million tonnes providing warehousing services for a wide range of products ranging from agricultural produce to sophisticated industrial products.

A few amendments were introduced in the House for passing. The Corporation is a Schedule A, Mini-Ratna Category – I Public Sector Undertaking with effect from 23 September, 2009. Based on that, the guarantee would be withdrawn as the Central Government dissociates itself from the responsibility of being a guarantor. I am unable to understand why the Government keeps away from a profit making body? What is the intention behind it? It is a fact that Mini-Ratna awardee Public Sector enterprises do not get financial support or Government guarantees as per the provisions. I think that by passing this amendment, the beneficiaries may feel insecure. It is an unwise decision when the Government is running with debts. The corporation has been consistently making profits and paying dividends to its shareholders. CWC paid dividend at the rate of 41 per cent of the equity for the year 2012-13.

According to the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the Government has also not given any guarantee besides the payment of minimum guaranteed dividend as required under some provisions of the Act.

The storage capacity utilisation of CWC was 86 per cent in 2013-14 and that should be improved in future. Sufficient warehousing facilities need to be extended for agricultural produce. Around 20-30 per cent of the total food grain harvest is wasted due to inadequate facilities. Only 29 per cent of the space accounts for agro warehousing. India needs to recalibrate its strategy to mitigate the challenges of high food grain wastage due to lack of scientifically sound storage facilities in the country and high inflation due to lack of cold chain

infrastructure like cold storage, refrigerated transport as it leads to wastage of fruits and vegetables.

The Central Railside Warehouse Company, under CWC, decided to construct Railside warehouses worth Rs. 15 crore each in the States of Gujarat, Maharashtra, Bihar, Assam and Karnataka. There was the same proposal for Malda in West Bengal during the last financial year, but that has been refused by the Railways. I would like to request the Government to rethink on the project because of its vital geographical advantage for the whole country.

Sir, with these words I conclude my speech with the expectation that the Government will look into it seriously.

Thank you.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस संशोधन बिल पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, यह इस कानून को बदलने का जो तर्क दिया गया है, वह यह है कि जब से यह कॉर्पोरेशन बना है, तब से यह फायदे में है और वर्ष 2003 से यह कॉर्पोरेशन पॉजीटिव साइड में है। मेरे ख्याल से यह तर्क यथेष्ट नहीं है, जिसके लिए कानून को बदला जा रहा है। अगर कॉर्पोरेशन सही से काम कर रहा है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी से हटना क्यों चाहती है? अगर कम्पनी कोई लोन नहीं ले रही है तो अच्छी बात है। सरकार को गारंटी देने में क्या समस्या है? आज के दिन 10.8 मिलियन टन की इनकी स्टोरेज कॅपेसिटी है। ऐसोचेम की स्टडी के अनुसार 33 मिलियन स्टोरेज कॅपेसिटी की जरूरत है। केवल कॉर्पोरेशन के ऊपर छोड़ देने से यह कॅपेसिटी नहीं बन सकती है। इसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन तभी आएगा, जब उनको यह भरोसा हो पाएगा कि वह जो पैसा लगाएंगे, उसका उनको रिटर्न मिलेगा। यह तभी सम्भव है, जब सरकार उसकी गारंटर रहेगी। इसको सिर्फ कॉर्पोरेशन के ऊपर छोड़ देंगे तो मुझे संदेह है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन में वेयर हाउसिंग बनाने के लिए कम्पनीज़ आएंगे।

महोदय, आज के दिन स्टोरेज कॅपेसिटी और विशेषकर कोल्ड स्टोरेज कॅपेसिटी की शोर्टेज की वजह से सालाना 13 हजार करोड़ रुपये का फल और सब्जियों का वेस्टेज हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज ही नहीं, अपितु कोल्ड स्टोरेज रिलेटिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। इसके साथ-साथ अन्य फूड ग्रेन का वेस्टेज मिल लें तो यह कुल मिला कर 45 हजार करोड़ रुपये का वेस्टेज हो रहा है। इस वेस्टेज को कम करने के लिए अच्छे स्टोरेज और निगरानी की आवश्यकता है, जिसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है।

महोदय, आज के दिन स्टोरेज केवल चावल का ही होता है, धान को वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में लेने का कोई प्रावधान नहीं है। आसमान के नीचे धान खरीदा जाता है और कोई अनसीजनल बारिश हो जाती है तो वह धान अंकुरित हो जाता है, जिसके कारण ही यह 45 हजार करोड़ रुपये का वेस्टेज होता है। इसलिए वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में केवल चावल को ही नहीं, अपितु धान को भी स्टोरेज के अंतर्गत लाया जाए। अगर पक्का वेयरहाउस न हो तो कम से कम एक टीनशेड के नीचे खरीदा जाए, खुले आसमान के नीचे न खरीदा जाए। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां तक ओडिशा का सवाल है, ओडिशा पहले राइस डेफीसिट स्टेट था, लेकिन आज यह राइस एक्ससेस स्टेट हो गया है। यहां चावल और धान की खूब उपज हो रही है। इसलिए वहां बहुत ज्यादा वेयरहाउसिंग कॅपेसिटी क्रिएट करने की जरूरत है। इसमें

आनंदपुर में 10 हजार टन का वेयर हाउस बनाना है, बालेश्वर में 10500 मीट्रिक टन केपेसिटी का बनाना है, कटरा में पांच हजार टन का बनाना है एवं उजगपुर में पांच हजार टन की केपेसिटी का बनाना है। लेकिन इनके काम में पिछले चार-पांच साल से कोई प्रगति नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अनाज खुले में पड़ा है, पानी में भीग रहा है और सड़ रहा है। ओडिशा में वेयरहाउसिंग मैनटेनन्स के लिए एग्जिक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे यहां के वेयरहाउस की अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है। इसकी वजह से हुदहुद आने के समय में बालेश्वर में ढाई सौ मीट्रिक टन अनाज नष्ट हो गया। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ओडिशा में जो एग्जिक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट थी, उसको पुनः स्थापित किया जाए ताकि ओडिशा में जितने भी वेयरहाउसिज़ हैं, उनकी अच्छे से देखभाल हो। इतना कह कर ही मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Deputy-Speaker Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Warehousing Corporation (Amendment) Bill, 2015.

Prior to my political life, I was serving as a Government servant. I worked in Andhra Pradesh State Warehousing Corporation for a long period upto 2004. My colleagues are still in service. I have been maintaining cordial relations till today with the Corporation. As an ex-employee of the Corporation, I feel that it is my bounden duty to speak on this Bill. I totally support this Bill in letter and spirit. I congratulate Shri Ram Vilas Paswan ji, the hon. Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution for introducing this important Bill.

The Central Warehousing Corporation has been awarded mini ratna status. Mini ratnas do not get financial support nor the Government guarantees as per the provisions. This Corporation is a profit-earning body which has neither taken any loan from the Government nor was it dependent on the Government Budgetary support. The Government has also not given any guarantee besides the payment of minimum guaranteed dividend. This Bill seeks to withdraw the guarantee of the Government, absolving its responsibility of being the guarantor.

Warehouses' main aim is to strengthen rural credit and marketing. At the time of Green Revolution and food scarcity, Warehousing Corporations played a crucial role to bring the situation under control and also to avoid hoarding of foodgrains. Even today they play an important role in the implementation of Government schemes, like the Public Distribution System procurement, mid-day meals scheme, Integrated Child Development Scheme, and also to arrange storage facility to the farmers and also to small traders and bulk depositors. It also facilitates the depositors to obtain hassle free loan on their produce.

I have a few suggestions to make. Traditional warehousing has declined and recent retailing trends have led to the development of warehousing-style retail stores. The same building serves as both warehouse and retail store.

With the entry of MNCs in the Indian market, it is very much essential to make rapid changes in the Government warehousing system, both at the Central and at the State level. They should mould themselves with diversified activities according to the changing needs of the Indian market. Even though private players are allowed in this field, the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations have to be preferred in Government programmes. I would request the Government to give this kind of encouragement to the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations.

The Central Warehousing Corporation has been maintaining the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Trust since its inception. The Trust had earned interest on the investment of Funds and it has accumulated to the extent of Rs. 45 crore approximately upto 2013-14. There is a CAG observation that there should not be any variation between the interest earned on the PF and the interest paid to the workers. Hence, I would request you to distribute the said surplus proportionately to the employees.

The Department of Public Enterprise issued instructions to all profit making Central Public Sector Enterprises to create a Contingency Fund to meet the contingencies, such as medical facilities, etc. exclusively for the retired employees. I would request the hon. Minister to create a Contingency Fund immediately.

The Central Warehousing Corporation's dividend, in the name of Performance Related Pay, may be proportionately distributed to the workers also. Apart from officers of Group A and B, Group C and D category employees may also be considered for this PRP.

Thank you for giving me this opportunity.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Deputy-Speaker, thank you for this opportunity.

Behind any Bill or amendment, I am sure, there is vision, foresight, depth and understanding. I think behind this amendment also, the vision, might have been to provide every village sufficient warehousing facilities. I think we are very far away from that dream. If there is one thing we have gone backwards since Independence, it is our capacity to store food grains in our villages. In our younger days, when we used to play hide and seek in our villages, we could go and hide in each other's godowns. But now neither a small farmer has the storage facility nor a big farmer has the storage facility.

The private-farmer-owned warehousing has come down to zero as of now because of modern logistics of agriculture marketing. So, while that has come down to zero, the private sector and the Government Warehousing Corporations have not taken the place of what we used to have in our olden villages. So, Sir, the Warehousing Corporation is doing a good job. It is self-sufficient unlike so many State-owned Warehousing Corporations and, of course, the FCI. So, in fulfilling its objective, I think, will taking off the guarantee help it or will giving it additional guarantee help? That is really the question. My personal belief and our Party's belief is that withdrawing the guarantee will not help it fulfil its dream. So, I think, guarantee should be given and, if possible, additional guarantee should be given.

Sir, in its own objective, the 464 and odd warehouses that it has are mostly in Punjab, Haryana and North India. The benefit of this is not there in South India. So, the Government should encourage it and let its good work spread to the rest of the country so that there is equitable development all across the country.

Secondly, the Food Corporation of India is not doing well. Why does the Government not assist the Food Corporation of India to do well? Why does it not take part and take equity in various State-owned Warehousing Corporations like the Andhra Pradesh Warehousing Corporation, the Telangana Warehousing Corporation and the various State-owned Warehousing Corporations which need the help? If it is doing so well, why does it not help the other Warehousing Corporations which are doing exactly the same thing?

In our newly-formed State of Telangana, we have recognised this problem. The problem is not merely to do with just the storage of grain but also remove the middlemen. But, more importantly, especially rice is grown more in South India. As you age the rice, the value of the rice increases. Older rice is more expensive than newly-harvested rice. So, the warehousing facility actually increases the value the farmer gets out of the tonnage of rice that he produces. So, with all these benefits, I think, we should ask the Government to provide additional support and we are against the very concept of removing the guarantee.

With these words, I conclude. Thank you.

*SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): I am happy to be given an opportunity to participate in the discussion on this Bill. There are reasons to feel apprehensive about this Bill. This has been already mentioned by several other respected members. This proposed amendment bill was first proposed during the previous UPA Government's time when the Hon. Prof. K.V Thomas was the minister. This Government is now introducing this Bill, without bringing any change.

Whether it be the Central ware House or the State Ware House or the Food Corporation of India, it was to ensure the food security of the poor in our country that the existing law was promulgated. These bodies, whether it be the CWC, SWC or FCI use to function well, but if we examine the recent functioning of the FCI we can see that it has not been satisfactory.

As far as Kerala is concerned, we had to carry out protest marches on several occasions. Though the FCI was intended to protect our farmers, often grain have not been procured, by ensuring remunerative prices to the farmers. Or else, we had failed to store the food grains in hygienic conditions. We have also not been able to ensure that the millions of our people get good quality food grains through our Public Distribution System.

Often it is foodgrains of very poor quality that we could supply to our poor. Several of our godowns are in very pitiable and unhygienic conditions. They need renovation as these buildings are vry old.

You know how foodgrains are stored in our houses. They are stored in clear places and in air tight conditions. But the FCI and CWC godowns have not been well maintained.

Many godowns are affected by water seepage. Without addressing these pressing demands, when you are going to transfer the FCI godowns to the CWC; I am compelled to doubt your intention.

* English translation of the speech originally delivered in Malaylam.

Do you think it is going to benefit our farmers; or the poor? No. Even some Members from the Treasury Benches also expressed doubts, whether this bill will benefit the private monopolists.

These doubts have been confirmed by our move to amend Section V of the existing bill.

What is the rail intent to change the CWC and FCI godowns that were built with lofty ideas during the time of our first Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru? Why do you hide your real intentions?

It also shows that this Government is following the same privatization policy of the UPA Government. I repeat, you are going to encourage the private monopoly.

A situation will be created where the poor, the small and the marginal farmers are not going to get remunerative prices for their produce. The private companies can construct godowns anywhere they want and procure grains at any price they fix. If it happens, the farmers will be ones who will be most affected.

The 1962 Act, was envisaged to protect our farmers, and also strengthen our Public Distribution System. All those objectives will be done away with if the amendment is passed.

But I do not intend to fully oppose the proposed bill. The minister will have to clarify, how this bill is going to benefit the poor in the country. Or else, the farmers and millions of poor who are benefited by the PDS, will be badly affected by the privatization. Why is the Government shirking away from their responsibility? Whom is the Government committed to? It is to the poor of the country that the Government should be committed to.

Instead of that, you are enabling the monopoly of the multinationals and allowing them to interfere in the procurement and storage of foodgrains.

The PDS system will collapse, the farmers will have to take up begging bowls.

So all these apprehensions are shared by many Members in this House and several others in our society. The people need to know what the real intent of the bill is. Or else, the bill will be a mere lip service. Once again, I thank the Deputy Speaker for allowing me to participate in this discussion.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on an important issue. Indirectly, the warehousing contributes both, food security and it also checks and controls the inflationary trends in the country. *Per se*, we welcome the Bill. There is not much of content in the sense that as far as I know, for any Government undertaking, the Government is the last resort. Therefore, by removing certain facilities like the income tax concessions and the Government absolving itself from giving guarantee for bonds, shares and debentures and not assuring guarantee on minimum dividend, it may not have much effect on the organisation. On the other hand, as the earlier speaker said, it might affect the organisation and it might lose its Mini Ratna status soon.

The very objective of the Warehousing Act is to meet the needs of agriculture, trade and industry and to do it in a scientific manner. But, unfortunately, we are mostly focusing on agriculture and neglecting trade and industry in the process. Over the years, the average capacity utilization of warehousing in India is coming down, maybe because of its inefficiency. We have now an efficient and a senior hon. Minister. We hope that he will definitely remove the inefficiency in the system.

We all know that warehouses in India have been very unevenly distributed. They are concentrated in certain areas and totally absent in certain other areas. Therefore, the Government may take necessary steps to ensure that the warehouses which are likely to be constructed should be built up in such areas, particularly in the South, where we have a lot of paddy to be stored. The new warehouses likely to come may be allotted to Andhra Pradesh.

Mostly we have warehouses in cities and in towns. In *tehsils* and at consumer level, warehousing is totally absent. Unless we do that, common man will not be benefited. Therefore, I am of the view that construction of warehouses should also go down to *tehsil* level, to consumer level, that is the village level.

The hon. Minister himself has said on several occasions that the facilities available to the labours at the warehousing is very much inadequate. The resting place is not available in many places. Canteen facilities are not available. Toilet facilities are not available, and very often toilets are extremely unclean. So the Government may focus on this. Since it is making huge profit, it may be shared with the labour that is working day and night.

Secondly, our warehousing is not extremely competitive and it is also not doing the complete logistics. For example, other than storing, we hardly are doing anything else. Therefore what I suggest is, our Warehousing Corporation should also take up the processes like insurance and safety for food material. They should also ensure that whatever food is stored, people should also get bank loans. They should also handle the Customs clearance and the Duty payments etc. Then only, we can compare ourselves with the private logistics.

Our country is basically an agrarian economy. But unfortunately, the warehousing is in a position to cater only 25 to 30 per cent of the agricultural products. We should ensure that the more number of warehouses are constructed to cater to the needs of the agricultural products.

As far as the staff working in warehouses is concerned, they are not highly motivated. Since it is making profit, the performance linked incentive may be given to the employees to wipe out their inefficiencies.

Although we have been repeatedly telling that we have to provide the basic infrastructure to the North-East, as far as the warehousing is concerned, it is almost negligible in North-East. The Government should look into that aspect.

The State level committees, which have exclusively been formed to find out the need for more warehousing, have found out that in as many as 20 States the

warehousing facilities are extremely inadequate. Therefore, the Government should take steps to fill this shortage by providing more warehouses. One of the methods in this direction could be by providing the private entrepreneurs guarantee. That means, whoever private person is constructing the warehouse, the Government may take it on a long lease, not on a short lease as it is doing presently. If it could take it for 20 years or 30 years, the private people may come in a large way. So, the private entrepreneurs guarantee may be provided.

Presently, we are only storing paddy and other things. The processed food should also be stored. The cold storage facility may also be provided at places like Andhra Pradesh. It will greatly help in the long run.

In certain areas, the price of perishable items is very high for example fruits and vegetables. Today, we are wasting about 30 to 40 per cent perishable items. If this cold storage facility along with the warehousing is provided, that will mitigate the problems of small farmers.

Sir, the hon. Prime Minister, before the General Elections has promised that he will revamp the Food Corporation of India by creating three divisions that are the handling procurement, management and distribution. This will definitely benefit the FCI which is acting as a major warehousing provider. Therefore, I request the Government that whatever has been said before the elections could be done at the earliest.

About 30 per cent of foodgrains in India get wasted. Therefore, more modernised silos or warehouses could be constructed to reduce this wastage. I have read in the newspaper that India is wasting food annually worth Rs. 15,000 crore. If we have good warehousing facilities, that wastage could be reduced.

Therefore, keeping all these points in mind, the Government may consider constructing scientifically modernised silos in future as required by the various States.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महोदय, हमारे देश की 70 फीसदी आबादी में किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे माननीय मंत्री राम विलास पासवान जी ने देश के तमाम उत्पादन किए हुए अनाज को व्यवस्थित करने का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास किया है, उन्होंने यह सराहनीय कदम उठाया है। वास्तव में देश का किसान गेहूँ, धान देश को खिलाने के लिए पैदा करता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछली सरकारों की लापरवाही की वजह से हमारे देश का लाखों टन अनाज सड़ता रहा। मैं विशेष कर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगी। मैंने स्वयं देखा कि खुले में, सिर्फ पन्नी के नीचे लाखों बोरियाँ लगी हुई थी, उन्हें चूहे खा रहे थे। उनको बचाने के लिए दवा की व्यवस्था और पता नहीं कितनी तरह के आँकड़े पेश किए गए, लेकिन एक तरफ अनाज सड़ता रहा और दूसरी तरफ देश के तमाम लोग भूखे सोते रहे, पेट भरने के लिए तरसते रहे। यह एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम रहा, जो गाँव-गाँव में लघु रत्न के माध्यम से भंडारागार बनाए गए। इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर ही हमारे लोगों को सुविधा मिली।

मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह भी करूंगी कि जितना हो सके गाँव-गाँव तक जाकर भंडारागार बनाने की व्यवस्था करें, जिससे अनाज को ज्यादा दूर ले जाने की दिक्कत किसानों को न हो और वे नजदीक ही अनाज को भंडारागार में रख सकें। देश के वे तमाम बेसहारा किसान, जो दर-दर की ठोकरे खाते हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। वहाँ पर जो बड़े शीतकालीन भंडारागार फलों या सब्जियों के लिए होते हैं, उनमें उनको जगह नहीं मिलती है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि बड़े पैमाने पर हमारी सब्जियाँ, जो महंगाई का कारण बनती हैं, सीजनल सब्जियों और फलों की वजह से कभी-कभी यह आवाज आती है कि बहुत महंगाई है, आम जनजीवन अस्त-व्यस्त रहता है। इसलिए जब जिसका मौसम हो, जिस क्षेत्र में जिस सब्जी का बहुतायत में उत्पादन होता हो, जिस फल का उत्पादन जहाँ होता हो, एक सर्वे कराकर वहाँ पर शीतकालीन भंडारागार बनाने की व्यवस्था करें। इससे बढ़ती हुई महंगाई का जो एक अनावश्यक आरोप लगता है, उस पर भी हम नियंत्रण कर सकेंगे। यह हमारा एक अच्छा सुझाव है।

माननीय मंत्री जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी आपके अंडर में आती है। मैं तमाम सेंटर्स के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि यह खाद्यान्न और किसान से जुड़ा हुआ मसला है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेंटर्स लगते हैं, एफ.सी.आई. के, पी.सी.एफ. के या स्टेट पूल के, वहाँ देखने में आता है कि जिस टाइम पर किसानों की फसल की पैदावार होती है, उस समय उनकी खरीद सेंटर्स पर नहीं होती है। हमारे किसान औने-पौने दामों में अपना मेहनत से पैदा किया हुआ बहुमूल्य अनाज 800, 900 रूपए में बेचकर

उदास होकर चले जाते हैं। राज्य सरकारों में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही और दलालों की साठगांठ से आपका दिया हुआ समर्थन मूल्य, सरकार का दिया हुआ समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलता है। इस कारण सरकार की मंशा सफल होते हुए नहीं दिखती है।

आज हमारे देश का किसान हमारी भारत सरकार से उम्मीद लगाए है, हमारे प्रधानमंत्री जी से उम्मीद लगाए हुए है कि हमें अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा, लेकिन आज जो बिगड़ा हुआ तंत्र है, जो साठगांठ और मिलीभगत है, उसके कारण हमारा किसान आज भी लुट रहा है। धान तो हमारा लुटा ही है, हमारा गेहूँ भी लूटने की तैयारी है।

महोदय, मैं पुनः निवेदन करूँगी कि आप अपने इस संशोधन में जो लाए हैं, लाभ होने के कारण जो भारत सरकार को निरन्तर लाभ मिल रहा था, उसको आपने अपनी तरफ से अवमुक्त किया है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगी कि जो आपकी सब्सिडी है, उसे ज्यादा से ज्यादा जनप्रिय बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से आम जनता के लोग निजी तौर पर आगे कदम बढ़ाएंगे और इससे हमें भंडारागार बनाने में सुविधा मिलेगी। इसकी तरफ भी आप अपना प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और आप लोगों को आकर्षित करेंगे। इससे हमारे बहुमूल्य अनाज को सुरक्षित रखने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. I thank our Beloved Leader Makkal Muthalvar Hon. Puratchithalaivi Amma for making me a Member of Parliament representing Thanjavur Constituency and allowing me to speak on the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015. Hon Amma has been working tirelessly for the welfare of the people of Tamil Nadu.

Sir, Central Warehousing Corporation (CWC) was started in 1954 for the purpose of warehousing agricultural produce and other commodities and to arrange for selling them in market for a remunerative price. CWC is operating 464 warehouses across the country with a storage capacity of 10.8 million tonnes providing warehousing services for wide range of products ranging from agricultural produce to industrial products. Warehousing activities of CWC include foodgrain warehouses, industrial warehousing, custom bonded warehouses, container freight stations, inland clearance depots, shipping and railway cargo stations and air cargo complexes. If these cargo services are identified and clubbed together with the departments concerned, it would be early to maintain and manage. I urge the Government to take necessary steps in this regard.

As an achievement, CWC has handled Rs. 1528 worth products. During the year 2013-14 CWC has earned Rs. 256 crore as profit before tax and Rs. 161 crore as profit after tax. The shareholders are provided a dividend of 47 per cent. I welcome this. More number of Central Warehouses should be opened in the country particularly in Tamil Nadu in order to increase the profit of CWC. CWC also offers training for the construction of warehousing infrastructure in different States. This training should be further extended to Tamil Nadu.

Under the able guidance of Makkal Muthalvar Hon. Puratchithalaivi Amma, the warehouse under State Warehousing Corporation of Tamil Nadu function successfully with a total warehousing capacity of 6.37 metric tonnes.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

There are 60 such warehouses. The Central warehouses have a handling capacity of 6.04 lakh metric tonne. The State Warehousing corporation of Tamil Nadu was started in February, 1958. "A grain saved is a grain produced" - the motto of State Warehousing Corporation of Tamil Nadu.

The Government of Tamil Nadu under the able guidance of Hon. Puratchithalaivi Amma has taken steps to ensure remunerative prices for the agricultural produce, for their safe storage and for availing loans on produced grains. It was planned to establish 3317 warehouses with a storing capacity of 4,11,800 metric tonnes. As of now, 2251 warehouses have been set up with a warehousing capacity of 2,72,500 metric tonnes. Union Government should increase the grant for extending this further.

In Tamil Nadu, for crop fertilizer manufacturing units, out of 15 warehouses, 13 warehouses have been constructed with a cost of Rs. 3 crore. In Kannampalayam at the Grow Out Test (GOT) farm for seed certification, a new storage capacity has been created with an expenditure of Rs. 26 lakh.

Under the guidance of Hon. Puratchithalaivi Amma several Crores of Rupees are allocated for creating cold chain storage in Tamil Nadu to provide storage facilities for flowers, fruits, vegetables, perfume products, food grains and other commodities. If Union Government allocate adequate funds for such storage facilities, it will be more effectively implemented.

In the Railway Budget, it was stated that there are no adequate storage facilities to store food grains. As regards Tamil Nadu, Hon. Puratchithalaivi Amma has always been supportive for implementing pro-poor programmes. Hon. Amma will always welcome the programme which will not affect poor. I therefore assure that Hon. Amma will be helpful in setting up Railway warehouses in Tamil Nadu.

Farmers in my Thanjavur constituency and adjoining 10 districts are mainly dependent on cultivation of paddy, sugarcane, banana and coconut. I urge upon the Union Government for setting up a warehouse and a cold storage facility in every Panchayat Union in all the 10 districts adjoining Thanjavur. These warehouses can be also used for storing food grains under Public Distribution System.

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):The Warehousing Corporation (Amendment) Bill, 2015 was introduced in Lok Sabha on 3rd March, 2015.

The Bill has been brought to suitably amend section 5 of the Warehousing Corporations Act, 1962 which would withdraw the guarantee the Government has given to the Warehousing Corporations under sub-section (1) of Section 5 of the Act.

Sir, why should the Government absolve itself when Central Warehousing Corporations is making profit and has not taken any loan from the Government nor is it dependent on its Budgetary report? Why should the mini-Ratna Public Sector Enterprise be absolved from the administration of the Government? It defies logic and reasoning. The Government needs to explain a lot.

Sir, I would like to highlight the food worth thousands of crores is wasted every year. In 2013, we had wasted food worth Rs. 13,300 crore. On one hand, we find poor go to sleep without food, on the other hand, we see foodgrains rot in Government godowns. It would be astonishing to know that according to 2013 Global Hunger Index, India ranks 63rd out of 78 hungriest countries. India is worse than Sri Lanka, Nepal, Pakistan and Bangladesh. United Nations Food and Agricultural Organisation believes that 17 per cent of Indians are still undernourished people which is more than all sub-Saharan Africa.

According to UNICEF, 47 per cent of the Indian Children are underweight and 46 per cent of those under 3 years old are too small in accordance with their age. The shocking thing is that almost half of all childhood deaths can be attributed to malnutrition.

The Indian Institute of Management in Kolkata estimated sometime back that cold storage facilities are available for only 10 per cent of perishable food products, leaving around 370 million tons of perishable products at risk. There is a need to bring in vast changes to stop perishable food products.

India is a food surplus country but still we are not able to curb the food grain wastage. Our food production is going up on one side year after year. Courts

too are telling the Government not to waste foodgrain in godowns instead, distribute among poor. There is a need for establishing state of the art distribution chains, vast high quality cold storage network across the country to ensure that food is not perishable. We may also introduce refrigerated trucks. There is also a need to ensure electricity supply 24X7. Excessive use of pesticides during storage in godowns should be stopped.

We have ASSOCHAM study report which claims that over 30 per cent of food grains are stored unscientifically. Is it true that we have inadequate storage capacity to the tune of around 20-30 per cent of total food grain harvest which is declared as waste? What measures are put in place in the last 10 months to modernize the storage of food grains?

Thank you Sir.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, apparently, on the face of the Bill, the proposed amendments, especially the major amendment, substitution of Section 5 and amendment to Section 27(4) seems to be harmless. But if you go in-depth into the amendment which is being proposed, it can be that the amendments are having fatal impact on the working and the affairs of the Central Warehousing. Therefore, I rise to oppose this Bill.

The Central Warehousing Corporation was established in the year 1957. It was created by virtue of the Agriculture Produce Development Warehousing Corporation Act of 1956, and subsequently, this Act was repealed in the year 1962 to have a new enactment. It is seen that from 1956-57 onwards, since 1956-57 to till this date, every year the Government of India is getting dividend from the Central Warehousing Corporation. It is an undisputed fact that the performance of the Central Warehousing Corporation is going in a better way.

As Prof. K.V. Thomas, the then Minister, has congratulated the CWC officials, I also take this opportunity to congratulate the performance made by the CWC because in the year 1957 they started with a capacity of 7,000 tonnes and seven warehouses, and when we come to 2014, we are having 108 lakh tonnes of storage capacity and 464 warehouses. In the year 2013-14 alone, after exempting tax, the annual profit was Rs.256 crore. So, now it has become a mini *ratna* company.

The interesting fact to be noted is this. I am seeking a clarification on this from the hon. Minister. The Statement of Objects and Reasons enclosed along with the Bill is going to state that since the Central Warehousing Corporation is having a huge profit and it is giving dividend to the Government of India, no budgetary support is required as far as CWC is concerned. No budgetary support is required for this Public Sector Enterprise as it had been declared as a mini *ratna* in the year 1997. Since there is no requirement of budgetary support and no guarantee is required, what is the logical reasoning of this Bill?

My specific point is, as per the Statement of Objects and Reasons, there is no logical reasoning in bringing such an amendment. This is a company or a corporation which has made a huge profit. It is giving big dividend to the Government of India and its capacity has been increased like anything. Since it is such a good performing company, we need not give any budgetary support to this company and, therefore, the power of the Government of India being the guarantor is being taken away.

Sir, if this amendment is accepted by this hon. House or carried out, what would be the impact? We have to discuss that. What is the present status of the corporation? Suppose the shares are issued to the public by the Central Warehousing Corporation by means of the existing Act, definitely the shares will be guaranteed by the Government of India. When the shares are being guaranteed by the Government of India means, the value of the shares will be going up. It is having a statutory support. It is having the Government's support.

My only question to the hon. Minister is this. So many Members, even the hon. Member from Shiv Sena, and so many other hon. Members have already made their apprehension known. What is the specific reason for withdrawing Government of India as the guarantor for the share which is being issued to the public? What is the reason? The hon. Minister has stated two reasons. First, as I have said, it does not require any budgetary support and also it is making huge profit. Then, why do you withdraw from the CWC?

And, second, the hon. Minister's introductory remarks are going to show that more financial powers will be given to the CWC. No, it is wrong. How will the Central Warehousing Corporation be getting financial powers? Suppose the shares issued by the Central Warehousing Corporation are having guarantee or the guarantor-ship of the Government of India, is the financial power or the financial autonomy of the CWC lost? If the CWC has to get some financial autonomy, then you have to relax the norms and you have to give more powers to the corporation since it is a mini *ratna* company. Instead of that, you are withdrawing the

guarantor-ship of the Government of India. What is the intention? What is the benefit? All right, we do agree.

16.00 hrs

Sir, my simple question is this. The fate of ITDC hotels and so many other companies is well known to all of us. Suppose, after five or ten years, like ITDC, it goes into losses, what would be the fate of this company? This will automatically be disinvested and privatised. I feel that there is something with a long-term perspective so as to privatise the CWC. My apprehension is that such an intention is behind this Bill. Otherwise, let the hon. Minister clarify it.

Last week I was in Udaipur. I forgot about a company, which had been given to Vedanta Group. It is making huge profits after disinvestment. That is why, I am saying that there is no harm, looking apparently on the face of the Bill. Suppose in future, the Corporation goes into losses, definitely, this will happen.

So, Section 5 is being substituted by a new section. That section is there in the Insurance Act, 1938 and Banking Regulation Act, 1949. It is there in the form of Section 20 of Indian Trusts Act, 1882. In all these cases, this will come within the ambit of securities. This is being protected by way of securities under these three Acts, but here the Government is absolving its entire responsibility. It means that the Government is slowly withdrawing. Now, they will withdraw the guarantee of the Government and in future, they will withdraw the control. This is only my apprehension as to how this will normally be going.

The next major amendment is of Section 27(4). The original Section 27(4) says:

“The bonds and debentures of a State Warehousing Corporation may be guaranteed by the appropriate Government

The only portion deleted from the Bill is ‘as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the appropriate Government’. So, as far as the bonds and debentures of the Warehousing Corporation are

concerned, the repayment is not being guaranteed. Those words are taken away from the original section. In the amended Section 27(4), these words are missing.

I cannot understand the omission of those words. Here also, this is in respect of issuance of bonds and debentures. For this, the Government is guaranteeing, but not for the repayment of the principal and interest. What is the intention behind it? So, the two core amendments to Section 5 and Section 27(4) are creating some sort of apprehension. It means that the Government is slowly withdrawing from the Central Warehousing Corporation. The fate or future of this Corporation may also be like that of the ITDC. Hence, I am having this reservation and seeking a clarification from the hon. Minister.

I conclude with these words and thank you very much, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now Shri Kaushalendra Kumar will speak.

I would request the Members to speak very briefly because we have to pass the Bill before 4.30 p.m.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि, यह भारत सरकार के प्रमुख भंडारण एजेन्सी तथा देश भर में सार्वजनिक वेयरहाउस चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जो कृषि सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को भंडारण के क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है। किसानों से जुड़े होने के कारण इस संस्था का महत्व काफी बढ़ जाता है।

हम बिहार राज्य से चुनकर आये हैं। हम लोग किसान परिवार से हैं। बिहार में किसान बहुत परेशान हैं। उनके धान की खरीद कम कीमत पर हो रही है। आज भंडारण की कमी के कारण, वे अपना धान औने-पौने दाम में बेच रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, जो बिहार से ही आते हैं। हमारे खड़गे जी, थॉमस जी और रामचंद्रन जी ने कुछ शंकाएं जाहिर की हैं। मैं समझता हूँ कि किसान परिवार से ही हमारे मंत्री जी हैं, निश्चित रूप से वे किसानों की हित की रक्षा करेंगे।

राज्य सरकार ने किसानों के हित के लिए कई भंडारण की व्यवस्था की है। यह जो विधेयक लाया गया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आज देश में अनाज को रखने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है, जिसके कारण खुली जगह पर अनाज का स्टॉक किया जाता है, जिससे अनाज की बर्बादी होती है। इसलिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता का निर्माण आवश्यक है। किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जबकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव में वादा किया था कि किसान की जो लागत लगेगी, हम उसका डेढ़ गुना मूल्य उसे देंगे। आज किसान बिहार में औने-पौने दाम में धान बेच रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए ढाई सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिए हैं।

रख-रखाव की एक बड़ी समस्या है। अनाज के उचित भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज हर साल बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है। कई टन अनाज चूहे भी खा जाते हैं। जहां एक ओर देश के गरीब लोग भूख से मर रहे हैं वहीं हजारों टन अनाज सड़ने की शिकायत भी मिली है। इसे नियंत्रण करना आवश्यक है क्योंकि देश की जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की है, किन्तु सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या पर नहीं जा रहा है। एक ओर जहां सरकार इस महत्वपूर्ण संस्था को स्वतंत्र कर रही है, वहां इसके दायित्वों का भी ध्यान रखे कि वह सही तरीके से निर्वहन करे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हर राज्य सरकार से बात करके इसमें सुधार किया जाए और राज्य सरकारें भी आपसे परामर्श करके उचित कदम उठाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बिल की प्रस्तावना रखते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी कारणों से लाया गया है। यह बिल पूर्ववर्ती सरकार के समय लाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय इसे लोक सभा से पारित नहीं करवाया जा सका, इसलिए अब पारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्तावना रखते हुए कहा कि इस बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह विषय इतना गंभीर है कि इस पर आपने चर्चा की अनुमति दी। विषय केवल इतना नहीं है कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के एक्ट में हम संशोधन की बात कर रहे हैं, बल्कि यह कृषि और इस देश के अन्नदाता के श्रम के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अभी सदन में इस बारे में चर्चा हो रही थी। कृषि के विषय पर इस सदन में अनेक बार चर्चा हुई भी है। आज भी शायद कृषि के विषय पर इस सदन में चर्चा होने वाली है। कृषि और कृषि के उत्पादन के मूल्य से जुड़ा हुआ विषय सीधा आज की चर्चा से सम्बद्ध है। इसी सदन में खाद्यान्न के उत्पादन की चर्चा हो रही थी और अनेक बार इस विषय में बात भी की गई है कि 30 प्रतिशत उत्पादन हर साल सड़ जाता है, खराब हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। जब सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना की गई थी, लगभग उसी के समकक्ष किसी समय में, यहां वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं, आदरणीय खड़गे साहब बैठे हैं, इन्हें ध्यान होगा कि भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इस बात की मांग की थी और देश से इस बात की अपील की थी कि देशवासियों को सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए ताकि इस देश के भूखे लोगों को अन्न मिल सके। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना के बाद देश को निश्चित रूप से अन्न की सुरक्षा मिली है, लेकिन जिस तरह अनप्रोफेशनली और अनहाइजिनिक वे से इस देश के वेयरहाउसिंग, फूड कार्पोरेशन के गोदामों में अन्न का संचय होता है, मैं एसोचैम की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 30 प्रतिशत अन्न हर साल बर्बाद हो जाता है।

मैं थोड़ी देर पहले कुछ आंकड़े देख रहा था। सन् 2012 में केवल पंजाब और हरियाणा के गोदामों में एक लाख छः हजार टन गेहूँ और खाद्यान्न बर्बाद हुआ। यदि एक परिवार को एक महीने में 30 किलो गेहूँ की आवश्यकता होती है, एक वर्ष में 1.6 लाख टन की बर्बादी होती है, उससे एक लाख भूखे परिवारों को तीन साल तक दोनों समय का भोजन कराया जा सकता था। यह समय की मांग है और देश की आवश्यकता भी है। कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी चर्चा की गई, 45,000 हजार करोड़ रुपये का खाद्यान्न, सब्जियों और फलों का वेस्टेज भंडारण और प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होने के कारण हो रहा है। माननीय

प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता के विषयों में से भी एक है। 70,000 हजार करोड़ रुपये की घोषणा सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की गई है। इस सदन के माध्यम से मैं सरकार और मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बांड के माध्यम से पैसे जुटाए जाने हैं उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को इसके साथ भी जोड़ा, कृषि के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की इस देश को आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। यह चर्चा की गई गई है कि ढाई सौ करोड़ रुपये का प्रोफिट इस संस्था को हो रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से इस संस्था के बाद भी अन्न का नुकसान हो रहा है। यदि उसकी कीमत जोड़ी जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस बिल के माध्यम से मंत्री महोदय ने प्रस्तावना रखते हुए कहा कि बिल में संशोधन करने के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में और आकर्षित होगा। यह समय की मांग है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में निवेश करने वाले लोगों को इन्कम टैक्स में रिलीफ दी जाए, इन्कम टैक्स बेनिफिट दिए जाएं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और अधिक प्रोत्साहन के लिए शार्ट टर्म लीज की अवधि को लॉग टर्म लीज में परिवर्तित किया जाए जिससे और अधिक लोग इस क्षेत्र में आकर्षित हो सकें और देश का जो नुकसान हो रहा है, श्रमदाता के श्रम का जो असम्मान हो रहा है, उससे यह देश उबर सके।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the scope of this Bill is very limited. My learned friends have explained that and I do not want to say much on that.

We are proud of our country in many sectors like technology, education, growth rate in the financial sector and all kinds of things. But as far as storage of food grains is concerned, our position is very backward. We all know that. Figures show that very clearly. Our willingness for introducing new technology in the storage sector is very poor. As far as industrial relations in Warehousing Corporation are concerned, I think they are also not up to our expectations.

If we see the storage capacity in the country then and now, we know that the capacity was 7000 tonnes with seven warehouses, and now it is 108 lakh tonnes with 464 warehouses. That much of progress we have made and we can be proud of that. However, there is still a wide gap between the availability of space and the real requirement. In response to a question in this House it was stated that we are having a wide gap in storage capacity.

ASSOCHAM have made a scientific study on this. They said in their report that around 20 to 30 per cent of total food grains harvest is wasted due to inadequate storage capacity. Each grain bag is handled at least six times before it is finally opened for processing which leads to higher storage and transport charges.

Similarly, only 29 per cent of space in warehouses are available for agro type of storage. Similarly, many study reports say that India wastes food worth Rs 13,000 crore annually. That is the figure in that report.

Similarly, *The Hindustan Times* reports say that millions go hungry, but India lost foodgrains worth Rs 45 crore in 5 years.

Sir, we are failing in many sectors but there is a silver lining in this. In the last UPA Government, Prof. K.V. Thomas did his maximum for increasing this storage capacity. Similarly, the new Minister is also doing that.

The last point is about industrial relations. In our system, in Warehouse Corporation, industrial relation is not very cordial. I urge upon the Government to make it more cordial.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों को यहां रखने का काम किया है। थामस साहब यहां बैठे हैं। इस बिल का दायरा बहुत छोटा है। यह अमेंडमेंट है और जैसा उन्होंने कहा कि इन्हीं का बच्चा है। हम सिर्फ उसे लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह प्रजातंत्र की खूबी है। हम भी जब आपोजिशन में रहते हैं, तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि कोई पूछे कि अभी कितना समय हो रहा है और पार्लियामेंट में डिसकशन शुरू हो जाये, तो अभी सवा चार बज रहे हैं। लेकिन लोग बहस करना शुरू करेंगे कि अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है और डिसकशन करते-करते जब भारत में आयेंगे, तो उस समय सुबह के सवा चार बज जायेंगे। इसलिए खासियत भी है। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, खड़गे साहब हमारे साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने दो-तीन बातें कहीं। एक बात उन्होंने यह कही कि जो ढांचा है, उसके तहत पूंजीगत शेयर होल्डर का विश्वास कहीं खो न जाये और हम कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब थामस साहब ने पहले ही दे दिया था। इस पर बहुत डिसकशन हुआ और डिसकशन होने के बाद यह मामला स्टैंडिंग कमेटी में भी गया था। स्टैंडिंग कमेटी के बाद कैबिनेट में गया, फिर कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट में आया। पार्लियामेंट के बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी से लौटकर आया, लेकिन तब तक चुनाव हो गया। उसके कारण यह बिल पास नहीं हो सका।

जहां तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, जब 50 परसेंट से ज्यादा शेयर, यानी 55 परसेंट शेयर गवर्नमेंट का रहेगा, तो उस परिस्थिति में शेयर होल्डर को इसमें कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह उठायी गयी कि यह बिल क्यों लाया गया और इसकी क्या जरूरत पड़ी? यहां मोइली साहब समेत सब वरिष्ठ साथी बैठे हैं। जब आप मिनीरत्ना और ग्रेड-वन का दर्जा दे देते हैं, तो सरकार के सपोर्ट को हटाना पड़ता है। उससे आपको अलग करना पड़ता है, क्योंकि यह नियम है, कानून है। उसी नियम के तहत, चूंकि मिनीरत्ना और ग्रेड-वन का दर्जा दिया गया, अनुसूची एक में रखा गया, उसके तहत 5(1) है या 27(4) वगैरह सब उसी से संबंधित हैं। इसलिए उसके तहत इसे हटाना जरूरी थी, इसलिए हटाया गया है। हम समझते हैं कि इसके पीछे कोई दूसरी मंशा नहीं है।

श्री के.वी.थामस साहब इसी मंत्रालय में रहे हैं। हम लोग हमेशा बातचीत भी करते रहते हैं। हमारी एक आदत है कि हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हम ही सब कुछ जानते हैं। हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, हम उनसे और खासकर पूर्व मंत्रियों से बात करते रहते हैं कि जिस सुधार की आवश्यकता

है, उसे बताएं। हम हमेशा बातचीत के लिए बैठते हैं। इन्होंने साइलो के बारे में कहा है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। यहां शांता कुमार जी बैठे हुए हैं। कई साथियों ने एफसीआई के बारे में जिक्र किया है। हालांकि यह कार्य क्षेत्र में नहीं है। रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि साइलो पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने बिहार, यूपी के बारे में कहा। कौशलेन्द्र जी, बिहार के बारे में बोल रहे थे। बिहार में 53 लाख टन अनाज की आवश्यकता है। हम मान लेते हैं कि 53 लाख टन में 33 लाख टन चावल की जरूरत है। अब 33 लाख टन को डेढ़ गुणा कर देंगे तो 51 लाख टन के करीब होता है। अब 51 लाख टन धान की आवश्यकता है। बिहार डीसीपी स्टेट है। यहां एफसीआई नहीं खरीदती है, राज्य सरकार खरीदती है। यहां हमारे कई साथी बैठे हैं, रमा जी बैठी हैं, उपेन्द्र जी बैठे हैं। सब लोग वहीं से हैं। पहले हमने कहा कि 31 जनवरी तक खरीदने का समय रखिए और सब राज्यों से बात की। जब फसल की कटाई होती है तो उसी समय किसान बेचता है और बाद में बिचौलिया लेकर बेचना शुरू कर देते हैं। कहा गया कि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दीजिए तो 15 फरवरी कर दिया। इसके बाद कहा गया कि 28 फरवरी कर दीजिए और 28 फरवरी कर दिया। इसके बाद कहा गया कि 28 फरवरी से 15 मार्च कर दीजिए तो 15 मार्च कर दिया और अब कहा गया कि 31 मार्च कर दीजिए। कितनी खरीद हुई? हमें 53 लाख टन चाहिए और अभी तक दस लाख टन खरीदा गया। हम बाकी कहां से लाते हैं? हरियाणा, पंजाब से लाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी बैठती है? कौशलेन्द्र जी भी यही कह रहे थे कि किसान सब जगह चिल्ला रहे हैं कि एमएसपी रेट पर कोई खरीदता नहीं है। कौन खरीदेगा? अभी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, शांता कुमार जी ने रिपोर्ट दी है और कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश गरीब राज्य हैं, इनकी तरफ एफसीआई को ध्यान देना चाहिए और खरीद करनी चाहिए। हम इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे और दे रहे हैं।

महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि दो गलतफहमियां हैं। एक बोनस को लेकर है कि जो बोनस लागू किया गया, उसमें कहा गया कि वह राज्य जो डीसीपी स्टेट है और जहां सरप्लस पैदावार होती है, वहां बोनस की बात है लेकिन, पंजाब उसमें नहीं है। पंजाब डीसीपी राज्य नहीं है, पंजाब में खरीद की बात है तो उसमें कहां बंद है। इन्होंने एफसीआई के बारे में कहा। एफसीआई वहां नहीं खरीदती है, हाँ एफसीआई भी खरीदती है। एफसीआई टोटल दस परसेंट खरीदती है। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम अपने आप व्यवस्था कर लेंगे, आप एफसीआई से कहिए कि दूसरी जगह पर लगे। पंजाब सरकार कहेगी तो हम करेंगे, वह नहीं करेंगे तो हम खरीदेंगे। 'कौआ कान लिए जा रहा है' तो पहले हम कान को देखेंगे कि कौए को देखेंगे। हल्ला हो जाता है कि यह हो गया, वह हो गया, कुछ नहीं हो रहा है।

महोदय, जहां तक भंडारण की बात है। हमारे पास 2,000 लाख टन की पैदावार होती है जिसमें से 2014-15 में गेहूं का उत्पादन 957 लाख टन और चावल का 1030 लाख टन हुआ। दोनों को मिला दें तो करीब 2,000 लाख टन होता है जबकि गेहूं की खरीद 957 लाख टन में से 280 लाख टन हुई है और चावल की 418 लाख टन हुई। दोनों को मिला दें तो करीब 598 लाख टन हो जाता है। कुछ सदस्यों ने पूछा कि भंडारण की क्या कैपेसिटी है। भंडारण की कैपेसिटी हमारे यहाँ 711 लाख टन की है। लेकिन यह बात जरूर है, हम भी इस बात को चाहते हैं, हमारे पास गोदाम की संख्या भले ही जरूरी हो, लेकिन क्रय-केन्द्र सभी जगहों पर खुले। क्रय-केन्द्र है ही नहीं। मैं तो सबसे वर्स्ट बिहार का ही उदाहरण दे सकता हूँ। श्रीमती रंजीता जी यहाँ पर बैठी हैं। बिहार के पूर्णिया, मधेपुरा वगैरह में चले जाइए, वहाँ के किसान कहाँ बेचेंगे? जो चावल के मिल-मालिक हैं, वही खरीदते हैं। इधर से उधर जाता है और वह हल्ला करता रहेगा। बिचौलिया किसान से 900 रुपए में खरीदेगा और उसे 1400-1500 रुपए में बेचेगा। यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है।

श्रीमती कृष्णा राज : यह रुकेगा कैसे?

श्री राम विलास पासवान : उसको रोकने के लिए मैंने कहा, देखिए! हर चीज़ में होता है कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। इसमें दो काम हैं। एक काम केन्द्र सरकार का है। हमारा काम है कि हम पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से अनाज उठाते हैं और उसे दूसरे राज्यों में देने का काम करते हैं। अब अनाज हरियाणा से उत्तर प्रदेश आ गया, पंजाब से बिहार आ गया। बिहार में एफसीआई के गोदामों तक पहुंचाना हमारा काम है। एफसीआई के गोदामों से वह अनाज कहाँ जाता है, वह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार स्टेट के गोदाम में ले जाती है, वहाँ से फेयर प्राइस शॉप पर ले जाती है, उसके बाद वह बेनिफिशियरीज़ के यहाँ ले जाती है। हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो शिकायत क्या है? शिकायत सभी जगह पीडीएस से है। गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, खराब अनाज मिलता है। हमारे पास गोदाम की जितनी कैपेसिटी है, 50 प्रतिशत गोदाम केन्द्र सरकार के हैं और 50 प्रतिशत गोदाम राज्य सरकार के हैं। यदि दो हजार टन अनाज पैदा हो रहा है और केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर सात सौ टन खरीदती है, तो बाकी 1300 टन की जवाबदेही कौन ले रहा है? 1300 टन में से कुछ अनाज कहीं खेत में पड़ा हुआ है।

श्री आर.के.सिंह (आरा) : मैं भोजपुर से आता हूँ। हमारे यहाँ यह दिक्कत हुई कि बारिश के दिनों में हर पाँचवें दिन पर कहा जाता था कि गोदाम भर गया। भारत सरकार की भंडारण कैपेसिटी होगी, लेकिन बिहार में भंडारण कैपेसिटी की कमी है, इसकी बेहद कमी है।

श्री राम विलास पासवान : बिहार में 53 लाख टन अनाज सालाना चाहिए। तो एक महीने में लगभग साढ़े चार लाख टन चाहिए और गोदाम की कैपेसिटी पाँच लाख टन से ज्यादा है। हम चाहते हैं कि एक हर स्टेट स्तर पर विचार हो। बहुत-सी गलतफहमियाँ भी हैं। बिहार के संबंध में मैं सोच रहा था, लेकिन पता नहीं अभी संसद का सत्र कब तक चलता है, हम चाहते थे कि एक बार हर स्टेट के एम.पीज़ को बुलाकर संबंधित राज्यों की समस्या के संबंध में पूरे तौर से बातचीत करें। जैसा कि हमने कहा, आप जो बात कह रहे हैं, जैसे आप आरा की बात कह रहे हैं, हो सकता है कि टोटैलिटी में गोदाम की कैपेसिटी ज्यादा हो, लेकिन जिस एरिया की बात ये कह रहे हैं, वहाँ यह कम हो, ऐसा हो सकता है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Minister complete the reply. We have to take up another Bill also.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.

... (Interruptions)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : मंत्री जी यह कहा गया कि सालाना 53 लाख टन अनाज एफसीआई द्वारा लिया जाएगा लेकिन वहाँ यह कहा जाता है कि पिछले साल का ही अनाज अभी गोदाम में पड़ा है, इसलिए इस साल हम कम ले रहे हैं। इस समस्या को आप कैसे हल करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जैसा हमारे साथी ने पूछा है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि पहले ऐसा होता था कि चार-पाँच साल अनाज रखा रहता था। हमने आने के बाद स्ट्रिक्टली कह दिया है कि चावल और गेहूँ की लाइफ दो साल की होती है, क्योंकि दो साल तक इनकी क्वालिटी बढ़िया रहती है। डेढ़ साल से ज्यादा कोई भी सामान कहीं भी नहीं रखा जाएगा। हमने आर्डर जारी कर दिया है और यदि कोई कहेगा तो हम चैकिंग करने के लिए तैयार हैं। यदि मालूम हुआ कि डेढ़ साल से ज्यादा समय से सामान किसी गोदाम में रखा है, तो उस जी.एम. को हम उसी समय सस्पेंड करेंगे, यह हमारा वायदा है।

साइलो के संबंध में कहना चाहता हूँ कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। चूंकि उसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी है, सबसे ज्यादा कम लीकेज का मामला है।

श्री धर्मवीर (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : हरियाणा के किसानों के लिए दिक्कत आ जाएगी क्योंकि आपने अपने शब्दों में कहा है कि हरियाणा की सरकार ने कहा है कि हम अपना प्रबंध स्वयं करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : हरियाणा के किसानों से आप कहिए कि वे अपना भ्रम दूर कर लें। केवल एफसीआई ही उनका अनाज नहीं खरीदती थी बल्कि एफसीआई भी उनका अनाज खरीदती थी। राज्य

सरकार के साथ एफसीआई भी उनका अनाज खरीदती थी। जैसा हमें आफिशियली बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि एफसीआई को दूसरी जगह खरीदने के लिए कहिए, हम खरीद लेंगे। यदि हरियाणा सरकार कहेगी कि हम सक्षम नहीं हैं और एफसीआई भी खरीदे, तो एफसीआई भी हरियाणा के किसानों का अनाज खरीदेगी। लेकिन शांता कुमार जी की कमेटी की रिपोर्ट है, इन्होंने ही अपनी कमेटी रिपोर्ट में कहा कि दूसरे राज्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अभी हमने फैसला नहीं लिया है।... (व्यवधान) हमने कहा है कि रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि 67 परसेंट से घटाकर 40 परसेंट कर दीजिए, तो क्या हम 40 परसेंट कर देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खड़गे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, थामस साहब ने अपने विचार रखे, गणेश जी ने बहुत बढ़िया सुझाव रखा, विजय कुमार जी, तपस कुमार मंडल जी, बलभद्र मांझी जी, नरसिंह जी, श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर, बाराप्रसाद राव जी, श्रीमती कृष्णा राज, परशुराम जी, प्रेमचंद्रन जी, कौशलेन्द्र कुमार जी, राजेन्द्र सिंह शेखावत जी, मोहम्मद बशीर जी और अन्य सभी माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए हैं, उनको मैंने नोट किया है और मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें ज्यादा डिटेल् में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जगह पर अगर कोई दूसरा मंत्री होता, तो कह देता कि यह मामला सीडब्ल्यूसी का है और सीडब्ल्यूसी में कुछ नहीं है। यह टेक्नीकल मामला है और इसे मिनी रत्न मिल गया है इसलिए इन्हें मिनी रत्न के मुताबिक पांच-ए को खत्म कर देना चाहिए। उनके लिए यह सिर्फ दो लाइन का मामला होता। लेकिन आप सभी साथियों के मन में कुछ शंकाएं थीं, जिनकी तरफ मैंने आपका ध्यान खींचा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम तो जमीनी स्तर के नेता हैं और जो आपका काम होता है, उसी काम को हम अपने डिपार्टमेंट से क्रिटिकल होकर पूछते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हमारे रहते हुए, हमारी सरकार में चाहे किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, कहीं भी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House may now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि इस विधेयक को पारित किया जाए।”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

16.36 hrs**REPEALING AND AMENDING BILL, 2014**

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up item No. 28, namely, the Repealing and Amending Bill, 2014.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to move:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration.”

Sir, the Repealing and Amending Bill, 2014 which was introduced in Lok Sabha on 11th August, 2014 proposes for repeal of 36 Acts out of which four Acts were suggested by other Ministries/Departments. It also proposes to amend two Acts to correct formal defects and patent errors detected therein. The said Bill was referred to the Departmentally-related Parliamentary Standing Committee which has submitted its Report on 19th December, 2014. The Committee has recommended that the Bill may be passed after omitting the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 from the Bill.

The Committee has observed three or four things that need to be taken into consideration. The recommendations of the Standing Committee, *inter alia*, are (1) for a sun-set clause for their automatic repeal clause so that they do not remain on Statute Book after their purpose is achieved. That is one point which need to be looked into; (2) to have easy and understandable codification of the law; and (3) to make the law simple while reviewing the existing enactments on the Statute Book; and there is one Bill which need to be left out. These are the four observations made by the Standing Committee.

With these words, I present the Bill before the House.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration”

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Mr. Deputy-Speaker Sir, I thank you for allow me to participate in the discussion on the Repealing and Amending Bill, 2014. I am also grateful to our beloved President, Shrimati Sonia Gandhi for allowing me to participate on behalf of the Party.

At the very outset, I would like to wish the hon. Minister many happy returns of the day. We are very old friends and colleagues. I know that he is becoming younger today.

Repealing laws and amendment Acts which have lost their meaning is important for modernization and reform of laws because it clears Statute Books and spares citizens from inconvenience of taking notice of unnecessary laws which have ceased to bear any relevance to the current conditions. In 1998, the Jain Commission had examined around 2500 central laws in the Statute Book and recommended that more than 1300 laws be repealed.

The Repealing and Amendment Bill, 2014 has initiated the process of clearing these laws from the Statute Book by proposing to repeal four principal laws and 32 amendment Acts. The Bill also further amends two laws, namely, the Prohibition of Manual Scavengers Act, 2013 and the Whistle Blowers Protection Act, 2011.

The four principal laws which are being repealed by this Bill are:

1. The Indian Fisheries Act, 1987.
2. The Foreign Jurisdiction Act, 1974
3. The Sugar Undertakings (Takeover of Management) Act, 1978, and
4. The employment of Manual Scavenging and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1978.

The Indian Fisheries Act, 1987 was enacted by the British. It has lost its relevance after we adopted our Constitution, which placed 'fishing' in the State list. This law thus has never been involved because of its lack of applicability. So, this law needs to be repealed.

Here, I would like to have a clarification from the hon. Minister regarding the cases of foreign sea fishing or deep sea fishing where our fishermen are also involved in certain cases. I would like the Government to take some corrective measures because there are some old cases. Will they be affected or not? That the hon. Minister should clarify.

In the case of Foreign Jurisdiction Act, 1947, I would like to say that this law applies to Indian territories under the foreign control. It is not relevant anymore because all our territories with native States have been fully integrated into the Union of India.

In the Standing Committee a point was raised whether the repeal of the Foreign Jurisdiction Act, 1947 would have any adverse affect on the Instrument of Accession signed between the Government of India and the Tribal Kings of the North-Eastern States, like the States of Nagaland, Meghalaya, Tripura, Assam, and the tribes of Arunachal Pradesh.

I would like to say that the hon. Prime Minister during his visit to the North-East and the hon. Finance Minister in his Budget speech, and in the President's Address also it is mentioned that the North-Eastern States are given special preference. But I would like to draw your attention to the fact that the North-East Industrial and Investment Policy, NEIIP, 2007 has been suspended. It really affects the people of the North-East when you people in the mainland say that you are thinking of the interests of the North-East, in fact suspend the Industrial Policy. It really hurts the people of the North-East. Taking this opportunity, I would like to appeal to the House that this should be again brought back and this should be taken into consideration.

The Sugar Undertaking (Takeover of Management) Act, 1978 was invoked as a short-term measure to empower the Union Government to assume temporary management of defaulting sugar undertakings. The provision of the law has not been utilised since the last three decades and is further useless because the State Governments have enacted their own respective legislation to protect sugar crop growers. Thus, this law has become obsolete.

Though the management of the mills was handed over to the respective sugar mill owner, an amount of Rs. 19.58 crore still needs to be recovered. Though the savings clause in the Bill has been included so as to protect the interests of the Union Government in recovering the loan, I would like to ask the Government whether it is possible to recover the amount which has not been recovered for all these years. The principal amount along with the interest needs to be recovered. Hence, I would request the Government to respond to this and explain as to how and when the Government is planning to recover the amount.

The fourth principal law which is being repealed by this Bill is, the Employment of Manual Scavenging and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993, which has also lost its relevance after UPA II Government's comprehensive legislation. The UPA Government has done a great job, by passing the Prohibition of Manual Scavengers Act in 2013. That law has a wider scope and higher penalties to the offenders. It prohibits manual scavenging and provides for rehabilitation to manual scavengers by providing them alternative employment. So, the law of 1993 is no longer necessary and needs to be repealed.

However, the Manual Scavenging Act of 1993 has been enacted by the Parliament upon the receipt of Resolution of six State legislatures, namely Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra, Tripura and West Bengal. Now, when the Government is repealing that law, first of all the Government needs to take the Resolution of those respective State Assemblies into consideration. The Standing Committee Report has also observed this violation. This is in para 9.2. It says, "The Committee is, however, surprised to note that the repeal of such an Act has been

initiated without receiving Resolutions from the concerned State which appear to be a violation article 152 of the Constitution.”

Article 252 of the Constitutions says and I quote:

“Any Act so passed by Parliament may be amended or repealed by an Act of Parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State. ”

The Government should thus follow up for passage of Resolutions in the said States. Because, bypassing State Legislatures and constitutional provisions and procedures sets a bad precedence in our country and it is a violation of the Constitution. Also, the Government must amend Section 5 of the Prohibition of Manual Scavengers Act, 2013 which 5 reads:

“Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993, no person, local authority or any agency shall, after the date of comment of this Act, construct an insanitary latrine,....”

So, Sir, the Government needs to bring a subsequent amendment to Section 5 of the Prohibition of Manual Scavengers Act, 2013 to bring clarity to the statute. The other 32 amendment Acts which are being repealed by this Bill do not have any impact on the existing law of the land and their repeal only removes what is already dead. Because, the contents of these amendments are included in the respective principal laws.

After the introduction of this Bill, the Law Commission of India had submitted four interim reports till November, 2014 which further identified laws that have become obsolete and thus recommend for immediate repeal

The Commission has recognized 252 laws which are obsolete and have ceased to be relevant in tune with the changing needs of the time. Also, the PMO Committee has identified 1741 of the 2781 existing Central Acts to be repealed. I

request the Government to take note of this and further bring forward more repealing and amending Bills to clear the statute book.

I also recommend to the Government to include a sunset clause - which the hon. Minister always stated - in every amending Bill and appropriate Bill so that laws will be repealed automatically after their intended purpose has been fulfilled.
Thank you.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for affording me an opportunity to participate in the debate with respect to the Repealing and Amending Bill, 2014.

I stand here to support the Bill. Basically, if we trace the origin of the repealing and amending provision, it started in the year 1856 in the United Kingdom and in our country also from 1866. This is a periodical exercise even during the pre-Independence era. Up to 1998, we have repealed almost 1291 Acts by ten Repealing and Amending Acts. But, after 1998, so far, no exercise has been done. Only one exercise was done during the last Session. In 2014, 90 amending Acts were repealed by a Repealing and Amending Bill, 2014. Now, by this Repealing and Amending Bill, 36 Acts have been taken into consideration. Out of the 36, four relate to principal Act and the remaining 32 relate to Amending Act.

Basically, the effect of Repealing and Amending Bill is that. Once the amendment is notified, then the amendment in the principal Act is automatically carried out.

Now, what is the effect of this Act? Basically the question arises - will it repeal the amendments made in the principal Act? For this purpose, already clause 4 of this Bill is there. But Section 6(a) of the General Clauses Act takes care of the situation. Therefore, the amendment made in the parent Act, by amending Act, will be incorporated in the parent Act. Repeal of such amendment Act will not affect the continuance in force of the amendment which has already become part and parcel of the principal Act.

So far as clause 4 of this Bill is concerned, basically it is analogous with Section 6 (a) of the General Clauses Act. Clause 4 provides the saving provision to the effect that anything done under that Act will not affect if the provision of amendment Act is repealed. I would also like to suggest to the hon. Minister that instead of doing this exercise every time, we can also carry out a suitable amendment in Section 6(a) of the General Clauses Act, so that all the exercises

that are carried out every time, bringing the Repealing and Amending Bill before this august House may be taken care of.

So far as the functioning of the amending Act is concerned, basically it only incorporates the amendment in the principal Act, and once the function of incorporation is accomplished, then it dies a natural death. But that is not sufficient. For the Act to die a legal death, the Repealing and Amending Bill is being brought before this august House. It is not the case like a human being. Once the natural death is there; no legal death is required to be carried out. But in the Bill like this, once the amendment is carried out, it is nothing more to understand as to what is the purpose of the amending Act. Basically, the amending Act is a launch vehicle. Once the satellite is launched in the orbit, then, there is no use of launch vehicle. But formally we have to bring it before this august House, to give it a legal shape. Once it is passed by this august House, then only we can remove that deadwood from the legal library. Therefore, in other terms, we can say that basically the Repealing and Amending Act pertains to those Acts which cease to be in force and become obsolete and no purpose is served for keeping these Acts in the law library. Moreover, it also creates confusion.

For this we have to adopt the pragmatic jurisprudence instead of bringing every time before this august House we can provide a deeming provision or sunset clause in the Act itself. Once the Bill is notified, it will perform two functions. One is – amendment is carried out in the principal Act; at the same time, it will also work as the deeming provision in the Act itself, which suggest that as soon as the Act is notified, then the amending Act is deemed to have been repealed. So, by amendment Act itself, we can determine the life of the Act itself, then, it would cease to be in force automatically.

Through the Repealing and Amending Bill, three principal Acts have also been brought for repealing. One is the Indian Fisheries Act, 1897; that is of British era. The object of the Act was to prevent killing of the fish or poisoning of water etc. and the punishment was also provided. For that purpose, after coming

into force of the Constitution of India, now fishing is a State Subject and fishing and fisheries beyond territorial water is under the Union List. Therefore it is rightly being repealed by this Repealing and Amending Bill.

So far as the Foreign Jurisdiction Act, 1947 is concerned, as per Article 372, only those Acts enacted prior to the commencement of the Constitution, except those repealed by the Constitution, shall continue. So, it is no longer required as no territory of India is under the control of any colonial power. Therefore, this is also a right step for repealing such type of obsolete law.

The third is the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act. Since 2013, sugar sector has been decontrolled; levy obligation on sugar mills have been removed, and regulated release mechanism of open market sale of sugar has been dispensed with. The Act is not relevant in the present scenario. The Act was a temporary measure taken way back in 1978.

With this suggestion, I extend my thanks to the hon. Minister and I fully support the Repealing and Amending Bill, 2014. Thank you very much, Sir.

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Thank you, Sir, for allowing me to participate in the debate on the Repealing and Amending Bill, 2014 which is enumerated as Bill No. 95 of 2014. Already, Bill No. 155 of 2014 was passed in the last Session by this august House.

In this Bill, as many as 36 Acts are sought to be repealed which are enumerated in the First Schedule. In the First Schedule, the first four Acts are obsolete laws which are no longer required because they have become redundant. The remaining 32 are Amendment Acts. The provisions of these Amendment Acts have already been incorporated into the Principal Acts. Therefore, these Amendment Acts need no longer be on the Statute Book. Therefore, the items mentioned in the First Schedule are to be repealed. The two items in the Second Schedule, namely, the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, and the provision in the Whistle Blowers Protection Act need to be amended because by some inadvertence, some errors have crept into the Principal Act. Therefore the Government has moved this Bill.

Up to 2001, as many as 1367 Acts were repealed. But the job is not over yet. The Law Commission has identified as many as 253 laws as obsolete and has suggested their repeal. The Law Commission in its interim report of September, 2014 has suggested the repeal of as many as 700 Appropriation Acts which have been in the Statute Book for well over a decade. We are in agreement with the recommendations of the Law Commission of India. Obsolete laws like deadwood are a wasteful burden occupying the pages of the law books without any purpose and they confound us like a will-o'-the-wisp.

17.00 hrs

Therefore, these obsolete as well as amending laws, whose provisions have become part and parcel of the Principal Acts which are either substantive or procedural, need no longer be in existence and these amendments should be indicated by way of foot notes in the Principal Acts. Therefore, the retention of

this amending Acts as statute is redundant and superfluous. They serve no useful purpose and they are to be repealed.

I am in agreement with the Law Minister and I welcome the step. I also urge the Law Ministry to go ahead with the repeal of other redundant and obsolete laws.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir, for allowing me to speak on this very important Repealing and Amendment Bill. It may appear innocuous at the threshold but not to put too fine a point on it I must emphasise on how important this piece of legislation is. My only lament is that the piece of legislation does not go far enough.

I think, the task at hand, as the Law Minister will readily concede, is a humongous and gargantuan one. In 1998, the Jain Commission had prepared two reports on the review of administrative laws. It had recommended that out of 2,500 Central laws in force at that time (in 1998), more than 1,300 laws needed repealing. It means, more than 60 per cent of the laws were found to be otiose. Thereafter, the present Prime Minister set up a Committee to examine the issue of obsolete laws. This Committee identified 1,741 out of 2,781 existing Central Acts for repeal. So, what are we looking at? We are looking at repealing 36 Acts in this particular piece of legislation out of which 32 are amending Acts, only four substantive Acts have been set up for repeal. As I said earlier, this does not go far enough. The job at hand is a huge job and must be proceeded with great alacrity.

I am reminded of William Shakespeare's immortal lines – ‘We must look into the glass darkly and come face to face.’ The time has come in India for us to come face to face with the reality which we must confront. I know that the Prime Minister means well when he says: “Make-in India should become a national campaign.” I understand that the Finance Minister means well as well when he says that "ease of doing business" in India is a very important facet of his Government. But we have also to realize that a major deterrent to investment is India's inability to enforce contracts thanks to this myriad maze of laws and also an ill-equipped judiciary. There is a World Bank Report “Doing Business-2014”, which points out that it can take up to 1,400 days in India to obtain a legal remedy for non-enforcement, which is not just higher than the OECD countries' average of 529 days but also way above the South Asian average of 1,075 days. The cost

of such legal remedy can run up to 40 per cent of the claim in India. This is how difficult it is in India to do business. Therefore, if you say "Make-In India", if you say "ease of doing business" in India, these cannot be mere slogans, these are hard facts that we in India must come face to face with.

We have also to realize as to how prolific we have been in our legislation. Before the Constitution –115 years leading up to the Constitution – only 2,911 Central Acts were enacted. In the last 70 odd years after the Constitution, we have come up with almost 3,800 Central Acts. Our Parliament has been extremely prolific in legislating. I say with a great deal of regret that the proliferation of Parliament in legislation has been met with an equal disdain by our people in their regard for the laws. As much as Parliament legislates, the people disregard laws in this country and that again is a hard fact we must come face to face with.

Mr. Deputy Speaker, Sir, Parliament, as I said, has legislated with great alacrity. It is lamentable that while the legislation has been done with great alacrity, the enforcement of laws and the lack of adherence to it, has also been with a great deal of alacrity. There has been such poor enforcement, that in any case, any meaningful legislation almost always comes to naught.

Hon. Deputy Speaker, Sir, I only want to draw the attention of the hon. Law Minister to some of these absolutely ridiculous laws which still continue to obtain on our law books, and I cannot understand why in one fell swoop you cannot get rid of them. There are eight, ten which really count for humour and nothing else.

There is the Criminal Law (Amendment) Act, 1938 which says that there is a punishment stipulated for those who dissuade people from taking part in a war in which the British Empire is involved in. It is one of the most ridiculous pieces of legislation which is still on the books.

The Bengal Indigo Contracts Act, 1836 deals with regulation of indigo cultivation. I do not know if there is any indigo cultivation left in this country. The Shore Nuisances (Bombay and Kolaba) Act, 1853 aims at removal of nuisances and encroachments below high watermark in the Bombay Kolaba

Islands. The Madras Compulsory Labour Act, 1858 – Mr. Deputy Speaker, Sir, this is your territory – allows forced labour, which is now banned under the Constitution. The Stage Carriage Act, 1861 is aimed at creating a system to licence and regulate horse drawn carriages. I think, only the President's carriage can now be governed by this. There is no other carriages in India we know of .

The Lepers Act of 1898 allows Police to arrest without warrant any person who appears to be a pauper leper. This is again banned in law in our country.

There is the Exchange of Prisoners Act, 1848 to facilitate exchange of prisoners between India and Pakistan post partition. There is a Telegraph Wires Act of 1950 despite the fact that telegraph has now been wound up. There is a Hackney Carriage Act of 1879 for licence of hackney carriages. I do not even know what Hackney carriages mean. I do not think that anybody in this House knows what Hackney carriages mean.

Therefore, there are these ridiculous pieces of legislation still obtaining on our law books, and these ridiculous pieces of legislation must be quickly brought to an end so that we do not make a laughing stock of ourselves in the international fora. I can see Mr. Moily nodding his head. But all I can say ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

SHRI PINAKI MISRA : Hon. Deputy Speaker, Sir, please give me just a minute more.

It is lamentable also that the first Repealing and Amending Bill came into being only in 2001. So, the Congress Party in the 60 odd years that it ruled us was extremely lazy in getting rid of many of these otiose pieces of legislation.

I am grateful to the NDA Government, both in 2001 and 2014 that they have made some headway but please make much more rapid headway. That is what the requirement of the day is. I support this Bill and wind up my speech.

Thank you very much.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, we definitely welcome this Bill.

In my previous speech also, on the same subject, we talked about weeding out the files from the Office which are redundant and which are not relevant for the execution of the Acts. So, they need to be immediately repealed and amended. It was already passed.

Today, after two, three months of passing of that Bill, we are again coming with repeal and amendments.

When you go through the list of Repealing and Amending Bill given in the First Schedule and the Second Schedule, Sir, one Act attracts me in a very negative way, and that is, the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, and the amendment, the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act. What I would like to ask is whether the Acts are made for the sake of enactments of law. Is there any meaning for it? How do you implement it? Is there any way to discuss as to how they are implemented?

Sir, this Act is such a blemish on our free country. You are having still manual scavenging and providing punishment for the manual scavenging practices. We are talking about going to the Moon; we are talking about India joining the Atomic Club of the world; we are talking about aircraft, dream liners, flyovers, etc. In such a situation, we do not even talk about manual scavenging, and we are talking about those Acts still and again keep on amending that Act. To what effect? How long these Acts were to alleviate the problems of the scavengers? These scavengers are manual scavengers. Take, for example, Railways. When anybody goes to railway station, we see how human excreta are cleaned and how human excreta are attended to by the people. What is the fate of those people?

Instead of spending lakhs of crores of rupees on Defence or the Moon Mission or the Atomic Club of the World, let us spend some amount of money on these scavengers, which is a blot on the Indian democracy. In the international fora if we say that these are the lists of business today, these are the Acts to be amended and these are the Acts to be repealed, would we not feel ashamed? I feel very ashamed to talk about the scavenging Act. In India, we simultaneously have the Customs Act, the Excise Act and so many other Acts, which are very elite to the Indian conditions. But we also have these types of Acts, which are not being implemented sincerely. These all Acts starting from 1993 have become Acts in 2013. Now, again we come with the amendments.

Sir, any Act does not exist for the sake of Act. There has to be some human approach also. Let us abolish the scavenging by spending some amount of money instead of spending money meaninglessly on so many other schemes, just to have a prestige of the country in the international fora. Our prestige does not depend on spending huge amount of money on the atomic and other moon missions. It all depends on how far we are eliminating poverty and the type of unsociability being practised in a daylight. Anybody, any foreigner visiting a railway station in India, can understand what is human excreta and who are the people attending on them. It is a pertinent question, which strikes everybody.

I would urge upon the hon. Law Minister – of course, I appreciate his steps – to please increase the scope of this amendment. Thank you.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Repealing and Amendment Bill, 2014.

By this enactment, 36 Acts are sought to be repealed out of which four are Principal Acts and the rest 32 are Amendment Acts. All these enactments cease to be in existence. They have become obsolete or redundant due to many reasons. Thirty-two Acts are Amendment Acts.

As has already been pointed out here, once the amendment is carried out, these provisions become part of the Principal Acts and all these Acts are redundant in principle. But due to the Fiction of Law, all these Acts are being alive throughout. So, all these enactments are to be repealed; and I support this attempt on the part of the Government to repeal all these enactments.

Sir, in many cases, it appears that the Government is in a hurry to see that the Bills are passed without much discussions or deliberations in the House as well as in the Standing Committees. We have got 24 Standing Committees. I am very happy to see that this Bill is presented with a Standing Committee Report also. The Standing Committee has also suggested for a comprehensive enactment either by amending the General Clause Act especially Section 6A. The other remedy is to see that all these Amendment Acts, once the amendment is made part of the enactment, become repealed by way of provision included in the Amendment Act itself.

Sir, I would make a suggestion to the hon. Law Minister. If it is possible to have deliberations by the Standing Committee, we can bring in many ideas, more clarity and transparency in the enactment. By this, we can avoid a lot of inconvenience at the implementation level. Being a lawyer, I find a lot of provisions in the enactment, which cannot be implemented or which can be interpreted to the interest of the persons concerned. So, by having deliberations in the Standing Committee, we can have more clarity and transparency in the enactments. By this process, we can strengthen the legislative process in the Parliament.

Sir, coming to the Bill again, there are three Principal Acts of which one is of the British era, namely, 'The Indian Fisheries Act, 1897'. It has become redundant due to passage of time and subsequent enactments. Another example is 'The Foreign Jurisdiction Act, 1947' and 'The Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978.' Similarly, 'The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993' has also become obsolete and redundant due to enactments made by the Legislative Assemblies concerned. There are also 32 amendment Acts. Once that amendment act is notified, all the provisions are to be amended in the principal act as they have already been made part of the amendment Act and there is no point in keeping all these amendment Acts. It has to be repealed.

I am concluding with a request to the Government. I request the Government not to be in a hurry to make the laws. We can have deliberations in the Standing Committees also. Thank you Sir.

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): I do agree that some of the laws which we have enacted do require repealing because they are either outdated or they do not suit the present situation. So, my request is that while repealing the Acts or the laws which we have enacted, the exact reasons for repealing should be made known to the general public. People should know what are the laws which the Parliament has enacted? The Parliament is repealing. We repeal many existing laws and people may not be knowing the laws which were enacted.

Sir, inordinate delay in disposal cases is the main problem which we are facing in the legal field. For that, in my opinion, the procedural aspect - the Civil and Criminal Procedure Codes - which were enacted long back, the same procedure is now being adopted. The mindset of the people, the mindset of the advocates, the mindset of the litigants and the mindset of the judiciary have now changed. That is why, this is right time and we should try to conduct surgery over these laws which were enacted long back and which are not suiting now and which are now coming in the way of speedy disposal of the cases.

There are some ambiguities which we are enacting thereby leading to many litigations in the courts, they will come in the way of implementation of many laws in the country. For example, special status was given to Hyderabad-Karnataka under Article 371(J). In this, what has happened Sir? Our Law Minister is also fully aware. In Hyderabad-Karnataka region, if any problem arises in that area or if there is a case in Bellary, that case has to be decided by the Bench at Dharwad. Dharwad does not have any jurisdiction under Article 371(J) over Hyderabad-Karnataka. Bellary comes under Hyderabad-Karnataka region. There is a court in Hyderabad-Karnataka region that is in Gulbarga. Instead of fixing the jurisdiction to Gulbarga, the cases of Bellary are being disposed of by Hubli-Dharwad Bench. Keeping that thing as an instance while legislating laws, there should not be any ambiguity. If any ambiguity is there, definitely it leads to many litigations. For example, there are nearly 36 laws which we have enacted and now, we are repealing. Of course, there are two amendments which you are

seeking for two Acts. Except for this 1 and 2 that is Indian Fisheries Act and Foreign Jurisdiction Act, all other Acts which we are now repealing were enacted recently. You are repealing some marriage laws also. While making laws now, we should also keep in mind the mindset of young people. The mindset of young people differs from the marriage laws which were enacted long back. That is why, while enacting laws now, we should also study the present scenario, the mindset of the people and the way in which our society is moving and what are the problems that are being faced by the people now and what are the problems which are coming in the way of these young couples and why a lot of cases are being filed in the matrimonial courts? These are all the requirements by the legal system to study them effectively and while enacting, we should give an end to all such problems.

In spite of that, we do agree that a lot of cases are being filed under the marriage laws. That is why, you should take extra care in bringing new legislation. Many times, the laws, which we enact now in Parliament, will be subjected to scrutiny by the courts. That is why, in many cases the hon. Supreme Court or the respective High Courts have struck down those laws.

The hon. Law Minister is from Karnataka. He is from the southern part of the country. He is also an advocate by profession. The concept of judiciary is to see that better and effective justice should be rendered to the doorsteps of the people. Keeping that point in mind, I insist and urge upon the hon. Law Minister to take up this matter to see that justice is delivered at the doorsteps of the people of South India. I request him to kindly see that a Supreme Court Bench is established at Bangalore to enable people of the southern part to get justice easier, cheaper and effectively. Thank you.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Mr. Deputy Speaker Sir, I thank all the hon. Members who have supported this Bill. They have made certain observations. I would like to draw the attention of the Members who have made a few observations in this regard.

First of all, I will take through the Bill which I have presented. Out of 36 Acts, four Acts are principal Acts. The Standing Committee also went into them in detail as far as the four principal Acts are concerned. My friend, hon. P.P. Chaudhary has addressed those issues. Regarding the point on the laws which are prevailing earlier to the day of Independence and how those Acts have been taken away by the Act of Constitution, has already been addressed by my friend. As far as these 32 Amendment Acts, which are in Schedule I are concerned, they are not a matter of concern and everybody has felt that they should be repealed.

Regarding the four principal Acts, which were referred to the Standing Committee, the Standing Committee elaborately dealt with those matters. They have observed about the main Act about which my hon. friend Mr. Ninong Ering was telling that the Foreign Jurisdiction Act may hurt the North-Eastern States where there was an earlier instrument in relation to the accession signed between the Union of India and the Tribal Kings. But after due discussions and deliberations in the Standing Committee, they made it clear that the provisions of the Act, which was there earlier to the day of Independence and as per the Constitution, have been clearly looked into and there are certain provisions which were made under the Constitution practically made the Foreign Jurisdiction Act redundant and it is no more in force. The Committee even observed:

“The enactments prior to the commencement of the Constitution of India, except those repealed by the Constitution itself, continued to remain in force unless and until they were repealed by the Indian legislature, in view of the provisions of Article 372(1) of the Constitution of India. The Foreign Jurisdiction Act, 1947 was last used in 1962. It is no longer required as no territory of India is under the control of any colonial power. The said Act is, therefore, recommended for repeal.”

Very clear versions have been given by the Standing Committee. I hope my friend will agree with the views given by the Standing Committee while deliberating on this issue.

As far as Sugar Undertakings Act, 1978 is concerned, it has been clearly said as follows: “It was also submitted to the Committee that there has been no occasion in the last three decades to exercise the provisions of the said Act.” The interests of sugarcane farmers by sugar mills have been statutorily supported and enforced by respective State Governments.

Moreover, since 2013 sugar sector has been decontrolled. Levy obligations on sugar mills have been removed and regulated lease mechanism of open market sale of sugar has been dispensed with. Then, various States themselves have made certain rules to control all these issues. So, this Act is not in use for the last three decades. Therefore, the Act is not relevant in the present scenario. Even otherwise the Act was a temporary measure taken back in the year 1978. It is clearly observed that at present it is of no use. We are well aware of the fact that sometimes the dead laws create some sort of confusion if it remains in the statute book. So, the Act has to be repealed.

One of the important issues that has been raised is why this Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 was deleted from the list of this Act. Practically, we consult with the Department concerned whether the law is in use or in force at present. In an earlier occasion in 1976, the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 was enacted under Article 252 (1) of the Constitution and it was applied in eleven States. In 1999, the said Act was repealed after getting particulars from various States. At that time, it was found that it was not in use. So, it was repealed. But only two States had passed resolution to repeal the Act and a provision was made for continued application of the repealed Act in the other States till they adopt the repealed Act by a resolution under Article 252 (2).

Here also, we thought that several States have passed resolutions and only two or three States have not passed the resolutions. Just like the precedent in 1976 in Urban Land (Ceiling & Regulation) Act when the law was not used by any of the States, we proposed it. Even in the case between West Bengal v/s P.K. Sur, it was held by the Supreme Court that if a law is operative in the State of West Bengal, a resolution is to be passed to make the repeal effective in that State subsequent to the repeal. So, in the instant case, three States have passed the resolution for repeal of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993. So, there was nothing wrong in inclusion of this Act in the Repealing and Amending Bill. However, the Standing Committee has recommended that the Government has to drop it from the proposed Bill. So, I am going to drop that Bill from this list.

As far as Schedule II is concerned, it is only a patent error that has been committed on the earlier occasion when the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Bill 2013 was discussed and accepted. In the proviso to sub-section (3) of Section 1, the word 'notification' shall be substituted by the words 'the said notification'. A small error had occurred. For that reason I have got it. It is a very formal defect and it is a very formal inclusion.

In the Whistle Blowers Protection Act, 2011 in enacting formula, the words 'Sixty-second Year' have to be changed with 'Sixty-fifth Year'. So, it would be Sixty-fifth Year of the Republic of India. In sub-section (1) of Section 1, the figure '2011' has to be substituted with the figure '2014'. These are the patent errors that need to be rectified.

Then, there are some other observations made by my learned friend with regard to the ease of doing business and delay in disposal of disputes. I do concede that it is true that delay in disposal of disputes has created much confusion among the people across the country. Not only here, even in the arbitration cases, people prefer to file arbitration cases outside India rather than having arbitrations here. Now, this Government has taken an initiation to bring some stringent amendments

to the Arbitration Act. Already amendment to Arbitration Act is ready. The Bill is ready and we are going to bring that Bill in the next Session so that the ease of doing business will be certainly geared up and people, investors and even the private players will be happy if some stringent amendments are brought to the Arbitration Act. We are working on it. This will be placed before Parliament in the next Session.

HON. DEPUTY SPEAKER: What do you mean by next Session - April or Monsoon Session?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, it will be brought in April because I have already taken this matter to the Cabinet and the Cabinet has given its approval. Now, I have to only bring it to Parliament. Apart from that ...
(Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : डी.वी.सदानन्द गौड़ा जी कॉरपोरेट के रूप में नहीं थे लेकिन आप आहिस्ता-आहिस्ता उधर लेकर जा रहे हैं ... (व्यवधान) खाया न पिया ग्लास फोड़ा बारह आने का, ऐसा किया जा रहा है।

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Hon. Khargeji, I do not want to have a postmortem of all those things that happened in the past because doing postmortem will not serve the purpose. We should inject some new tonics for this and then only can we go ahead.

One more apprehension that was just addressed is with regard to the disposal of disputes at the earliest. We are also working on it.

Already Law Commission has given a report for establishment of Commercial Benches in the High Courts. We are working on that also. That Bill will also be brought before the Parliament in the next Session so that all these things will help in ease of doing business in India.

I will not traverse other issues which were raised about various Acts and laws. You were just telling, but I do not want to traverse all those things. ...
(Interruptions) I will do that.

It is true that nearly 1,741 redundant laws, which are almost dead laws, are in existence. We have already prepared a draft Bill for repealing nearly 741 appropriate Acts. That is already ready with me. I will take it to the Cabinet for its approval. Another Bill is already there for 79 repealing and amending Acts before the Rajya Sabha. That is also being taken up immediately. It will be coming to this House as early as possible, when it is passed by that House. So, as far as repealing and amendments are concerned, we are working on it. We will see that within a short span of one or two years, we hope so, all these redundant laws which are not in use, the so-called dead laws, are taken care of. Certainly, the Statute Book will be cleared so that there should not be any confusion in the process of disposing of cases.

Sir, I would like to place before this august House one more thing. Why are we giving so much importance to repealing and amendment Bills? Unlike human beings, the statutes do not die natural death, with the possible exception of statutes whose life is predetermined by the Legislature at the time of their enactment. One of my friends observed with regard to the sunset clause. I do concede and I do not dispute that there should be a sunset clause, but the life of the law is determined in the sunset clause. The removal of the redundant law from the statute has to come only after repealing the said Act from the book.

Sir, I think that I have cleared all the observations made by my friends. This is the initial step as far as the Repealing and Amendment Bill is concerned from this new Government. This new Government is working on it, and all the redundant laws will be removed from the statute book at the earliest. So, this Bill may kindly be passed.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shrimati Meenakashi Lekhi.

... (*Interruptions*)

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Sir, please allow me to ask one small question. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot allow it.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I can allow only one person. We are going to take up an important discussion under Rule 193 and other things are also to be taken up, which are also very important. Therefore, please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, kindly stick to the clarification only.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I will stick to the clarification. The clarification is in view of the Standing Committee Report on the Manual Scavenging Act. There is another Act of 2013, and this one is of 1993, and the Standing Committee had reservations that since the States have not sent the Resolution, this cannot be brought about.

I have two points to make on this. One is that since this august House has passed the 2013 enactment after due consideration, and various aspects of it have been considered. So, it is pertinent that this very Act be implemented all across the country. The second part is that it is not just Article 252 of the Constitution, but it is also the Fundamental Rights, which get affected. Especially, in case of manual scavenging, it is the right to live with dignity, and when we bring it under that enactment, then this House can always resolve and the Government can resolve to do away with the Resolution part and let the 2013 enactment be the Act across the country.

By way of *swatchatha*, let us bring *swatchatha* in every day activity and even house-keeping activity of the Government, so that repealing and amendment that have been long-pending can be taken care of. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is all right whatever you have said on it.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Okay, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Vincent H. Pala to ask only a question.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I want a clarification regarding the Foreign Jurisdiction Act, 1947. Especially, in the North East, this Act is mainly to give power to the Government of India to annexe many small States to the Government of India in 1947. But the problem in Nagaland and Meghalaya is that there are some States, which have an agreement with the Government of India in those days. So, if you are repealing this Act, then what about those agreements, which India and those States had like the Instrument of Accession, etc.? How the Government will deal with those things? This is one of the areas where we have a lot of extremism in the North East because the Government of India annexed them without a proper agreement in those days. So, I would need a clarification on this. How will you deal with those Acts?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA : As far as the Constitution requirements of the Resolution under Article 252 being a Constitutional requirement is concerned, it cannot be waived off by the Parliament without seeking proper redressal for that. So, at this stage, that could not be done.

As far as my friend's observation with regard to the North Eastern Foreign Jurisdiction Act is concerned, it is very clear that the territories, which are under the control of the colonial powers while the territories, which were integrated to the Union of India in North Eastern States, where of the Assam Province and the repeal is not related to the Instrument of Accession signed between the Union of India and the Tribal Kings in the North Eastern States. It has got nothing to do with that.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

First Schedule

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.3 to First Schedule.

Amendment made:

Page 2, *omit* lines 22 and 23.

(3)

(Shri D.V. Sadananda Gowda)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the First Schedule, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

First Schedule, as amended, was added to the Bill.

Second Schedule was added to the Bill.

Clause 1

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.2 to Clause 1.

Amendment made:

Page1, line 2, *for* “2014”, *substitute* “2015”. (2)

(Shri D.V. Sadananda Gowda)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister to move Amendment No.1 to the Enacting Formula.

Amendment made:

Page1, line 1, *for* “Sixty-fifth”, *substitute* “Sixty-sixth.”. (1)

(Shri D.V. Sadananda Gowda)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

17.43 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193
Agrarian situation in the country

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No. 29 – Discussion under Rule 193. Shri P. Karunakaran.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, can we take it up tomorrow?

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not that. We have got time up to 6.00 p.m. You can speak.

SHRI P. KARUNAKARAN: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am happy to initiate the discussion with regard to the Agrarian Situation in the country under Rule 193. I am speaking when most of the Ministers are absent and the gallery is empty. ...
(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Ministers are here. Agriculture Minister is here; Mines Minister is here; our Law Minister is here; Shri Rudy is also here.

... *(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, India is considered as a nation of lakhs and lakhs of villages. India is an agricultural country. It is the backbone of our economy. So, the farmers and agriculture workers constitute a major force in the productive sector, that is, agriculture. So, agriculture has to be given the utmost importance with regard to many of the policy decisions that the Government has taken.

There is a serious crisis in agricultural sector now which may be due to various reasons like policy decisions and internal and external forces. It is unbelievable that in India 1.5 lakh farmers committed suicide between 1997 and 2005. It is alarming to note that one farmer committed suicide every 32 minutes in India between 1999 and 2005. Due to lack of confidence, our farmers are not in a position to stay put in their lands. Farmers' suicides are continuing even in this era. This pathetic situation is a result of the policies followed by various Governments and other factors. It is a fact that political parties, farmers'

organisations and many other forces are taking up this issue, but the situation in agricultural sector has not improved in any way.

Agrarian conditions in rural areas have further worsened for the broad masses of poor peasants and the rural agricultural workers in the last three years especially. The long-term slowdown in agricultural growth is due to lack of public investment and capital formation in this sector. As we have seen in the recent Budget also, investment in agriculture is declining every year. As a result, farmers' suicides are continuing in almost all the States.

According to a National Crime Records Bureau report, 11,772 persons committed suicide in 2013 alone. It is generally agreed that the main reason for this is that farming is increasingly becoming uneconomical. Another reason is the sharp rise in input costs and a lack of proportionate rise in the output prices. It is true that the prices of seeds, fertilisers, pesticides, power and fuel have sharply gone up after 2012 due to the policies of the Government.

Research and development is an essential step that has to be taken by the Government. Not only in agricultural sector but in industry and other sectors also R&D should receive highest importance. I am sorry to say that agricultural sector has been taken over by multinational companies, domestic corporate houses as far as seed production and distribution are concerned. They do things suited to their convenience and not for the sake of lakhs and lakhs of poor and marginal peasants in the country.

Control of corporate houses on farm inputs is growing nowadays. The sharp rise in the cost of different agricultural inputs has been left uncontrolled and farmers are not compensated by a corresponding increase in output prices. Prices of agricultural commodities in international markets have also adversely affected farmers. In such a situation, public procurement system is one relief for the farmers. But the Government is not giving due importance to this. They are inviting multinational corporations into retail sector and to the farm gates.

We know that sugarcane farmers are affected because of failure of the state to ensure payment of their dues to the tune of 110 billion from sugar mills. How can sugarcane farmers survive if they are not in a position to get back their dues? Here it is for the big sugar mills, not for the farmers. So, State Governments as well as the Central Government have to take up this type of issues which are most important as far as farmers are concerned.

Sir, agricultural credit is another thing which comes to the assistance of farmers. But in practice, it also goes to the big corporations, agriculture houses and big farmers. Small and marginal farmers are unable to get the loans at a cheaper interest rate and they are forced to depend on the money-lenders. As a result, the indebtedness among the peasants is growing. We had discussed in the House that the earlier Government appointed Swaminathan Commission which gave many suggestions in its report. One among them was the provision of free loans or loans at cheaper interest rate that is 4 per cent as far as farmers are concerned. In the Budget the Government says, we are raising Farm Credit Target to Rs 8.5 lakh crore. But what is the interest rate? It is 12 to 14 per cent. As far as the farmers are concerned, the most important issue is whether the Government is ready to reduce the interest rate of loans given to farmers.

The Cooperative Societies have been giving assistance to farmers in the states like Kerala. There is a well established cooperative system covering all villages of the State of Kerala. They are really assisting and protecting the farmers especially in my State but the new policy on Cooperative Credit Societies have created much difficulties for them in giving loans to farmers. The Cooperative Societies and Banks are not allowed to accept deposits, thereby being unable to lend money to farmers. This has become an issue in the State.

There are more than 1,000 Primary Cooperative Societies, 14 District Cooperative Banks and a large number of other Cooperative Societies. But at the same time, they were really the protector of the villagers as far as Kerala is concerned, because the farmers were getting loans and they could also make deposits. But as per the new decision taken by the Government, the Cooperative Societies are not able to get the deposits. Because of the new decision of the RBI and the Government, the cooperative sector in Kerala is facing great difficulties. This will affect the farmers also because they will not be able to get the loans. They will have to go to the money-lenders. Why is the Government disallowing the Cooperative Societies from receiving the deposits and why have they to go to the private banks? It means that they are diverting the farmers and also other persons to go to private Banks instead of Cooperative Banks.

The cooperative sector is really the sector of the people. So, I request the Government to apply their mind as far as the State is concerned because unlike other States, the cooperative sector is well established and well networked in Kerala. In every village, we can see such Cooperative Societies and Cooperative Banks. Irrespective of political parties, we placed these issues before the Finance Minister and the Prime Minister, but I am sorry to say that they have not taken any decision. At least the Minister of Agriculture can take up this issue for the sake of farmers.

The Government has decided to change the pattern of the MGNREGA Act. The total number of the blocks converted by the Act is limited and the labour component is also changed. Earlier it was 60:40 but now it is 51:49. Due to these changes, on both sides the employment opportunities for the workers are reduced. The earlier Government had passed this not only as a scheme, but as an Act. So, it is on the issue of the demand that the work has to be given by the Panchayats, Blocks or Districts. As a result, lakhs and lakhs or crores and crores of people were getting employment.

When we talk about the agriculture sector, it is in a difficult position. How is it possible for the workers to get work if you are taking up such legislation or such a change in the existing MGNREGA scheme? So we strongly urge the Government that there should not be any change with respect to the blocks. The Government says that there is no change. There are 6,000 or more blocks in India but now the number is confined to 2,500.

I know that. In my State, there are 102 blocks but now it is applicable only in 50 blocks. In my district, there are six blocks but it is applicable only in four blocks. The Government says it has not made any changes. Who has given these directions? How has the decision to change taken place? The number of blocks has come down, as a result of which employment opportunities are coming down. Another major decision relates to 60:40; sixty per cent means the wages of the workers and the other portion is the materials. ... *(Interruptions)*

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA) : This is slow poisoning. ... *(Interruptions)*

SHRI P. KARUNAKARAN: This is really contributing to the slackening of the agriculture sector. That also has to be taken into account.

The Government has passed the changes in the Land Acquisition Act. There was a strong protest in this House. There were about 104 votes that we got. Maybe, this is a first as far as the Opposition is concerned. I am sure that even on the side of the Treasury Benches, many of the hon. Members were thinking that it was not desirable. Though many of them were not able to vote against it, they had abstained and gone out of the House. It means, a large number of Members and a large number of parties were not in favour of passing this Bill. ... *(Interruptions)*

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Why have they passed it? If a number of Members and a number of parties do not want to pass it,

has god come and made them to pass it? It is a democracy with open voting in the House. ... (*Interruptions*)

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Sheer numbers.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Democracy means numbers also; it is about numbers and Members. Otherwise, you would have been here; we would have been there; and they would have been somewhere else. It is simply a decision of the people. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is also a question of everybody's acceptance. When you get power, you must act judiciously; you should not bulldoze. That is the only request. ... (*Interruptions*) You should not feel that you can do anything you want. It is also about how will you act. ... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We have learnt from your experience of Emergency and we are products of the anti-Emergency movement. ... (*Interruptions*) We have learnt from that. You have set so many precedents. We are fortunate to have those precedents. ... (*Interruptions*) We are learning from you.

This is a new interpretation that 450 people do not count but 40 people will decide. Shri Karunakaran, I am sorry to stop you. You have got every right to express your views but do not cast aspersions on Members who have voted for the Bill. ... (*Interruptions*) You may have a difference of opinion. It is not only the majority but an overwhelming majority of two-thirds against one-third who have voted. So, how can you say that? ... (*Interruptions*) It is wrong to say that all Members are opposed to it. That is not fair. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : We are not deriding; we are only dissenting. ... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : I am happy to hear your intervention because I do not want to disgrace all your Members who were not here at the time of the voting. I do not want to tell the names. ... (*Interruptions*)

Shiv Sena is a constituent of your Government. Is that not a fact? What was their position? ... (*Interruptions*) Was it imposed by us? They knew that this Bill was not in the interest of the country.

The BJD did not participate in the voting because they knew that it was not in the interest of the people. ... (*Interruptions*) Many of the other parties were also there.

It is true that in a democracy, the majority decision is the main decision but why did they not support you?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Can we have a conscience vote in respect of the Land Acquisition Bill in this House? ... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : If you go for the conscience vote, it would be against the Government. The people who are supporting BJP will vote against it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If you go for that, the RSP which used to be on the Left will go with the Right, that is, the Congress Party.

SHRI P. KARUNAKARAN: We have witnessed at the time of the voting as to how many parties were there and how many Members were there and how many had gone out. Many Members abstained. It shows that there was a strong opposition in their conscience with regard to the adverse effect of the Bill. That is what they had expressed. ... (*Interruptions*)

I think, you have to understand and realise that in your own party and in your own Government there are disagreements with this. I would like to quote from the autobiography of Shri Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister.

18.00 hrs

He made it clear that it is true that the majority rules, that is the decision, but at the same time the majority has to think how the minority feels. Here, it is not only the minority, the persons who have assembled before you are also not in a position to support you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Karunakaran, you may continue tomorrow.

The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

18.01 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, March 19, 2015/Phalguna 21, 1921 (Saka).*
